

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 जनवरी, 1974

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विषय-सूची

मंगलवार, 15 जनवरी, 1974

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 1
अध्यक्ष महोदय द्वारा कामन लैडज (रैगुलेशन)	(9) 37
बिल 1971 सम्बन्धी	
वर्ष 1974-75 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9) 37
व्यक्तिगत सपष्टीकरण -	
चौधरी दल सिंह द्वारा	(9) 57
वर्ष 1974-75 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9) 61
परिशिष्ट	

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 जनवरी, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,
सैक्टर— 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई । अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

Mr. Speaker : The Question Hour.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cases of Theft, Arson and Murder

***547. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the district-wise total number of cases of theft, arson and murder committed in the State during the year 1973 separately; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above which have been detected so far?

Home Minister (Shri Poswal) : (a) and (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The district-wise total number of cases of theft, arson and murder committed in the State during the year 1973, (upto 26-12-73) separately, is as under :

District	No. of cases committed		
	Theft	Arson	Murder
Hissar	366	12	43
Rohtak	330	10	26
Gurgaon	430	10	25
Karnal	293	5	24
Ambala	355		19
Narnaul	188	9	8
Jind	137	1	16
Bhiwani	127	5	9
Kurukshetr a	201	8	26
Sonepat	130	4	20
Total	2577	64	216

(b) The number of cases out of those referred to in part (a) above, which have been detected so far is given below .

District	No. of cases detected.		
	Theft	Arson	Murder
Hissar	178	9	40
Rohtak	221	6	23
Gurgaon	246	6	20
Karnal	107	4	21
Ambala	183	—	17
Narnaul	83	6	6
Jind	70	1	14
Bhiwani	85	5	9
Kurukshetra	123	6	23
Sonepat	74	—	19
Total	1370	43	192

चौधरी राम साल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि जिला हिसार में 366 केस चोरियों के हुए, 43 मर्डर हुए और 12 आरसन के केस हुए और इसी तरह गुड़गांव में 430 चोरियां, 10 आरसन और 25 मर्डर के केस हुए । बाकी जिलों में कहीं 1 हुआ है और कहीं 4 हुए हैं

तो क्या वजह है कि हिसार और गुड़गांव में ये केस ज्यादा हुए कब?

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी फल चन्द (रोहट) : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कुछ ऐसे भी केसिज दर्ज हुए हैं जिनमें केस दर्ज करने के बाद आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, सिर्फ केस ही दर्ज किये जाते हैं?

Mr, Speaker : How does it arise out of this question?

Chaudhri Phool Chand (Rohat) : Cases have been registered, but the people have not been arrested.

Mr. Speaker : What type of cases ?

Chaudhri Phool Chand (Rohat) : Theft cases and cases under section 420.

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 1973 में 2557 चोरियां हुईं जिनमें से 1570 वरामद हुईं, इन में माल कितने रुपये का बरामद हुआ?

श्री के० एल० पोसवाल : स्पीकर साहब, ऐसा है कि जो चोरियां हुईं वह 34,10, 238 रुपये की हुईं और जो रिकवरी हुईं वह 24,96,865 रुपये की हुईं ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह जो रिकवरी है इसमें क्या-क्या चीज शामिल है?

श्री के० एल० पोसवाल : स्पीकर साहब, इ सके लिए सैपरेट नोटिस चाहिये ।

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह जो फिगर्ज दी हुई है में सन् 1972 से इन्क्रीज हुई है या डिक्रीज हुई ह?

श्री के० एल० पोसवाल : इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिये ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ये चोर आम तौर पर कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखते है?

श्री के० एल० पोसवाल : अब तो महाजन भी चोरी करने लग गए हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जितने केसिज दर्ज हुए हैं लगभग उतने ही दर्ज किये बिना नही छोड़ दिये गये.?

श्री के ० एल ० पोसवाल : ऐसी तो कोई बात नहीं है ।

श्री अमर सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि 1973 में 216 मर्डर हुए एं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि मर्डर के ऐसे कितने केसिज हैं जो अन-ट्रैसड डिक्लेयर किये गये हैं ?

श्री के० एल० पोसवाल : दस ।

श्री गिरीश थन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आरसन के केसिज में किसी पोलीटिकल पार्टी का भी हाथ था?

श्री के० एल० पोसवाल : इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिये ।

श्री गुलाब सिंह जैन : मन्त्री महोदय ने अभी फर्माया कि महाजन भी चोरी करने लग गए हैं । यह बात क्या इन्होंने किसी डैटा के बेसिज पर कही है या अपने अन्दाजे से कही है?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : वे तो सेल्ज टैक्स और इंकम टैक्स की बात कर रहे थे । (हंसी)

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, स्टेटमेंट में बताया है कि 2,557 चोरियों में 1370 बरामद हुईं, और 64 आरसन के केसिज में से 43 डिटैक्ट हुए और इसी तरह से 216 मर्डर केसों में से 192 केस डिटैक्ट हुए । इससे यह पता लगता है कि 1187 चोरियां, 21 आरसन के केस और 24 मर्डर के केस ट्रेस

नहीं हो सके । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इसके लिये पुलिस की ईनएफीशिएंसी कारण है या कोई और कारण है?

श्री के 0 एल 0 पोसवाल : स्पीकर साहब, इसमें एफीशिएंसी का सवाल पैश नहीं होता । कई दफा ऐसा होता है कि चोरी डिटैक्ट हो जाती है और आदमी बाहर चला जाता है इसलिये गिरफ्तारी नहीं हो पाती ।

चौधरी अब्दुर रजाक खां : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कत्ल के जो केसिज अन-ट्रैस्ड मिले वे लाशों लाशो लावारिस मिलीं या उनका कोई वारिस था?

श्री के0 एल0 पोसवाल : इसके लिये सैपरेट नोटिस दे बता दिया जाएगा ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : क्या मन्त्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि कितने एम0 एल 0 एज0 के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं?

Mr. Speaker : Order please. It is not a supplementary question.

G .C. Sheets and Mutton Tallow

***632 Shri Dhaja Ram :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of parties who were released G.C. Sheets and Mutton Tallow and recommended for import

licences during the year 1971-72 for Jind District;

(b) whether the material was allotted to the genuine industrial units during the said period and out of those how many units are in working condition at present;

(c) whether any enquiry has been conducted for making wrong recommendation/allotment of the said material by the Department;

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative the findings of the said enquiry; and

(e) whether any official has been found guilty; if so, the action taken against the said official ?

Industries Minister (Shri Harpal Singh) :

(a & b) A statement is laid on the table of the House.

(c) No enquiry was conducted in regard to the recommendations/ allotments for the year 1971-72. No complaint was received pertaining to this year.

(d & e) Does not arise.

STATEMENT

(a)

(1) The following units were released G.C. Sheets during the year 1971-72 :-

(i) M/s Raj Group of Industries, Jind.

(ii) M/s Guru Nanak Trunk House, Safidon.

(iii) M/s Devico (India) Foundry & Engg. Works,
Narwana

(iv) M/s Haryana Rice Dall and Gene ral, Mills,
Safidon

(v) Sh. Chattar Singh s/o Sh. Raja Ram, Lulana

(vi) M/s Krishna Rice and Dall Mills, Jind.

(vii) M/s Bharat Carpontry & Blacksmithy
Production Co-operative Industrial Society, Safidon

(viii) M/s Haryana Kris hi Udyog, Narwana

(2) The following units were released Mutton Tallow during
the year

1971-72.

(i) M/s Sumer Chand & Sons, Safidon

(ii) M/s Phool Chand Shri Niwas Safidon

(iii) M/s Narwana Oil & Soap P.C.I.S. Ltd.,
Narwana

(iv) M/s Kapoor Soap Factory, Jind

(v) M/s Narwana Oil and Soap Co-operative
Society, Narwana.

(3) The following parties were issued Essentiality
Certificates/Import Licences during the year 1971-72-

(i) M/s Sushil Auto Industries, Jind

(ii) M/s A.Paul Instruments Co., Jind

(iii) M/s Haryana Krishi Udyog Narwana, Distt,
Jind,

(iv) M/s Gupta Industries, Laxmi Bari Nagar,
Rohtak Road, Jind.

(v) M/S Kabir Industries. Patiala Chowk, Jind.

(b)

(1) G. C. Sheets

The material was allotted for construction purposes and it has been reported to have been properly utilised. All the units are working satisfactorily at present.

(2) Mutton Tallow

Mutton Tallow was allotted to genuine industrial units which are reported to have utilised it properly. However, the unit of M/s Sumer Chand & Sons, Safidon is not functioning at present.

(3) Essentiality Certificates/Import Licences

The units at 5, Nos. (i) to (iii) of (a) (3) above which were recommended essentiality certificates for the issue of import licences are working satisfactorily. The units at S. Nos, (iv) and (v) are not functioning and they have not been issued import licence by the Govt, of India.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जी० सी० शीटस और मटन टैलो की डिमांड कितनी थी ?

श्री हरपाल सिंह : इसके लिये मैपरेट नोटिस चाहिए । डिमांड का यहां पर कोई सवाल नहीं है, इसमें तो जिन पार्टियों को रिकमैंड किया गया उनकी लिस्ट है

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएं गे कि जी 0 सी 0 शीट्सु की अलाटमेंट करने का क्राइटेरिया क्या कछ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इसका तरीका यह है कि जिस आदमी की मशीन लगौ होती है या लगानी होती है उसको कस्ट्रक्शन के लिये मैटीरियल की जरूरत होती है । उसकी स्कीम को वहां का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीजु आफिसर देख कर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन को रिकमैंड करता तै । फिर वह उसको अलाटमेंट करते हैं ।

श्री हरि सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जन आदमियों ने इम्पोर्ट लाइसेंस के लिये ऐप्लीकेशंज दी क्या उनको लाइसेंस मिल गए या नहीं?

श्री हरपाल सिंह : पांच पार्टियों को इम्पोर्ट लाइसेंस के लिये रिकमैंड किय गया थ उनमें से तीन को लाइसेंस मिल गया है और दो को नहीं मिला है ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जी 0 सी 0 शीट्स और मटन टैलो देने के लिये जिन आदमियों की लिस्ट हाउस में ले को गई हे उनमें से हरिजन कितने हैं?

श्री हरपाल सिंह : इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये ।
लेकिन हमारे पास जो भाई आया उसको मिला है

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे
कि जितनी सप्लाई की गई डिमांड उससे कम थी या पूरी के?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, उस वक्त मैं समझता
हू कि इतनी शार्टेज नहीं थी जितनी कि अब हो रही है. यानी
1971 - 72 में यह पोजीशन नहीं थी ।

Hospitals in the State

***645 Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Industries
be pleased to state—

(a) the total number of Hospitals constructed
during the years 1972-73 and 1973-74 in the State; and

(b) whether the construction of the building of the
Civil Hospital Palwal has been started ; if so, the time by
which the construction is likely **to** be completed and the
number of beds to be provided therein ?

Mr. Speaker ; This is not a supplementary question. This does
not arise out of this question,

Mr. Speaker : Order please. This is not a supplementary
question.

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) वर्ष 1972-73 और 1973- 74 में किसी हस्पताल के लिए नये भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया । परन्तु पहले शुरू किए गए निर्माण कार्यों में से 6 हस्पतालों के भवन वर्ष 1972- 73 में और चार हस्पतालों के भवन वर्ष 1973- 74 में पूर्ण किए गए ।

(बी) यद्यपि इस भवन के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है, परंतु धन को कमी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदया बताने को कृपा करेगी कि 1974- 75 में कोई नया हस्पताल खोलने की योजना है या नहीं अगर है तो कहा-कहा?

श्रीमती शारदा रानी : 1974- 75 में नया भवन निर्माण करने को कोई योजना नहीं है ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मन्त्री महोदया बताजगी कि जिन हम्मनालो का निर्माण कार्य 1972-73 और 1973- 74 में हुआ वह कौन-कौन से हैं?

श्रीमती शारदा रानी : सन् 1972-73 में जो हस्पताल तैयार हुए उनके नाम इस तरह से है रु-

1) फिरोजपुर झिरका

2) नूह

- 3) कालका
- 4) झज्जर
- 5) लोहारू
- 6) तोशाम

सन् 1973- 74 में जहां-जहां तैयार हुए :-

- 1) नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ
- 2) हिसार
- 3) महेन्द्रगढ और
- 4) गोहाना

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या यह बात गवर्नमेंट के नोटिस में है कि देहातों में मैडिकल फैसिलीटीज नाकाफी है? अगर ऐसा है तो क्या देहाती क्षेत्रों में कोई हस्पताल खोलने की योजना सरकार के जेरेगोर है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब देहातों के लिए अलग से योजना है और वह मिनिमम नीड्ज प्रोग्राम के अन्तर्गत है । देहातों में बड़े हस्पताल नहीं हैं बल्कि प्राईमरी हैल्थ सेंटर हैं और अगली पंचवर्षीय योजना में कुछ प्राईमरी हैल्थ सेंटर्ज को अपग्रेड करके रूरल रेफल हैल्थ सेंटर बनाने की योजना है और

चार व्लाक्स में एक रेफल हैल्थ सेंटर होगा जिस में 30 बेंड होंगे और अगले पांच कला प्लैन में हमारा इस प्रकार के 17 रेफल हस्पताल खोलने का प्रोग्राम है ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहिबा बताने की कृपा करेंगी कि सन् 1971- 72 और 1972- 73 में जो हस्पताल बनाए हैं उन पर क्या लागत आई है?

श्रीमती शारदा रानी : उनके लिए 698 लाख की लागत का ऐस्टीमेट था ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मैं जान सकता हूं कि जो 17 हस्पताल खोलने । को योजना है वह कहां-कहां पर खोले जाएंगे ?

श्रीमती शारदा रानी : इस के लिए अलग से नोटिस दे दीजिए मैं फिर बता दूंगी । लेकिन यह हस्पताल नहीं होंगे रेफल हैल्थ सेंटर होंगे ।

चौधरी श्याम लाल : स्पीकर साहब मच्छी महोदया ने पार्ट 'बी' के उत्तर में कहा है कि पलवल सिविल हस्पताल का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है. । क्या मैं जान सकता हूं कि इस को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है?

श्रीमती शारदा रानी : यह तो फण्ड्ज पर डिपेंड करता है और पैसा मिलने का कोई निश्चित समय नहीं है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदया बताने को कृपा करेंगी कि । नारायणगढ में जो हस्पताल बना है वह कब तक चालू हो जाएगा? ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question. This does not arise out of this question.

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहिब वजीर साहिबा ने बताया था कि अगले साल में कोई हस्पताल नहीं खोला जाएगा । क्या मैं जान सकता हूं कि लोगों में बीमारी ही कम हो गई है या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है हस्पताल खोलने के लिए?

श्रीमती शारदा रानी : बात यह है कि हस्पताल खोलने के लिए काफी पैसा चाहिए और हमारे पास उतना पैसा नहीं है, बाकी बीमारिया तो चलती ही रहती

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर महोदया बताने को कृपा करेंगी कि मटोर जो जीन्द का सब से बड़ा गाव है वहां पर न कोई डिस्पेंसरी है और न ही कोई वैटरिनरी डिस्पैसरी है । क्या वहां पर प्राईमरी हैल्थ सेंटर खोलने को कृपा की जाएगी?

Mr. Speaker : Order please. This isn not a supplementary question.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहिबा बताने की कृपा करेंगी कि इन हस्पतालो में कुल कितने बैडज का अरेजमेंट है और क्या स्टेट की जरूरत के मुताबिक वह पूरे हैं या कम हैं?

श्रीमती शारदा रानी : स्टेट की जरूरत के मुताबिक बैडज पूरे तो नहीं हैं लेकिन अलग-अलग उन हस्पतालों की जो नम्बर अगफ बैडज की डिटेल है वह इस तरह से है :-

हस्पताल का नाम संख्या	बैडज की
1) फिरोजपुर झिरका	25
2) नुंह	25
3) नारनौल	120
4) कालका	25
5) हिसार	200
6) झज्जर	25
7) महेन्द्रगढ	25
8) लोहारू	25
9) तोशाम	25
10) गोहाना	25
11) कौथल	50
12) गुड़गांव	150

13)	नरवाना	50
14)	जींद	50
15)	भीवानी	200
16)	कुरुक्षेत्र	50
17)	रिवाड़ी	50
18)	नारायणगढ	50
19)	जमनानगर	50
20)	मैडिकल कालेज हस्पताल	192
21)	सरसा	100

लेकिन सरसा का जहां तक सम्बंध है वहां के रेजीडेंशल क्वार्टर अभी बन रहे हैं, और आदमपुर तथा जगाधरी में अभी तक नए अस्पताल नहीं बनाए गए हैं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहब जब मैंने सवाल पूछा था कि नारायणगढ का हस्पताल कब तक चालू हो जाएगा तो आप ने डिसअलाऊ कर दिया था लेकिन अभी वजीर साहिबा ने बताया है कि वहां पर 50 बैड का हस्पताल बना है । तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह कब तक चालू कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : अब आप पूछ सकते हैं । श्रीमती शारदा रानी रू 1974- 75 में ही चालू कर दिया जाएगा । श्री अमर सिंह रू क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर और डिविजनल हैडक्वार्टर पर जो हस्पताल बनार गए हैं उन कितने-कितने बैड्ज होने चाहिए इसका क्या क्राईटेरिया रखा गया है?

श्रीमती शारदा रानी : यह वैसे तो जरूरत पर और आबादी पर डिपेंड करता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और सब डिविजनल लैवल पर हम कम कम 50 और 25 बैड का हस्पताल प्रोवाईड करना चाहते हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा : मंत्री महोदया ने जो हस्पताल अभी बताए हैं उन में से क्या किसी में अगले साल बैड बढ़ाने की योजना है?

श्रीमती शारदा रानी : नहीं जी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : वजीर साहिबा ने अभी बताया कस कि जिला लैवल पर और सबडिविजनल हैडक्वार्टर पर कम से कम 50 और 25 बैड की हस्पताल प्रोवाईड किया जाएगा । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारा झज्जर तहसील हैडक्वार्टर है और मिलटरी का एरिया है इस लिए वहां पर क्यों ज्यादा बैड प्रोवाईड नहीं किए जाते?

श्रीमती शारदा रानी : अभी तक तो वहां पर डिस्पैसरी थी लेकिन तुम ने वहां पर 25 बैड का इन्तजाम कर दिया है । इसलिए मैम्बर साहिब कुछ देर के लिए सब्र करें फिर किसी वक्त बढ़ा देंगे ।

चौधरी दल सिंह : क्या मवी महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जितने हस्पतालों का उन्हाँने जिक्र किया है उन सब में दवाईयों का मुकम्मल इन्तजाम है?

श्रीमती शारदा रानी : अपनी तरफ से तो चेष्टा यही रहती है कि दवाईयों का मुकम्मल इन्तजाम हो लेकिन इसमें बहुत सी बाधाएं हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जो हस्पताल 1972- 73 में खोले गए थे वहां के लोगों की तरफ से ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि उन में दवाईयां नहीं मिलतीं?

श्रीमती शारदा रानी : मैडीसन्ज की शिकायतें आती हैं विशेषकर मंहगी दवाईयों के न मिलने की । हमने अमरजैसी के लिए ही मंहगी दवाईयां रखी हुई होती इसलिए वह सब मरीजों को नहीं दी जा सकतीं । हम सैंट-परसैट दवाईयां प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उस के लिए बहुत पैसा चाहिए ।

Night Bus Service

***669. Chaudhri Phul Singh Kataria :** Will the

Minister for Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide night bus service from Chandigarh to Rewari via Rohtak, Jhajjar, if so, the period within which it is likely to be materialised ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : चण्डीगढ़ से रिवाड़ी बरास्ता रोहतक—झज्जर रात्रि बस—सेवा अप्रैल, 1974, से चलाई जाएगी । चौधरी राम लाल वधवा रू क्या मवी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नाईट सर्विस और कहां—कहां पर चलती हैं?

विकास मन्त्री (कर्नल महा सिंह) : नाईट सर्विस हमारी स्टेट में गुड़गांव में फिरोजपुर झिरका से, महेद्रगढ़ में नारनौल से, बल्लभगढ़ से भी चलती है, और देहली से चण्डीगढ़ और देहली से डबवाली चलती है

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या वजीर साहब बताएंगे. कि चण्डीगढ़ से हिसार और हिसार से चण्डीगढ़ के लिए नाईट सर्विस चलाने का विचार है?

कर्नल महा सिंह : जी हो गमियों में शुरू करेंगे, अभी आज कल इतनी सवारियां नहीं मिलती ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गवर्नमेंट की ऐसो योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर को देहली और चण्डीगढ़ से नाईट सर्विस से मिला दिया जाए?

कर्नल महा सिंह : स्पीकर साहब ऐसा है जहां पर जरूरत समझी जाएगी वहां से नाईट सर्विस चलाई जाएगी लेकिन जो जिला हैडक्वार्टर देहली से नजदीक पडते है वहां पर नाईट सर्विस की जरूरत नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बताएंगे कि कुरुक्षेत्र से भी नाईट सर्विस चलाने का, जो चण्डीगढ पहुचा सके, गवर्नमेंट का विचार है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : नहीं जी, अभी तो नहीं है क्योंकि वह से काफी बसे हो कर आती जाती हैं ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जौ हरियाणा मे नाईट सर्विस चलती है इसमें रात के वक्त रास्ते मे चाये पानी का कोई बंदोबस्त है या नहीं?

कर्नल महा सिंह : हर जगह सब-डिपोज पर इसका बंदोबस्त है?

चौधरी अमीर चन्द : कक्कड़ रू क्या वजीर साहब बतायेगे कि नाईट सर्विस तजुरब्बा इन्कम के लिहाज से कैसा साबित हुआ हे?

कर्नल महा सिंह : बहुत अच्छा । बहुत सवारियां मिलती हैं और दिन से भी ज्यादा मिलती है खास तौर पर गर्मियों के दिनों में ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि फरीदाबाद से चण्डीगढ़ के लिए नाईट सर्विस कब तक चला देगे?

कर्नल महा सिंह : बल्लभगढ़ से चण्डीगढ़ के लिए नाईट सर्विस चलती है और वह फरीदाबाद से होकर ही आती है और यह इनके कहने पर ही है इन्होंने ही फरमाया था कि बल्लभगढ़ से चलाई जाये ।

मलिक सत राम दास बसरा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि रात के वक्त चलने वाली बसों के साथ मकैनिक रखने की भी कोई तजवीज हूँ ताकि अगर कोई बस खराब हो जाए तो ठीक हो सके और लोगों को तकलीफ न हो?

कर्नल महा सिंह : इसकी अभी आवश्यकता नहीं समझी जाती है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो रात को बसे चलती हैं ये साधारण बसे चलती हैं या डीलक्स और क्या किराया साधारण लिया जाता है या ज्यादा लिया जाता है? कर्नल महा सिंह रू अभी नाईट सर्विस में हमारी बसे साधारण ही चलती हैं और किराया भी साधारण ही लिया जाता है ।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि देहली से चण्डीगढ़ के लिए जो नाईट सर्विस है जब से वह चली हूँ तब से कितने ऐक्यीडैट हुये ह?

कर्नल महा सिंह : इस के लिये सेपरेट नोटिस चाहिये लेकिन ऐक्सीडेंटस जैसे दिन के वक्त होते हैं वैसे रात के वक्त भी होते हैं रात को कोई ज्यादा नहीं होते है

श्री मेम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि चंडीगढ से देहली को जो नाईट सर्विस चलती हूँ उस के बारे क्या ऐसा कम्बिज्न करने के लिए तैयार है कि उसे कुरुक्षेत्र से हो कर चलाया जाए?

कर्नल महा सिंह : नहीं जी, उसकी जरूरत नहीं समझी जाती ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या वजीर साहब बतायेगे कि जो रात को वसें चलती हैं क्या उनके लिए पहले से ही उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध कर लिया गया है ?

कर्नल महा सिंह : ला एंड आर्डर का होम मिनिस्टर साहब ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है । (हंसी)

Income from the Sale of Wine

***571. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state—

(a) the income accrued to the Government by the sale of wine during the financial year 1967-68;

(b) the district-wise income accrued to the Government the sale of Country liquor and Indian Made

Foreign Liquor, separately, during the period as referred in part (a) above;

(c) the total income accrued by the sale of wine during the financial year 1972-73; and

(d) the district wise income accrued to the Government by the sale of Country liquor and Indian Made Foreign Liquor during the period as referred to in part (c) above, separately?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) :

(a)

(b) A statement is laid down on the Table of

(c) the House

(d)

STATEMENT

(a) Rs. 6,18,09,037

(b)

Name of District	Income from Country Liquor	Income from Indian Made Foreign Liquor	Total
Hissar	1,03,60,797	1,62,672	1,05,23,469

Rohtak	1,14,35,291	3,70,120	1,18,05,411
Gurgaon	93,69,706	12,18,944	1,05,88,650
Karnal	95,08,089	13,31,544	1,08,39,643
Ambala	99,13,476	28,87,280	1,28,00,756
Mohindergar h	22,02,521	26,200	22,28,721
Jind	29,84,038	38,349	30,22,387
Total	5,57,73,918	60,35,119	6,18,09,037

(c) Rs, 12,44,63,989.

(d) —

Name of District	Income from Country Liquor	Income from Indian Made Foreign Liquor	Total
Hissar	2,26,17,364	13,37,024	2,39,54,388
Rohtak	1,84,66,334	25,59,385	2,10,25,719
Gurgaon	1,64,82,942	72,68,145	2,37,51,087
Karnal	1,94,41,044	49,10,164	2,43,51,208
Ambala	1,79,88,590	59,68,161	2,39,56,751
Mohindergar h	2,84,510	1,464	2,85,974

Jind	69,36,039	2,02,823	71,38,862
Total	10,22,16,823	2,22,47,166	12,44,63,98

9

Note .—(1) District and Tehsils were re-organised in the State about the end of calender year 1972, but the above position relates to the pre-re-organisation districts.

(2) District Mohindergarh remained dry during the year 1972-73. The income shown above against this district was for 1973-74, but was deposited into the treasury during the year 1972-73 in the form of security for country liquor licenses and license fee etc. for foreign liquor shops for the year 1973-74.

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1968 के मुकाबले में 1972— 73 में शराब से जो आमदनी हुई है वह दो गुना हो गई है इसका क्या कारण है?

Shri Shyam Chand : Sir, I told the hon. Member yesterday that there are so many reasons for this, First, there is increase in the population. Secondly, there is increase in the number of ex-service men. Thirdly, there is increase in the number of tourists visiting Haryana. Fourthly, we have eliminated illicit distillation and, therefore, now the people go in for licensed liquor. Another reason is that we have liberalised the excise policy, so that there are no monopolists.

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : स्पीकर साहब, सब से बड़ी वजह यह है कि किसान ज्यादा खुशहाल हो गए हैं । (हंसी)

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जब से आप ने शराब की बढ़ोत्तरी की है सरकार की तरफ से तब से जो इलिसिट शराब निकलती है वह ज्यादा निकलती है या कम निकलती है?

श्री श्याम चन्द : बढ़ौतरी करने वाले तो वही है । हमारा जिला रोहतक पहले ड्राई एरिया होता था लेकिन इन्हीं ने पहली दफा उसे वैट किया था । (हसी)

चौधरी लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कटरी मेड लीकर और इन्डियन मेड फोरन लीकर की बोतल कितने में तैयार होती है और सरकार उस पर ड्यूटी कितनी लगाती है?

Shri Shyam Chand : It depends whether it is from molasses or from malt.

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि शराब ज्यादा बढ़ जाने से लीगी में लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी ज्यादा नहीं बढ़ गई हैं?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब कुछ आदमी ऐसे है जो पीते है देसी और लड़ाई करते हैं अंग्रेजी शराब की दुकान पर । (हंसी)

Jui Canal

***387 Shri Behari Lal Balmiki :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area of land irrigated by the Jui Canal during the year 1973; and

(b) the period in a year during which the water flows in the said Canal ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) Irrigation of 18,000 acres has been booked upto 15/12/1973; further booking is in progress.

(b) Jui Canal was run for 188 days in 1973.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जुई कैनल पर कितना खर्च हुआ है और पानी इस में कहां से आता है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : खर्च इस पर 3. 31 करोड़ आया है और पहले-पहले इस में फ्लड वाटर दिया था और उस के बाद औगशमैटेन कैनल बनाने से और औगमैटेशन ट्यूबवैल्ज लगाने से जो पानी बढ़ा है उस में से कुछ हिस्सा जुई कैनल को मिलता है ।

श्री हरि सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जुई कैनल कौन से मुकाम से शुरू होती है और कौन से मुकाम पर खत्म होती है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : स्पीकर साहब यह जुग्राफिया का सवाल हर रोज आना शुरू हो गया है हांसी ब्रांच को दो नहरें हो जाती हैं । एक भिवानी को जाती है और एक जाती है सुन्दर सब-ब्रांच को जो आगे जाकर जूई फीडर बनती है और फिर आगे जाकर जूई कैनल बनती है ।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जूई कैनल में कितना पानी वैस्टर्न जमुना कैनल से और कितना पानी औगमैटेशन कैनल से लिया जाता है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : हमारा सारा पानी ज्वायंट है । इस में वैस्टर्न जमुना कैनल का पानी, औगमैटेशन ट्यूबवैल्ज का पानी भी और औगमैटेशन कैनल का पानी भी पड़ता है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें वैस्टर्न जमुना कैनल का कितना पानी और औगमैटेशन कैनल का कितना पानी पड़ता है ।

श्री गुसाब सिंह जैन : क्या वजीर साहब बताधेंगे कि जूई कैनल से कुल कितनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगी और खर्च इस पर कितना हुआ है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : इस पर 3.31 करोड़ रुपया खर्च आया है और एक साल में इससे दो करोड़ 70 लाख रुपये की ऐडीशनल क्रॉस होगी यानी 75 फीसदी एक साल में रिटर्न होगी ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि इस जूई कैनल की कैपेसिटी किननी हे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : 250 क्युसिक्स ।

Minor irrigation (Tubewells) Corporation

***602 Chaudhri Dal Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of State tube-wells working under the Minor Irrigation Scheme as on 30-11-1973;

(b) whether the Minor Irrigation Tube-wells Corporation is running in profit ;

(c) if so, the total profit earned by the said Corporation in the year 1972-73 ; and

(d) if the answer to part (b) above be in the negative, the total loss suffered by the said Corporation in the year 1972-73 ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) 1621.

(b) Yes, Sir.

(c) The accounts for the year 1972-73 have not yet been audited by the statutory Auditors. However, the tentative Balance Sheet has been drawn up and this reveals a net profit of Rs. 8,52,000.

(d) Does not arise in view of (b) above.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि ट्यूबवैल्ज को खोदने लिये हमारे पास कितनी मशीनरी है और उसकी कितनी कीमत है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : हर मशीन को अलग-अलग कीमत है और हमारे पास इतनी मशीने हैं कि दूसरे सूबों को भी हम फीड कर रहे हैं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1062 ट्यूबवैल्ज जो एम. आई. टी. सी. ने लगाये है इन से कितनी जमीन सैराब होगी और अनाज की पैदावार बढ़ाने में कितना फायदा होगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठा : हम ने जो ऐडिशनल पानी दिया है औगमेंटेशन ट्यूबवैल्ज से और डायरैक्ट ट्यूबवैल्ज से वह 2, 800 क्यूसिक्स दिया है और हम तीन चार सी एकड़ पर एक ट्यूबवैल देते है ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि इन ट्यूबवैल्ज पर टोटल खर्च कितना हुआ है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : इसके लिए सैपरेट नोटिस दें तो बता देते ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इन में से कितने ट्यूबवैल्ज चल रहे हैं और कितने बंद हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा: टोटल ड्रिल्ड ट्यूबवैल्जु 2060 है और इन में से 851 डायरैक्ट और 770 ओगमेंटेशन ट्यूबवैल्ज चल रहे हैं ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि और अधिक ट्यूबवैल्ज लगाने के लिये और रिग्ज खरीदने की कोई तजवीज है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : हमारे पास इतने रिग्ज है कि हर साल हम एक हजार क्यूसिक्स पानी ऐड कर सकते हैं ।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : हम कुछ रिग्ज ऐसे खरीदना चाहते हैं जो पहाड़ी एरिया के अन्दर बोरिंग कर सकें और उसके लिये एग्रीकलचुर डिपार्टमेंट को हमने अपनी रिक्वीजीशन भेजी हुई है और वह इस बात पर विचार कर रहे हैं । सब माउनटैनस-एरिए के अन्दर ट्यूबवैल लगाए सकते हैं और ऐसे रिग बाहर से इम्पोर्ट करने का विचार है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बाहर के किस प्रान्त में इस कापोरेशन ने काम किया है और इससे कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च आया?

मुख्य मन्त्री (चौधरी वैसी लाल) : स्पीकर साहब, इस वक्त हमारी एम ० आई० टी ०सी० विहार में काम कर रही है । आमदनी को फिगर जैसे पहले बताया गया है, बाद में आएगी लेकिन इतना बता देता हूं कि अब हमारा टैंडर नेपाल में भी एक्सैप्ट होने वाला है ।

मलिक सत राम दास बसरा: जहां पानी कड़वा है और लोग ट्यूबवैल का फायदा नहीं उठा सकते, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि ऐसी जगहों पर नहरी पानी देने की कोई तजवीज ह?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : जब रावी-व्यास का पानी आएगा तब जहां-जहां कमी होगी, पूरी की जाएगी ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि झध्वैर तहसील और नाहड के एरिया मे कोई स्टेट-ट्यूबवैल लगाने को योजना है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : डैफिनेट तो कह नहीं सकते, अगर नीचे पानी है तो हम ट्रायल-बोर करवा कर देख लेंगे ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कार्पोरेशन के तहत जो डीप । बैल्ज खोदे गये हैं, इनके बारे में क्या कोई शिकायत सरकार के पास आई है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : किस ढंग को शिकायत?

श्री अमर सिंह : ऐसी शिकायत जिसमें पानी को तकलीफ की शिकायत हो?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : पिछले साल नरवाना ब्रांच से शिकायत आई थी और उसकी वजह यह थी कि कई साल बारिश न होने की वजह से पानी नीचे चला गया था ।

श्री हरि सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि माइनर इरीगेशन ट्यूबवेलज कार्पोरेशन के तहत स्टेट में रिसर्च सेटर भी खोले गये हैं जो टेक्निकल रिसर्च करते हैं

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : वे काबिल इंजीनियर हैं और रिसर्च कर रहे हैं ।

चौधरी दल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि व्यास रावी से कब तक पानी मिलने की आशा है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : जब व्यास-लिंक बन जाएगा उस वक्त पानी मिलेगा ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नाहड के इ लाके में जो बोरिंग किया था उसका क्या रिजल्ट है?

श्री बनारसी दास गुप्ता : इसके लिए अलग नोटिस दे तो इन्फर्मेशन दी जा जाती है ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब ऐसे ट्यूबवैल हो सकते हैं जो कुछ समय के बाद अनसर्विसेबल हो गए हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे ट्यूबवैल हैं जो शुरू से ही अन-सर्विसेबल हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : ऐसे ट्यूबवैल हो सकते हैं जिनको हमने एक बार शुरू किया और इन-कम्पलीट पड़े हैं और इ सकी वजह बिजली न मिलने की हो सकती है । लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि डिपार्टमेंट की वजह से कोई ट्यूबवैल खराब पडा हो ।

Police Station

***731 Shri K. N. Gulati ;** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the total number of Police Stations in Faridabad/Ballabgarh area ;

(b) whether the Police Stations referred to in part (a) above are located at easily accessible places; and

(c) if the answer to part (b) above is in the negative, the time by which these Police Stations will be so located ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :
(ए) तीन ।

(बी) हां ।

(सी) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : स्पीकर साहब, एन० आई ० टी० फरीदाबाद का जो पुलिस स्टेशन हूँ उसको नम्बर 1 का इलाका नजदीक पड़ता है लेकिन वह सैक्टर 15 के थाने के साथ लगा दिया है । क्या मन्त्री महोदय उस पुलिस स्टेशन को नजदीक के थाने के साथ लगा देंगे?

श्रीमती शारदा रानी : सैक्टर— 15 में सैट्रल पुलिस स्टेशन है और नया बनाया गया है । क्राइम्ज की स्थिति को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था एन ० आई ० टी० के साथ पड़ने वाले स्टेशन और बल्लभगढ पुलिस स्टेशनों का थोड़ा—थोड़ा भाग निकाल कर इसमें मिलाया गया है । अगर इसकी आवश्यकता हुई तो देख लिया जाएगा ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : 5 नम्बर पुलिस स्टेशन में जो जुडिशियल के होते हैं उन के लिए गुड़गांवा भागना पड़ता है । क्या मन्त्री महोदय इसको बल्लगढ के साथ मिलायेंगे?

Mr. Speaker : It is suggestion and not a supplementary question.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मन्त्री महोदया बतायेगी कि पुलिस स्टेशनों पर और पुलिस पोस्टों पर स्टैन्थ कम है? इस कमी को पूरा करने के लिए क्या सरकार स्ट्रैन्थ बड़ाने का विचार रखती है?

श्रीमती शारदा रानी : जी हां ।

Paediatrics Clinic

***678 Chaudhri Mehar Chand** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of the Hospitals where the facility of paediatrics clinic has been provided in the State;

(b) whether the Government intends to provide this facility in every Hospital located at district headquarters in the State; and

(c) if so, the time by which this facility is likely to be provided

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) पैआडिट्रिक्स क्लीनिक निम्नलिखित हस्पतालों में है
: (1) सिविल हस्पताल, करनाल ।

(2) सिविल हस्पताल, अम्बाला ।

(3) सिविल हस्पताल, हिसार ।

(4) सिविल हस्पताल, नारनौल ।

(5) सिविल हस्पताल' गुड़गांवा ।

(बी) हां ।

(सी) बाकी जिला हैडक्वार्टर्ज के हस्पतालों में पंआडिट्रिक्स क्लीनिक उपलब्ध करने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोशिश की जाएगी ।

Area Irrigated by Canals and Tube-Wells

***694. Chaudhri Surjit Singh Mann :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area in the State irrigated by canals in the year 1967-68 and 1972-73 separately;

(b) the total area in the State irrigated by tube-wells in the years 1967-68 and 1972-73 separately; and

(c) the target fixed for irrigating land from canals and tube-wells separately, during the year 1973-74.

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : (a), (b) & (c) A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) The total area Irrigated by Canals in the State is as under :—

In the year 1967-68 — 33,57,400 Acres

In the year 1972-73 — 38,07,527 „

In addition to the above, area irrigated in Haryana by Agra Canal under the administration of U.P. Govt, is as

under :-

In the year 1967-68 - 34,199 Acres

In the year 1972-73 — 76,204 Acres

(b) total area irrigated by tube-wells

during the year 1967-68 8,51422-5

Acres

and during the year 1972-73 — 26,02,060

Acres

(c) (i) Target fixed for irrigation by

canals, during the year 1973-74 — 36,89,000

Acres

(ii) Target fixed for irrigation by

tube-wells, during the year 1973-74 — 26,81,020

Acres.

चौधरी सुरजीत सिंह आन : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया कि 1972-73 में 38,07,527 एकड़ एरिया इरीगेट हुआ है और आगे उन्होंने बताया है कि 1973-74 के लिये 38,89,000 एकड़ का टारगेट फिक्स किया है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह कमी किस वजह से हो गई?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : जो टारगेट रखते हैं वह फिक्स करना जरूरी है । कई बार बरसात ज्यादा होने की वजह से पानी ज्यादा भी दे सकते हैं और यह भी हो सकता है कि एक

वक्त वर्षा बिल्कुल न हो और पानी कम दें । इसलिए हम टारगैट तो 36, 89,000 एकड़ का ही फिक्स करते हैं लेकिन आम तौर पर इरीगेशन ज्यादा होती है ।

Segregated Children of Lepers

***700. Divan Hans Raj Suri** Will the Minister for Social Welfare

and Taxation be pleased to state -

(a) whether any care is being taken for the healthy segregated children of lepers; and

(b) if so, the details of the facilities, if any, which are being provided to such children ?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) ;

(a) Yes.

(b) A home for the healthy segregated children of lepers has been set up at Chhachhrauli (Ambala) by the Haryana State Child Welfare Council, wherein the inmates are provided free boarding, lodging and maintenance.

चौधरी राम लाल बधवा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसे बच्चों को कोठी से बिल्कुल अलग रखा जाता है या साथ?

Shri Shyam Chand ; It is a separate home for the children.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या' मंत्री महोदय बतायेगे कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं?

श्री श्याम चन्द : 48

Co-operative Societies

***704. Shri Jagjit Singh Tikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of Co-operative Societies working in the State as on 31st March, 1973;

(b) the total working capital of the said Co-operative Societies as on 31st March, 1973; and

(c) whether any Co-operative Societies were liquidated during the period from 1st May, 1968 to 31st March, 1973; If so the district-wise number thereof ?

सहकारिता तथा स्थानीय शासन राज्य मंत्री (चौधरी गोर्धन दास चौहान) : सहकारिता वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है । इसलिए सूचना सहकारिता विभाग में तदनुसार रखी जाती हैं । सूचना जो कि प्रश्न में मांगी गई है, 30 जून, 1973 तक प्रश्न के भाग 'क' तथा 'ख' के सम्बन्ध में और 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1973 तक प्रश्न के भाग 'ग' के सम्बन्ध में नीचे दी जाती है :-

(क) 15, 460

(ख) 213. 44 करोड़ रुपये

लाई गई संख्या	(ग) क्रम संख्या	जिला	परिसमापनाधीन समितियों की संख्या
	1	अम्बाला	237
	2	कुरुक्षेत्र	47
	3	करनाल	241
	4	जीन्द	64
	5	रोहतक	220
	6	सोनीपत	35
	7	गुड़गांव	271
	8	महेन्द्रगढ़	83
	9	भिवानी	44
	10	हिसार	265
		कुल योग	1507

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने मेरे सवाल के पार्ट (ए) में बताया कि इतनी सोसायटियां स्टेट मे वर्क कर रही हैं । क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन में ऐसी सोसायटियां भी हैं जिन पर एम्बैजलमेंट के केस थे?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : इसके लिए सैपरेट नोटिस दें ।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन सोसायटियों मे अर्बन एरिया की जितनी सोसायटिया हैं और रुरल एरियाज की कितनी है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए.

चौधरी मेहर चन्द : मन्त्री महोदय ने पार्ट (सी) के जबाब में फरमाया है कि 1507 सोसायटियों को लिक्विडेशन हुई है । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि लिक्विडेशन की वजह क्या थी?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : लिक्विडेशन को वजह कोआप्रेटिव एक्ट में है, इसको देख लें कि किमु वजह से लिक्विडेशन होती है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि 1507 सोसायटियां लिक्विडेट ही गई है । क्या मन्त्री महोदय वनायेगे कि इससे फाइनेशियल लोस कितना हुआ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : इसके लिए भी संपरेट नोटिस चाहिये ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहव, 1973 में कुछ सोसायटियों के लिये लिक्विडेटर मुकर्रर किए गए थे क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वे तमाम सोसायटियां लिक्विडेट हो चुकी हैं या बकाया रहती है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : यह तकरीबन हो ही चुकी है ।

चीधरो फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इनमे इंडस्ट्रियल सोसायटिया कितनी कितनी है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

चौधरी फूलचन्द (मुलाना) : क्या मन्त्री महोदय वनायेगे कि इन में कोआप्रेटिव फार्मिंग को सोसायटिया भी शामिल हैं अगर है तो क्या वे सोसयाटियां ठीक ढंग से चल रही हैं, क्या उनका झगड़ा होता है और इस कारण उनको तोड़ने के लिए तैयार है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : मेरे ख्याल में जो टूटी हुई हैं वे जरूर इममें शामिल होंगी । झगड़े वाली कोई बात नहीं है, अगर आपके नोटिस में झगड़े वाली कोई बात हो तो सरकार के नोटिस में लाए हम ऐक्शन लेंगे ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने सवाल के पार्ट (ए) के जवाब में बताया है कि 13,400 सोसायटियां हैं क्या मन्त्री महोदय डिस्ट्रिक्ट-वाइज ब्रेक-अप बनायेंगे ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए

श्री हरि सिंह : स्पीकर साहब, कई कोआपरेटिव सोसायटियों में कर्ज देते समय फर्जी अंगूठे लगाए हैं और उनके नाम कर्ज दिखा देते हैं । क्या मन्त्री महोदय 'के नोटिस में ऐसे केसिज आए हैं?

मलिक सतराम दास बत्रा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सोसायटियों को जो लोन दिया जाता है उसकी रिकवरी कितनी हुई है ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : इसके लिए भी सैपरेट नोटिस चाहिए जी ।

श्री अमर सिंह : क्या आनरेबल मिनिस्टर यह बताने की कृपा करेगे कि सरकार के पास इस किस्म की कितनी शिकायतें आई हैं कि तमस्सक गलत भरे जाते हैं और गलत लोन लिया जाता है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब वैसे तो यह सवाल मन सवाल से पैदा नहीं होता लेकिन अगर आनरेबल मैम्बर के नोटिस में कोई ऐसी बात होगी तो हम जरूर इक्वायरी करायेंगे और इन्साफ करेंगे ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने बताया कि हरियाणा प्रांत में कुल 13,460 सोसाईटीज हैं । क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से हरिजन सोसाइटीज कितनी हैं और दूसरी कितनी हैं?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब, इसके लिए भी सैपरेंट नोटिस ही चाहिए ।

Shortage of Cement

***709. Shri Girish Chander Joshi :** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state —

(a) whether it is fact that there is any scarcity of cement in the state, if so, the reasons therefor, and

(b) the steps, if any, taken by the Government for the proper and fair distribution of cement in the State ?

Social Welfare And Taxation Minister (Shri Shyam Chand):

(a) Yes, the scarcity of cement is not only in this State, but all over the country, mainly due to less production by the cement factories, on account of shortage of power, coal, inadequate supplies of empty wagons and occasional strikes in the cement factories, on the other hand, there has been considerable increase in demand due to developmental activities in the country.

(b) the State Govern: Anent has taken following steps to ensure proper and fair distribution of Cement in the State: —

(i) Promulgation of Haryana Cement (Licensing and Control order, 1973 with effect from 15-2-73 under which every cement Stockist is required to obtain a dealers Licence and arrange distribution of cement according to instructions contained therein.

(ii) Formation of Sub-Divisional level Committees under the charge of Sub-divisional Officers (Civil) in each Sub-division for issue of cement permits to general consumers in the State.

(iii) Earmarking of separate quota of cement for Industries and its allotment through the Director of Industries, Haryana.

(iv) Earmarking of 25,000 tonnes per quarter under free sale category with break-up of 10,500 tonnes each for urban and rural areas and 2,000 tonnes each for Panch-

ayats and such small scale Industries, whose demands are less than a wagonload.

Government of India has been approached at the highest level to enhance the allocation of our State.

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि यह बात सच है कि हरियाणा प्रान्त में जो सीमेंट पैदा होता है वह बाहर भेजा जाता है और वाहर से हरियाणा प्रान्त को सीमेंट आता है?

Shri Shyam Chand : Sir, the allocation is made by the Government of India.

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस सीमेंट की कमी को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ में सीमेंट फ़ैक्टरी लगाने का मामला गवर्नमेंट के विचाराधीन है?

Shri Shyam Chand : Sir, the department is already seized of the matter.

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : स्पीकर साहब, उस सन्बन्ध मे मैं थोड़ी रोशनी डाल दू । गवर्नमेंट आफ इंडिया तो चाहती है कि हम निजामपुर में नारनौल के पास एक सीमेंट फ़ैक्टरी लगाएं लेकिन हम फ़ैक्टरी लगाना नहीं चाहते क्योंकि हमारा सीमेंट बाहर जाएगा और हमको मिलना नहीं । हम तो लाईम स्टोन का चूना बनाकर खुद इस्तेमाल करेंगे सीमेंट फ़ैक्टरी नही लगाएगे ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि हरियाणा में जो सीमेंट फ़ैक्टरीज हैं उन पर हरियाणा सरकार का कंट्रोल किस हद तक है?

चौधरी बंसी लाल : किसी भी हद तक नहीं है ।

श्री अमर सिंह : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में जो सीमेंट फ़ैक्टरीज हैं उनमें सीमेंट की कितनी प्रोडक्शन है और हमारी डिमांड कितनी है?

श्री श्याम चन्द : डिमांड के बारे में तो स्पीकर साहब कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन हमारे यहाँ दो फ़ैक्टरीज सूरजपुर और दादरी में हैं जिनसे हरियाणा को दस हजार टन सूरजपुर से मिलता है और सतरह हजार टन दादरी से मिलता है ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा सरकार को जुलाई क्वार्टर, अक्टूबर क्वार्टर और जनवरी क्वार्टर में कितना सीमेंट ऐलोकेट हुआ?

Mr, Speaker : No Sir, I need a separate notice for that.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बनाने को कृपा करेंगे कि ये दोगे फ़ैक्टरीज कितना सीमेंट पैदा करती हैं?

श्री श्याम चन्द :. सूरजपूर 30,000 टन और दादरी 17000 टन ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि सीमेंट के डिपोज मेलने में हरियाणा सरकार का कंट्रोल नहीं है लेकिन जो डिपोज हैं उन्होंने अपने खब-डिपोज खोल रखे है । जब एलोकेशन होती

Mr, Speaker : No argumentative supplementary question please.

श्री जगजीत सिंह टिक्का : इसमें सप्लीमेंटरी स्पीकर साहब इसके बाद ही बनता है ।

Mr. Speaker : You put a direct supplementary question,

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो सब-डिपोज हैं उन पर सीमेंट भेजने के लिए डिपो वालों को ओब्लीगेटरी करेंगे कि वे अपने सब-डिपोज पर लाजमी तौर पर सीमेंट भेजे क्योंकि सब-डिपोज पर

Mr. Speaker : Again argumentative supplementary question. Not allowed.

श्री के 0 एन 0 गुलाटी : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लैक में जो सीमेंट मिलता है यह कहां से आता है?

Mr. Speaker : This is also not a supplementary question.

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करे कि जहां पंचायत और गाँव वाले लोग रुपया इकट्ठा करके स्कूल बनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें डेढ हजार या दो हजार कट्टे सीमेंट की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए सरकार तैयार है और उसके लिए क्या इन्होंने बन्दोबस्त कर रखा है?

Shri Shyam Chand : I have already told the Hon. Members that there is sparate quota for the Panchayats .

श्री अमर सिंह : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में चल रही सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए यह सरकार सैट्रल गवर्नमैट को इस बात के लिए मनाने के लिए तैयार है कि हरिया णा की सीमेंट प्रोडक्शन हरियाणा में ही रहे?

Shri Shyam Chand : Sir, we have written to the Government of India to enhance our quota. The Hon'ble Chief Minister has also written a letter to the Industries State Minister and I think something will be done.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा के कितने ऐसे डिपाटमेंट्स हैं जिनको सैपरेट कोटा एलोकेट किया गया है?

श्री श्याम चन्द : इंडस्ट्रीज और पंचायत ।

चौधरी अमीर चन्द कवकड : क्या मिनिस्टर साहब फरमायेगे कि इसकी क्या बजह है कि कंट्रोल लागू होने से पहले तो 100 परसेंट डिमांड पूरी होती थी मगर आज जबकि 60 परसेंट गवर्नमेंट के काम भी बंद हो चुके हैं, 40 परसेंट डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है?

श्री श्याम चन्द : सर कंट्रोल शार्टेज के बाद किया है?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह शयोरां : स्पीकर साहब, स्कूलों के लिए पंचायत को 20 से ज्यादा कट्टे नहीं मिलते । मजदूरी मजदूरी तो पूरी लेता है मगर बैठा खाली रहता है । इसलिए मेरी मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीमेंट मिलना चाहिए ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

राव दलीप सिंह : स्पीकर साहब, किसान लैंड मार्गेज बैंक से जमीन गिरवी रख कर कुआं बनाने के लिए लोन लेता है । क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि उसको कुआं बनाने के लिए 'सीमेंट देने का सरकार कोई खास प्रबन्ध करेगी क्योंकि उसने इस्टालमेंट भी अदा करनी होती है?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है लेकिन जितनी डिमांड है उसमें और सप्लाय में

काफी अन्तर है इसलिए कुछ लोगों को इन्तजार भी करना पड़ेगा ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, कंट्रोल सिस्टम से लोगों को बड़ी तकलीफ बैग । क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे इसे खुले बाजार में मुहैया करवाने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम चन्द : जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी उसके बाद ।

चौधरी राम जी लाल : मगर क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब नूह तहसील में सीमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड प्रौपर है तो वहां स्कूल की बिल्डिंग क्यों गिर रही है?

श्री श्याम चन्द : इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

श्री अमर सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शार्टेज कब तक रहेगी?

Shri Shyam Chand : This is not a fact. It depends upon power supply and also frequency of wagons. If we get both, then I think the shortage will be removed.

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेगे कि जो डिपो वाले अपने सब-डिपो पर माल नहीं भिजवाते उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लेंगे?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, सब-डिपो को तो अलाउ ही नहीं करते ।

श्री गुलाब सिंह जैन : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि जो सीमेंट आता है उसे डिफरेंट हेडज में यानी अर्बन एरिया के लिए इतना रूरल एरिया के लिए इतना और इंस्टिच्यूशन्ज के लिए इतना, ऐलोकेट किया जाता है । क्या वे यह बताने को कृपा करेंगे कि जो सीमेंट अर्बन एरिया में दिया जाता है उसकी ऐलोकेशन में नई कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए अलग-अलग कोटा मुकर्रर किया जाएगा?

Shri Shyam Chand : There is already separate quota for new constuction and repair.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि हरेक डिपार्टमेंट को अलग से कोटा दिया जाता है । हरिजन वैल्फेयर बोर्ड को ओर से हरिजनो को गावो में चौपाल और कुये बनाने के लिए ग्रान्ट दी जाती एं तो मैं यह जानना चाहता है कि क्या उनको भी अलग से कोटा दिया जायेगा क्योंकि वैलफेयर का महकमा भी इनके पास ही है ओर सीमेंट देने का महकमा भी इनके ही पास है ?

श्री श्याम चन्द : पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से हरिजनों को सैपरेट कोटा मिलता है ।

श्री निहाल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वैग्नज की कभी को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखेगी कि हरियाणा प्रदेश को हरियाणा की ही फैक्टरी से सीमेंट दे दिया जाये?

Shri Shyam Chand : Sir, we have already requested the Government of India.

Uchana Lake

***548 Chaudhri Ram La! Wadhwa** : Will the Minister for Home be pleased to State—

(a) the total amount spent on land, buildings and lake, separately, up to 30th November, 1973 at Uchana; and

(b) the income accrued from and expenditure incurred on the lake, restaurant, separately, during the period from 1.4.1973 to date ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी) :
अपेक्षित सूचना (केवल 9/73 तक) निम्न प्रकार है

भवन 18,39000 /—

भूमि 20,000 /—

लेक 7,71,000 /—

(बी) अपेक्षित सूचना (1/4/73 से 30/11/73 तक) निम्न प्रकार है

	खर्च	आय
लेक	5,658 /—	9,360 /—
रेस्टोरेंट	5,28,516 /—	5,57,319 /—

रेस्टोरेंट, बार, वैंड, कैन्टिन, बेकरी, कबाब कौरनर तथा सनैक कीरनर के स्टोरेज की खरीद खर्च इक्के किये जाने हैं अतः इन सब का लेखा जोखा रेस्टोरेंट में ही डाला गया है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंजे महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि रेस्टोरेंटम के अन्दर जो चीजें मिलती है वे बाजार के रेट्स से ज्यादा भाव पर मिलती हैं ?

श्रीमती शारदा रानी : ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नहीं हैं । कीमतें बढ़ गयी हैं । आप इस सवाल को ठीक ढंग से पुट करें ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि जी 0 टो 0 रोड पर करनाल के आस-पास कोई ऐसी खूबसूरत जगह बनायी है, डिवैल्प की है जिसस करनाल की शान बढ़ी हो ?

श्रीमती शारदा रानी : यह चौधरी रामलाल जी बता देंगे । (हंसी)

गृह मंत्री (श्री के 0 एल0 पोसवाल) : स्पीकर साहव
ये खूबसूरत चीजों को देखते ही नहीं हैं ।

procurement of Paddy

***655. Shri Om Parkash Garg:** Will the minister for social welfare and taxation be pleased to state—

(a) the quantity of paddy procured during the year 1968-69 ;

(b) the quantity of paddy so far procured in the State and the quantity likely to be procured during the current season; and

(c) whether the target fixed for procurment for the current year is likely to be achieved ?

Social Welfare and taxation Minister (Shri Shyam Chand) :

(a) No paddy was procured during the year 1968-69 but a quantity of 1.60 lakh tonnes of rice was procured under the levy scheme in that year.

(b) Procurement of rice is done in our State under the levy Scheme and as such no procurement of paddy is being made by the State Government. However, Food Corporation of India enters the market to procure paddy if the rates fall below the procurement price. The Food Corporation of India has procured 6400 tonnes of paddy this year and the rice millers have purchased a little over 6 lakh tonnes of paddy. A further quantity of 8000 to 10,000 tonnes of paddy is likely to

be purchased by the rice millers during the remaining period of current season.

(c) A target of 3.49 lakh tonnes of rice has been fixed for our State and we are likely to exceed the target.

चौधरी दल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह सच्चाई है कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट ट्रेडर्स को हरियाणा से बाहर पैड्री और राइस भेजने की इजाजात दी है और अगर दी है तो कितने के लिए दी है?

Shri Shyam Chand : It is not a fact.

***Starred Question No. 670**

Mr. Speaker : The extension asked for has been granted by me. The letter received from the Minister concerned in this behalf is as under.—

“चिरजी लाल

मन्त्री

राजस्व विभाग, हरियाणा

चंडीगढ़ ।

अ० स० पत्रांक 190— स्था (1)

—74 / 1129

चंडीगढ़, दिनांक 11 जनवरी,

1974 ।

विषय : चौधरी फूलसिंह कटारिया, सदस्य हरियाणा विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न नम्बर— 670—राज्य में पिछड़े क्षेत्र ।

प्रिय श्री सरूप सिंह जी,

कृपया तारांकित विधान सभा प्रश्न नम्बर 670 जो 15-1 - 1974 की सूची में चौधरी फूलसिंह कटारिया, सदस्य, दिन सभा के नाम है की ओर ध्यान देने का कष्ट करे । इस प्रश्न का उत्तर अभी तक तैयार नहीं है क्योंकि वाँछित सूचना को एकत्रित करने के लिए समय चाहिए । अतः आपसे प्रार्थना है कि इसका उत्तर देने की तिथि एक फरवरी 1974 तक बढ़ाने की स्वीकृति दें इस प्रश्न का उत्तर देने का समय बनाने के लिए सचिव, हरियाणा विधान सभा चंडीगढ़ से अलग से प्रार्थना भी की गई है । इस प्रश्न को 1 - 2- 1974 के बाद किसी तिथि को उत्तर के लिए निश्चित कर दिया जाये ।

भवदीय,

ह 0 चिरंजी लाल

चौधरी स्वरूप सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

चंडीगढ़ ।

House Building Loans

*572 Chaudhri Shiv Ram Verma ; Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) whether the Government will give interest free house building loans to the Low Income Group and economically backward people ;

(b) if so, the procedure thereof ; and

(c) whether the Government intends to give special attention to such people of rural areas ?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) :

(ए) नहीं ।

(बी) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(सी) नहीं ।

चौधरी शिवराम वर्मा : क्या मंजे महोदय बतायेंगे कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और गांव के लोग हैं उनको इससे क्यों वंचित रखा गया है?

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय हाउसिंग के लिए जो लोन मिलता वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से मिलता है । शर्तें और रेट आफ इन्ड्रस्ट उन्होंने ही मुकर्रर किया हुआ है । उसके मुताबिक ही हम लोन एडवान्स देते हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस आवश्यकता को ध्यान रखते हुए वे गवर्नमेंट आफ इंडिया को सुझाव भेजेंगे कि इसमें संशोधन करके, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं उनको कर्जा मिल जाए?

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय वैसे तो देहाती क्षेत्रों में जो भूमिहीन किसान हैं उनके सहूलियतें देने के लिए हरियाणा सरकार 100 वर्ग गज का प्लॉट मुफ्त देने की स्कीम केन्द्रीय सरकारकी सहायता से बनाने जा रही हैं । इस साल इस स्कीम पर 25 लाख रुपया खर्च किया जायेगा । इसके अलावा हरियाणा सरकार ने एक ऐपिक्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई है हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी जो लोग बनाएंगे उसको फाइनेंस उसके द्वारा किया जाएगा । इस प्रकार की सहायता देने का प्रबन्ध कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किया जा रहा है ।

चौधरी दल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो 100 वर्ग गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे वे गवर्नमेंट लैन्ड से दिए जाएंगे या पंचायत की शामलात लैन्ड दिये दिए जाएंगे?

श्री बनारसी दास गुप्ता : जहां से भी जमीन अवेलेबल हो सकती है ली जाएगी । अगर एक्वायर करने की जरूरत पड़ी तो वह भी की जाएगी ।

श्री गिरिश चन्द जोशी : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो लो इन्कम ग्रुप के हैं या जो बैकवर्ड हैं उनके लिए सरकार कोई मकान बना रही है?

श्री बनारसी दास : जी हां ।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की प्रेजेन्ट के तहत इकोनोमिकली बेकवर्ड और बिल्कुल डाउन ट्रोडन के लिए मकान की कोई योजना है?

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय वीकर सैक्शन के लिए हरियाणा प्रर्देश की सरकार का आवास बोर्ड मकान बना कर दे रहा है । अभी पिछले दिनों 500 मकान फरीदाबाद में दिए हैं । इसके अलावा जहां-जहां पर इन्डस्ट्रीयल एरिया है औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर यह योजना जारी है । कोशिश की जाती है कि जो ऐसे वीकर सैक्सन के लोग हैं उन्हें मकानों की सहूलियत बहुत जल्दी दी जाए ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 100 वर्ग गज के प्लाट्स देने की स्कीम तो केन्द्रीय सरकार को है तो क्या प्रान्तीय सरकार गांवों में भी इस प्रकार के लोगों को कोई ऐसी सहूलियत देगी?

श्री बनारसी दास गुप्ता : प्रदेश सरकार का भी कंट्रीब्युशन होगा, उनकी तो उसमें सहायता है । श्री अमर सिंह रू जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि 100 वर्ग गज के

प्लाट्स देहातों के अन्दर दिए जाएंगे का इसी प्रकार से शहरों के लिए भी कोई योजना है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय आवास बोर्ड जो कालोनोज बना रहा है उसमें से ही 10 परसेन्ट मकान हरिजनों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे और वही उन्हें दिए जाएंगे ।

Employment in the Private Sector

***588. Shri Behari Lal Balmiki :** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) the steps taken by the Government to generate employment in the private sector;

(b) the total number of persons who got employment in private sector during the period from 1st May, 1968 to 31st December, 1973 ; and

(c) the steps taken by the Government to provide jobs in the private sector to the unemployed persons in the State ?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal)

(a) The Government cannot take any direct action to generate employment in the private sector. The investments made in the public sector automatically lead to generation of employment opportunities in the private sector.

(b) According to the Employment Market Information Programme the employment in the private sector has increased from 86059 at the end of June, 1968, to

1,25,208 at the end of June, 1973, thereby providing additional employment to 39149 persons.

(c) As stated under (a) above.

Permission to Carry School going children or students by the Haryana Roadways Buses free of Charge

***603 Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Government has issued instructions to the Transport Authority in the State directing it to carry school going children or students by the Haryana Roadways buses free of charge from their residence to the school ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether it has come to the notice of the Government that certain conductors/drivers of the buses do not comply with the said instructions ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken against them ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative whether there is any proposal under consideration of the Government to give transport facility to the 'students as referred to in part (a) above ?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :
विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

Statement

(a) Children are not carried from their residences but instructions are as follows to give them lift from roadside -

(i) All girl students upto 10th Class and all boy students upto 8th class provided the distance of the school from the place of their boarding in the bus exceeds one mile.

(ii) All students (boys and girls) studying upto 4th class shall be carried free provided the distance of school from the place of their boarding in the bus exceeds half a mile.

(iii) The concession of free travelling will be available within a distance of five miles from their residence only and not more.

(iv) The students will, however, have to carry identity slips only from their headmaster/headmistresses to show that they are bonafide students.

(v) The children shall be provided standing place upto 25% of the seating capacity in case no seat is available in the bus.

(vi) This concession shall, however, not be admissible in the Local services in the cities.

(b) The department has received occasional complaints that at time' some drivers and conductors do not pick up school going children and students. On receipts of these complaints the supervisory stall has been instructed to carry out special checkings to ensure that the school going children and students are given adequate accomodation.

(c) Does not arise.

Rohtak Medical College Hospital

***732. Shri K. N. Gulati :** Will the Minister for industries be pleased to state—

(a) the total amount so far spent out of the amount allotted for

the Rohtak Medical College Hospital during the year 1973-74 ; and

(b) the reasons for the unspent amount, if any ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :
(फ) 104. 84 लाख की बजट अलाटमेंट में से नवम्बर, 1973 तक 63.29 लाख खर्च हुआ ह ।

(ख) शेष राशि में से अधिकतर साजौ-सामान फर्नीचर तथा दवाईयो इत्यादि के लिए है । इनकी खरीद के लिए आर्डर दिए जा चुके । या दिए जा रहे हैं । आशा कि जाती है कि चालू वित्तीय के अन्त तक अधिकतर बची हुई धन-राशि खर्च हो जाएगी ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि इस कालेज में इस साल कितने स्टुडैन्टसु ने ऐडमिशन के लिये ऐप्लाई किया और उनमें से कितनों को ऐडमिशन मिली?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, यह कालेज की बात नहीं है, अस्पताल को रात है ।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदया यह बताने क़रुाई कृपा करेगी कि दे । अमाउन्ट इन्होने अपने जबाब मे बतायी है, उसमें से कितनी अमाउन्ट मैडीसन्ट पर खर्च हुई है और कितनी स्टाफ पर खर्च हुई है?

श्रीमती शारदा रानी : इसके लिये अलग से नोटिस दे दे, हम बता देगे

Mr. Speaker : The Question Hour is over.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा—हरियाणा म्यूनिसिपल कामन लैन्डज्

रैगुलेशन बिल, 1971 सम्बन्धी

15.00 बजे

Mr. Speaker : I will read out the following message received from the Governor of Haryana returning the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1971 :-

Message from the Governor

"I, B.N. Chakravarty, Governor of Haryana; hereby return the Haryana Municipal Common lands (Regulation) Bill, 1971, for reconsideration by the House with a view to excluding from the purview thereof 'hose Shamlat Deh lands which have been treated as evacuee report under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (Central Act 31 of 1950) or arc of

composite nature in which evacuee and non-evacuee shares have not yet been separated.

Three copies of the Bill, in original, alongwith the direction of the President of India in original, are sent herewith."

I also read out the following directive dated the 13th December, 1973 from the President of India to the Governor of Haryana, Chandigarh :—

Directive by the President of 'India

"I, Varahagiri Venkata Giri, President of India, having considered the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1971, which was reserved for my consideration under the provisions of article 31A of the Constitution of India, do hereby direct, in pursuance of the Provision to article 201 of the Constitution, that the Bill be returned to the House of the Legislature of the State of Haryana with a message that the House will reconsider the provisions of the Bill with a view to excluding from the purview thereof those Shamlat Deh lands which have been treated as evacuee property under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (Central Act 31 of 1950) or are of composite nature in which evacuee and non-evacuee shares have not yet been separated."

The House will now resume discussion on the Budget. Shri K.N. Gulati may please resume his speech.

वर्ष 1974-75 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री के० एन० गुलाटी (फरीदाबाद) माननीय स्पीकर साहब, कल भी मैंने आपकी मार्फत सदन में यह अर्ज की थी कि

हमारे सामने जो बजट पेश किया गया है, वह निहायत ही सूझ-बूझ से बनाया गया है और जनता और सरकार, दोनों के हितों को देखकर बनाया गया है । इस से मुझे बहुत खुशी है. कल मैंने कुछ प्वायटस आपकी मार्फत सरकार से अर्ज किये थे और जो कुछ प्वायट्स रह गये हैं उनके लिये मैं सिर्फ 5- 7 मिनट ही हाउस के लगा ।

स्पीकर साहब, मैंने कल जब छोड़ा तो मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा था । मैं आपकी मार्फत यह अर्ज करना चाहता हूँ कि बजट हमेशा ही जनता और सरकार के हितों के लिये खर्च होते हैं । जनरल-ऐडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित मेरी अर्ज यह है कि हरियाणा के कोने-कोने में हालात देख कर तमाम जनता को सोशल, मोरल और लीगल जस्टिस मिलना चाहिए । जनता के अन्दर आम लोग और सरकारी ऐम्पलाईज भी आ जाते हैं । मैं आप की मार्फत कुछ उदाहरण इस बारे में देना चाहता है हमारे यह फरीदाबाद में एक ऐक्स सैनिक सोसायटी बनी सैं जिसके 2000 मँबर तै और जिसने लगभग 30 लाख रुपया इक्ठ्ठा कर लिया हैं । उसके खर्च करने के लिये कोई खास प्लानिंग नहीं है । इस सिलसिले में पुलिस-स्टेशन में कम्प्लेंट भी लाज्ड है लेकिन उसकी कोई इन्कवायरी नहीं होती आप देखिये 2000 मँम्बर इस की वजह से परेशान हैं । मैं आपकी मार्फत हाऊस को याद दिलाना चाहता हूँ कि वहां पर फिर वही वाक्या होगा जैसे पहले हुआ था कि जो एक गुरु गोबिन्द सिंह मैडीकल कालेज फरीदाबाद

में खुला था, उसमें फ्राड होता था, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और वह मामला पार्लियामेंट तक पहुंचा । इस सोसाइटी के 2,000 मैम्बरान ठीक कालेज वाले किस्से की तरह परेशान है । उन्हें यह पता नहीं है कि उनका 30 लाख रुपया कैसे और कहां खर्च होगा ।

मेरी सरकार से यह अर्ज है कि इ सकी इन्कवायरी होने चाहिए । एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं 12/13- 1 - 1974 को मैं फरीदाबामे में था । वहां पर दिल्ली बोर्डर के पास कुछ बिजनैसमैन 12- 13 साल से बसे हुए हैं उनको छः घंटे का नोटिस देकर उठा दिया गया । यह बात ठीक है कि इलाका साफ होना चाहिए और मैं इस चीज की दाद देता हूं कि इलाके को सुन्दर बनाना चाहिए लेकिन एक इन्सान की इस तरह से नहीं उठाना चाहिए । हरेक इन्सान को सोशल, मोरल और लीगल जस्टिस मिलना चाहिए । मेरे विचार में उन लोगों को सफीशीयैन्ट टाईम का नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि वे अपना सामान उठाने का कुछ प्रबन्ध कर पाते । जो उन्हें सिर्फ छः घंटे का नोटिस देकर सामान उठवा दिया गया है, यह उनके साथ बहुत बड़ी बे-इन्साफी है, इसकी भी जांच की जाये

स्पीकर साहब, ऐम्पलाईज भी आखिर इन्सान हैं टैम्पोरेरी ऐम्पलाईज जो दस-दस या बारह-बारह साल तक काम करते हैं, उनको रैगुलर किया जाना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मैं उदाहरण देना चाहता हूं वहा पर ऐम्पलाईज

काफी देर तक टैम्पोरेरी लगे रहते हैं लेकिन उनको रैगुलर नहीं किया जाता । मैं यह चाहूंगा कि जनरल-ऐडमिनिस्ट्रेशन में इस तरफ भी ध्यान दिया जाये कि सब टैम्पोरेरी ऐम्पलाईज को एक निश्चित वक्त के बाद रैगुलर कर दिया जाये ।

स्पीकर साहब, मैं लेबर माईन्डिड आदमी हूँ मैं यह भी चाहता हूँ कि स्टाफ को जहां-जहां पर तबदीली होता है, सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि उनको वहां पर रहने के लिये क्वार्टर मुहैया हों स्पीकर साहब, ट्रान्सफर के समय ऐम्पलाईज इसलिये तकलीफ महमूस करते हैं क्योंकि वहां पर उनको क्वार्टर मुहैया नहीं होते और उन्हें नयी जगह पर बहुत किराया देना पड़ता है । अगर सरकार ऐसा प्रबन्ध कर दे तो मेरे ख्यात में कोई भी ऐम्पलाईज ट्रान्सफर होने में हिचकिचायेगी नहीं और बड़ी खुशी से आपके हुक्म का पालन करेगा स्पीकर साहब, उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ फरीदाबाद में काम्प्लैक्स का ऐडमिनिस्ट्रेशन है मेरा विचार यह है कि उसके तमाम ऐम्पलाईज को हाउस-रेंट मिलना चाहिए अब क्या होता है, आधे ऐम्पलाईज को तो हाउस-रेंट मिलता है और आधे ऐम्पलाईज को नहीं मिलता । ऐसी बातें सरकार की नौलेज में होनी चाहिए और सरकार की जनरल-ऐडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान इस बात को देखें कि हरेक इन्सान को उसका हक मिल जाये स्पीकर साहब, मैं क्वैश्चन आवर में अपने एक सवाल को इसलिये क्लियर नहीं कर सका क्योंकि समय बहुत थोड़ा होता है और हम त्रोग एक ही सप्लीमेंट्री कर

सकते हैं उसमें मेरा कहने का मतलब यह था कि फरीदाबाद में तीन पुलिस स्टेशन हैं । बल्लभगढ़, 5-सैक्टर और 15 सैक्टर बल्लभगढ़ के साथ एक कोची गांव है । वहां के लोगों को कम्प्लेन्ट लाज करवाने के लिये 15-सैक्टर जाना पड़ता है । 15-सैक्टर के साथ ही एक मयस्सर गांव है वहां के लोगों को बल्लभगढ़ जाना पड़ता है इसी तरह से एक गांव के साथ सेक्टर-5 का थाना लगता है लेकिन उनको दूर जाना पड़ता है सरकार को इस तरह से प्रबन्ध करना चाहिये कि कम्प्लेन्ट को नजदीक से नजदीक जाना पड़े गांवों को नजदीक के पुलिस-स्टेशनों से अटैच करना चाहिए आज बड़ी महंगाई का जमाना है, लोगों को बड़ी हार्डशिप्स हैं आज इन्सान को अपनी कम्प्लेन्ट लाज करवाने के लिये थोड़े से टाइम में पुलिस-स्टेशन पहुंच जाना चाहिए इसके अलावा एक और अर्ज करना चाहता हूं । जुडीशियल कोर्ट बल्लभगढ़ में नहीं है । 5-सैक्टर एन0 आई0 टी 0 फरीदाबाद के लोगों को जुडीशियल केसिज के लिये गुड़ गांवो भागना पड़ता है मेरी अर्ज यह है कि वहां के लोगों को जुडीशियल कोर्ट बल्लभगढ़ में मिलनी चाहिए यह एक इन्साफ की बात है और लोगो को यह सहूलियत जरूरी मिलनी चाहिए इसी तरह से एक और केस के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं एक अजन दास नाम का व्यक्ति है जिसका लेबर-कोर्ट का फैसला 31- 3- 1970 को मिला और 2210 रुपये की डिग्री उसके हक में हुई । आज तीन साल हो गये है लेकिन उसको वह पैसा नहीं मिलता । मेरा ख्याल है कि वह सैंकडों लैटर डिपार्टमेंट को लिख चुका है लेकिन आज तक

उसको पैसे नहीं मिले । डी 0सी0 तहसीलदार और लेबर-कमिशनर बगैरा से चिटठी आ जाती है लेकिन उस ले-मैन को पैसा नहीं मिलता । वह बेचारा रोटी कमाने जाये या आपके दफतरो में धक्के खाता फिरे मैं यह चाहता हूँ कि गरीब आदमी की अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है या उसका मसला कोर्ट में है तो सरकार उसकी मदद करे

इसी तरह से स्पीकर साहब. मेरी नौलेज में एक बात आयी है चंडीगढ में जो कोओप्रोटैव स्टोर है, वह हरियाणा सरकार के अन्डर है वहां पर एक ऐ 0जी 0 ऐम0, बी0 ऐफ0 लाम्बा दो साल से नौकरी में था जब वह यहां आया तो 3,000 रुपये का घाटा था लेकिन अब उसने स्टोर को 21,000 रुपये का फायदा दिखाया है । उसके अगेन्सट कोई कम्पलेन्ट नहीं थी लेकिन दो साल नौकरी के बावजूद उसको सीधे टर्मिनेशन के आर्डर दिये गये. उसको कोई शो-काज-नोटिस या कोई दूसरे इल्जामों का चिह्ना नहीं दिया गया मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसी बातों की तरफ ध्यान दे । किसी भी ऐम्पलाई को बगेर नोटिस के, जबकि उसकी दो साल को सर्विस हो, इस तरह से नहीं निकालना चाहिए । यदि कोई पार्टीकुलर शिकायत हो तो आप उसे वार्निंग दे सकते हैं या कोई दूसरी सजा हो सकती है लेकिन इस तरह से टर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए । (घंटी)

स्पीकर साहब, मैं दो-तीन मिनट और लूंगा । स्पीकर साहब मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अन्दर सेल्ज टैक्स कम

होना चाहिए वह दिल्ली के बराबर होना चाहिए । पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स जो इन्डस्ट्री है और जो मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में है उन पर सेल्ज टैक्स बिलकुल नहीं लगना चाहिए, फरीदाबाद में प्रोफेशनल टैक्स माफ होना चाहिए मैं सरकार को एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि सारे टैक्सों को थोड़ा करके उनकी पूरी रिकवरी होनी चाहिए । स्माल सेविंग इक्वटा किया जाता है तो उसको इक्वटा करने में तमाम अफसरान लग जाते हैं और फिर स्माल सेविंग वापिस भी करना पड़ता है सरकार जो वाहे वह करती है और हम भी सरकार के साथ है । लेकिन हम यह नहीं चाहते कि सरकार का नुकसान हो । मैं प्वांएट आउट करना चाहता हूँ कि सारे अफसरान स्माल सेविंग को इक्वटा करने में लग जाते हैं और फिर उसको वापिस भी करना पड़ता है जिनसे स्माल सेविंग ली जाती है उनका लिहाज भी करना पड़ता है, वे टैक्स इवेजन भी करते हैं तो भी उनके साथ नर्मी का व्यवहार किया जाता है इसलिए स्माल सेविंग की प्रैक्टिस को खत्म किया जाए और सरकारी अफसरान को हरियाणा के अन्दर जो टैक्सिज हैं उनको इक्वटा करने में लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इक्वटा हो सके और सरकार के खजाने में जमा हो सके । स्पीकर साहव, बजट के अन्दर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो डी0ए0 बढ़ाने का आश्वासन इन-राइटिंग दिया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए । फरीदाबाद के अन्दर एक मिल्क प्लांट का उद्घाटन 12- 1- 1974 को होना था । लेकिन पता नहीं क्यों कैंम्बिल कर दिया गया मेरी यह रिक्वैस्ट है कि फरीदाबाद के

लिए जो मिल्क प्लांट लगाने की स्कीम है उसको जल्द से जल स्टार्ट किया जाए स्पीकर साहब, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं । हरियाणा सरकार जो सीमेंट सरकारी काम के लिए देती है उसको ठेकेदार पूल कर लेते हैं, वह ब्लैक में बेची जाती है और इससे करप्शन बढ़ता है मैं चाहूंगा कि सरकारी अफसरान सरपराइज चौक करें । लोयर स्टाफ को उस सरपराइज चौक की कोई इतला नहीं होनी चाहिए । अफसरान को देखना चाहिए कि कहां बेइमानी हो रही है इस बेइमानी में चाहे छोटा अफसर हो, चाहे कोई बड़ा अफसर हो उसको सजा मिलनी चाहिए । फरीदाबाद के अन्दर जो सरकारी सीमेंट होता है उसका पचास प्रतिशत मार्किट में आ जाता है सरकार इसको चौक करे ।

स्पीकर साहब, मैं एक अच्छा सुझाव सरकार को और देना चाहता हूं । मुझे तो वह सुझाव अच्छा लगता है, पता नहीं सरकार उसको पसन्द करती है या नहीं । वह सुझाव यह है कि सरकार एक सेंटर खोले जिसमें सोशल और नेशनल प्रिचिंग मिले । उस सेंटर में अफसरान और मिनिस्टर साहिबान और दूसरे लोग भी जाएं । वहा पर लोगो को बताया जाए कि ला एंड आर्डर कैसे रखा जाए, हरियाणा के अन्दर क्या हो रहा है? इस प्रकार नेशनल और सोशल प्रिचिंग से लोगों में कुछ सुधार आएगा और हरियाणा के अन्दर से करप्शन खत्म होगी स्पीकर साहब, मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से बड़े मीठे शब्दों में, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है, कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद में वड़े गरीब लोग

रहुते हैं, एन० आई० टी ० फरीदाबाद लेबर का इलाका है । आज एन ० आई० टी० पर हाउस टैक्स लगने जा रहा है नया टैक्स लगा ले कोई हर्ज नहीं क्योंकि डिवैलपमेंट के काम के लिए पैसा चाहिए लेकिन वहां पर 1972— 73 और 1973— 74 पिछले दो साल का भी हाउस टैक्स लगने जा रहा है यह बहुत ज्यादाती की बात है वहां के लोग बहुत गरीब है । मैं पुरजोर दरखास्त करना चाहता बात कि पिछले दो साल का हाउस टैक्स न लगाया जाए वहां पर पावर कट है, मजदूर बेकार हैं, वहां पर लें—आफ होने जा रहा है, दुकानदारों का बिजनेस ठप्प हो चुका है । स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हू कि उनसे दो साल का पिछला हाउस टैक्स न लिया जाए एन ० आई० टी ० से 1974—75 से हाउस टैक्स बेशक ले लिया जाए लेकिन 1972—73 और 1973— 74 का हाउस टैक्स न लिया जाए । इतनी कह कर मैं खत्म करता हूं धन्यवाद ।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :
माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से सन् 1974— 75 के बजट पर बहस चल रही है और इस से पूर्व तीन दिन तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी इस सदन में चर्चा चलती रही । अध्यक्ष महोदय, के अभिभाषण पर भी और बजट पर भी मेरे विपक्षी दल के भाइयों ने बहुत कुछ बातें कहीं कहनी भी चाहिए, उनका अधिकार है क्योंकि आप जानते हैं, डैमोक्रेटिक सैट—अप में जनतान्त्रिक प्रशासन में जितना महत्व सतारूढ दल का होता है

इतना ही महत्व विपक्षी दल का भी होता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आप यह भी सुनते होंगे कि यह सत्ता, यद्यु हकूमत एक मदमत्त हाथी को तरह होती है । यदि इस पर कोई विपक्षी दल था विरोधी दल का अंकुश न हो तो इस मदमस्त हाथी का पता नहीं कि वह सत्ता के मद में क्या कर बैठे और उसका क्या परिणाम निकले मेरे भाईयों ने जो नुक्ताचीनी की इसका मुझे कोई गिला नहीं कद, नुक्ताचीनी होनी चाहिए परन्तु स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए । जो बात सही है, जो सरकार की अच्छी बात है, सराहनीय है, तारीफ के काबिल है, उसकी सराहना को जाए । जहां कहीं त्रुटि है, कमी है उसका जिक्र किया जाए । सत्तारूढ दल का भी यह कर्तव्य बन जाता है कि इस प्रकार कोई त्रुटि या कमी बताई जाए तो उस पर गौर करे, उसको दूर करने की कोशिश करे । हमारे एक भाई चौधरी दल सिंह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे साथी हैं । हमने साथ मिल कर काम किया है आज नहीं अध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता प्राप्ति से पहले कन्धे से कन्धे मिलाकर काम किया है । उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर एक बात कही कि प्रति वर्ष एक ही बात को दोहराया जाता है कि सरकार ने हर गांव में बिजली पहुंचा दी, सरकार ने यह कर दिया वह कर दिया । अध्यक्ष महोदय मैं ऐसा समझता हूँ कि तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर हरियाण ही पहला प्रदेश है जिसने शत-प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिकेशन की है । यह एक ऐतिहासिक बात है ओर इतनी बड़ी उपलब्धि का इतनी बड़ी अचीवमेंट का यदि प्रतिवर्ष जिक्र किया जाए तो यह कोई अनुचित बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जो ऐतिहासिक बात होती है, बहुत

बडी बात होती है उनको दोहराया जाता है, उन पर गर्व होता हूँ, उन पर फ स होता है । आज से हजारों वर्ष पहले राम ने रावण पर विजय पाई लेकिन आज तक राम लीला के द्वारा प्रतिवर्ष दोहरा कर उसका जिक्र किया जाता है । आज से हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का सन्देश दिया तो वह आज तक दोहराया जाता है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो अच्छे काम हों, सराहनीय काम हों, अनुकरणीय काम हो उनको यदि प्रति वर्ष दोहराया जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है मैं अपने भाई चौधरी दल सिंह से कहूंगा कि वे अपने भाषण को भी देखे उनका भी प्रतिवर्ग का भाषण एक ही होता है और वह होता है बिजली बोर्ड के ऊपर हमला । अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पुरानी बातें अपने साथी को याद दिलाना चाहता हूँ एक समय था, हम दोनों चौधरी दल सिंह भी और मैं भी, जींद स्टेट के रहने वाले थे, हम प्रजा मंडल के अन्दर दोनों साथ काम करते थे । यह बात चौधरी दल सिंह को याद होगी । जो पहले जिला दादरी कहलाता था और पिछले दिनों महेन्द्रगढ जिले का एक हिस्सा था और आज वह भिवानी जिले में है, एक बार प्रजा मण्डल के अधिकारी के नाते हम दोनों ने बाड़डा से लेकर बोन्द तक उस सारे इलाके का पैदल दौरा किया चौधरी दल सिंह जी को याद होगा कि उस वक्त उस इलाके को स्थिति कैसी थी? वह कैसा इलाका था, रेगिस्तानी इलाका, मरुभूमि का इलाका वहां पर न कोई सड़क थी और न कोई रास्ता था अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई को तो शायद पता है कि उस समय सड़कें तो कहां, कोई

पगडन्डी भी नहीं होती थी, केवल ऊंटों के जाने के रास्ते होते थे और अगर आंधी का एक रेला आ जाए तो वह पगडन्डी भी गायब हो जाती थी जिसकी वजह से यह भी पता नहीं चलता था कि इस गांव से उस गांव तक का रास्ता कौन सा है जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है उसकी तो एक बूंद भी नहीं मिलती थी । उस वक्त ऐसी हालत थी कि उस इलाके में उड़ते काग की आंख निकल जाती थी लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता था। उस वक्त किसान वर्षा की इन्तजार में आसमान की तरफ आंख फाड़े देखता रहता था कि कब आसमान से पानी बरसे और वह हल लेकर खेत की तरफ जाए । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आसमान का कलेजा नहीं पसीजता था अर्थात् आसमान से पानी नहीं गिरता था बल्कि किसान की आंख में पानी आ जाता था । यह तो हालत थी उस इलाके की । यह हाल इन्होंने अपनी आंख से देखा था । हमारे एक महाशय मन्शा राम थे जो कि प्रजामण्डल के कार्यकर्ता थे और आज भी वे जीवित हैं । जब हम एक गांव में प्रचार के लिये गये तो वहां पर कुछ लोग हुक्के पर बैठ कर बातें कर रहे थे, आजादी की बात कर रहे थे उन्होंने महाशय मन्शाराम से पूछा कि अगर यह आजादी आ गयी, तो हमें क्या मिलेगा? गांव का किसान भोला होता है । उसने भोलेपन में यह बात पूछी । उस वक्त उनकी बातें सुन कर महाशय मन्शा राम जी ने जवाब दिया कि ताऊ अगर आजादी आ गई तो तेरी इस छान में बिजली का लड्डू लगवा दूंगा । यह बात मुझे याद है कि महाशय मन्शा राम जी ने आज से 30 35 साल पहले मेरी मौजूदगी में यह बात कही थी । आज से दो

तीन साल पहले बाढडा के जिम इलाके में हम दोनों ने दोरा किया था, उसके अन्दर बिजली का सब-स्टेशन बना जिसका उद्घाटन करने के लिये मुख्य मंत्री महोदय जा रहे थे, साथ में मैं भी गया । तो मैंने रास्ते में मुख्यमंत्री महोदय को महाशय मन्शा राम वाली वह कथा बताई कि आज हम उस इलाके में बिजली देने जा रहे हैं जहां यह चर्चा चली थी । स्पीकर साहब, जब हम उस गांव में पहुंचे तो महाशय मन्शा राम जी भी सौभाग्य से उस जलसे में पहुंच गए थे । हमने उनको बुलाया और अपने पास बैठाया और कहा कि महाशय जो आज से 30 साल पहले आपने जो भोले किसान को जवाब दिया था, जो भविष्यबाणी की थी, आप देखते हैं कि आपका वह स्वप्न आज साकार हो गया है और बाढडा जैसे रेगिस्तानी इलाके में आज घर-घर में बिजली के लड्डू जल रहे हैं (तालियां) अध्यक्ष महोदय में आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाऊं कि कल बजट के ऊपर बोलते हुए मेरे दोस्त ने एक बात और कही थी कि 90 परसेंट रुपया भिवानी के इलाके में मुख्यमंत्री खर्च करते हैं । चौधरी दल सिंह जी को तो इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिये । (व्यवधान) ठीक है अगर नहरो के ऊपर भी रुपया खर्च करते हैं तो भी कोई बुराई की बजट नहीं है । स्पीकर साहब, मैं भूतपूर्व जींद राज्य का रहने वाला हूं उस समय मैं कैद भी जाया करता था और दादरी के इलाके में तो रहता ही था । अध्यक्ष महोदय, आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा क्योंकि आपके वह पड़ोस का इलाका है कि वहां पर ऐसे-ऐसे गांव थे जहां लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता

था और 15- 15 कोस तक पीने का पानी नहीं मित्रता था । लोग छोटे-छोटे कुण्ड बना लेते थे और फिर उनमें बारिश की एक-एक बूंद को जमा कर लेते थे और फिर उन कुण्डो में से एक-एक गड़वी या लोटा पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझाया करते थे । रोहतक वाले लोग भी यहां बैठे हुए हैं, इनकी काफी रिश्तेदारी उन इलाकों में हैं । ये भी शायद जानते होंगे कि वहा यदि कोई मेहमान आ । जाते थे तो उनको दूध तो मिल जाता था लेकिन पीने के लिये पानी नही मिलता था यह हालत थी उस इलाके की । आप अब नजर उठाकर देखे' कि उस इलाके के लोगों को पीने का पानी मिला है और लोगों ने यह महसूस किया है कि 25 साल के बाद आज उन्होंने असली स्वाधीनता हासिल की है अगर 25 साल के बाद उस इलाके के किसानों के भाग्य ने पलटा खाया है तो चौधरी दल सिंह के पेट में दर्द क्यों होता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती । हम जो जींद स्टेट के रहने वाले है, दादरी में भी कांग्रेस का काम करते थे और जीद भी जाया करते थे । तो वहां पर हमारा मिलाप एक रोज चौधरी दल सिंह से हुआ । उस वक्त ये अपने खेत में खांड खोद रहे थे तो हमने इनसे कहा कि आप नौजवान आदमी हो, आओ हमारे साथ प्रजामंडल में मिलकर जन सेवा का काम करो । स्पीकर साहब मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया और उसी रात को इनके ग्राम रामराय में एक जलसा हमने किया । उस सारे गांव में सरकार के डर से उस जलसे की अध्यक्षता करने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं था । तो उस वक्त चौधरी दलसिंह जी ने उस

जलसे की अध्यक्षता की । स्पीकर साहब, इनको या पता है कि जितना पानी जींद में बहता है उतना तोशाम, लोहारू और सिवानी में नहीं है । स्पीकर साहब, आज स्वाधीनता के बाद जो यह काम हुए हैं, इन्हें लोग महसूस करते हैं अध्यक्ष महोदय, हम तो सदा ही इन इलाकों के लिए लड़ते आये हैं । 1957 के बाद जिस वक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, उस वक्त हमारी प्रदेश कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई गई । आपको भी याद होगा सम्भवतः आप भी उस कमेटी के मँबर थे । उस समय सरदार प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे और यह मीटिंग इस उद्देश्य से बुलाई गई थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया हे, उस पर विचार किया जाए । उस पर बोलते हुए मैंने एक धन्टे तक अपनी दलील दी थी कि हमें इस पंचवर्षीय योजना से विरोध नहीं हे, जो प्रोवीजन इसमें किए गए हैं, उससे हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन हम यह चाहते हैं कि पंजाब के अन्दर रीजनल इम्बैलेन्स, क्षेत्रीय विषमता जो है, उसको दूर किया जाए और हरियाणा रीजन के विकास पर भी कुछ खर्च किया जाये यह जो 80-90 परसेंट पैसा लुधियाना जालन्धर और अमृतसर पर खर्चा हो रहा है, यह न होकर पंचवर्षीय योजना में रीजनल एलोकेशन की जाए मैंने यह प्वायंट वहां पर रेज किया, आज प्रताप सिंह कैरो स्वर्ग में हैं इसनिए उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैंने यह ज्वायंट इसलिये उठाया । कि यहां इस प्रकार की चर्चा चल पडी । मेरी इ स आलोचना की वजह से उस समय के चीफ मिनिस्टर महोदय मुझ से नाराज हुए तथा एक

और साहब जो उस वक्त मिनिस्टर थे, स्पीकर साहब, शायद वह आपके गांव के रहने वाले थे

उन्होंने भी बुरा मनाया कि मैंने इस प्रकार की नुक्ताचीनी क्यों की । हम कहते थे कि यह जो क्षेत्रीय विषमता है, यह मिटनी चाहिये । एक इलाके में नहर हों, इंडस्ट्री हों और हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों और दूसरे इलाके में पीने का पानी तक न मिले तो हम ऐसी विषमता को दूर करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय मौजूदा सरकार से पहले किसी सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने कि लिए इतने बड़े-बड़े काम नहीं किये । तो मैं यह कह सकता हूं कि हरियाणा बनने के बाद इस सरकार ने बड़ी भारी प्रगति की है बरसों से चली आ रही इस विषमता को दूर किया है स्पीकर साहब, हमें तो इन बातों को देखकर खुश होना चाहिए और चौधरी दल सिंह जी को यह भी पता होना चाहिए कि काम जीद में भी हुए है केबल भिवानी, तोशाम और सिवानी में ही नहीं हुए. अगर आप जीद में गोहाना रोड पर चलें जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम जीद में नहर बल्कि चण्डीगढ़ में पहुंच गये हैं चौधरी दल सिंह जी आप को याद होगा कि आप जीन्द के टूटे हुए हस्पताल में बीमार पड़े हुए थे । उस टूटे हुए हस्पताल के एक कमरे में आप लेटे हुये थे और उस वक्त मैं आपको मिलने के लिये गया था । तो मैं पुछना चाहता हूं कि वह हस्पताल क्या था और आज का हस्पताल क्या है? अकेली भिवानी

में काम नहीं हुआ है, काम तो जीन्द में भी हुआ है, काम तो करनाल में भी हुआ है, काम तो अम्बाला में भी हुआ है, रोहतक में भी हुआ है और गुड़गांव जिला के अन्दर भी हुआ है हरियाणा के अन्दर तो आल राउन्ड प्रोग्रैस हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जब मैं आपके स्थान पर अर्थात् विधान सभा का अध्यक्ष था तो मुझे एक रोज मोरनी हिल्ज जाने का मौका मिला । हम चर्चा सुनते थे कि मोरनी का हिल स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है जब वहां के लोगों को पता लगा कि विधान सभा के अध्यक्ष यहां आये हुए हैं तो गांव के लोग वहां के स्कूल के अन्दर इक्ठे हो गये । अध्यक्ष महोदय, जितना गांव था वह सब स्कूल के अन्दर इक्ठे हो गया । उन लोगों ने बतलाया कि पहले उनकी क्या हालत थी? अध्यक्ष महोदय, वह मोरनी गांव एक ऐसा गांव है कि जहां चौधरी बन्सी लाल के मुख्य मन्त्री बनने से पहले कोई नायब तहसीलदार भी नहीं गया था । लेकिन चौधरी वसी लाल 5- 7 बार मोरनी गए । उस गांव की हालत क्या थी? वहां पीने का पानी ' सैकड़ों फुट नीचे खड्ड से लाना पड़ता था हमारे इलाके में तो मैदान में चलकर ही पानी लाना पड़ता था लेकिन वहां तो नीचे खड्ड से जाकर पानी लाना पड़ता था, वे वहां से पानी लाते थे और अपनी प्यास बुझाते थे । अध्यक्ष महोदय, आज आप वहां वाकर देखें घर-घर में पानी के नलके लगे हुए हैं । पहले क्या होता था कि बारिश के दिनों में उस

गांव का संबंध दूसरे मैदानी इलाकों से टूट जाता था । अम्बाला के अन्दर जो चीज जिस भाव पर बिकती थी, मोरनी में वह उससे डेढ़ गुना ज्यादा दामों पर बिकती थी । आज वहां हस्पताल हैं, वहा रैस्ट हाऊस है और लोगों को काम देने के लिए वहां एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला हुआ है जहां एरिया और कालीन बनते हैं । आज वहां अम्बाला के भ पर चीजों की सप्लाई की जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सरकार बर्दाशत करती है । मोरनी हिल रुपए लोगों ने मुझे बतलाया कि हमारी सात पीढ़ियां भी चौधरी बंसी लाल के ऋण से मुक्त नहीं हो सकेंगी जिन्होंने हमें पशु की जिन्दगी से उठा कर इन्सान की जिन्दगी दी है । मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं कि जो हर समय भिवानी की बात करते हैं कि गंगा के पास जोखादर का इलाका है, अगर आप इस इल हल में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक-एक गांव का दौरा किया है और इस पूरे इलाके के अन्दर जहां न कोई सड़क थी, न रास्ता था और न कोई स्कूल था । कई गांव तो ऐसे थे कि जिनकी किस्मत का कुछ पता ही नहीं होता था । जमना का बहाव कुछ इधर हो गया तो कुछ गांव यू ० पी ० में चले गये और अगर बहाव उधर हो गया तो हरियाणा में आ जाते थे । उस समय न तो हरियाणा वाले उनके लिये कुछ काम करते थे और न ही यू ० पी ० वाले कोई काम करते थे । लेकिन अब हमारी हरियाणा सरकार ने वहां सड़कें बनाई हैं, स्कूल खोले हैं, रास्ते बनाए हैं तथा और भी कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं । हमने यह नहीं सोचा कि ये गांव यू ० पी ० में

चले जायेंगे बल्कि यह सोचा कि यू ० की ० में चले. जायेंगे तो क्या बात है आखिर यह भी तो लोग हैं, इन्सान हैं, इनको भी तो हमने सुविधा देनी है । तो यह भलाई की बात है । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जब से यह सरकार बनी है यानी 1968 से तभी से ये सब विकास के कार्य हुए हैं । लै से चौधरी दल सिंह जी भी कुछ समय के लिए एक सरकार में मन्त्री रह चुके हैं । यह ठीक है कि उनको समय बहुत कम मिला लेकिन वे अपनी सरकार को कायम नहीं रख पाये । बहुत सारी खामियां थीं, इनमें कुछ ऐसी वजह थी जिनकी वजह से सरकार चल नहीं सकती थी । मैं इन सब बातों को चर्चा यहां नहीं करना चाहना । मैं सिर्फ बजट के ऊपर ही यहां चर्चा करना चाहता हूं । हमारे जनसंघ के भाई चौधरी राम लात जी कल बजट पर मेल रहे थे । उन्होंने आकड़े देकर कुछ बातें कहीं । वैसे मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बजट को पढ़ कर कुछ फिगरज देखीं यह दुसरी बात है कि इन्होंने तथ्यों को अपने ढंग से पेश किया हो या तोड़ू मरोड़ कर पेश किया हो । वे बता रहे थे कि बिजली बोर्ड को रिटर्न कम हुई । मैं इनको. एक बात बतलाना चाहता हूं कि यह बिजली बोर्ड या हरियाणा सरकार कोई ऐसी संस्थाएं नहीं हैं जिनका उद्देश्य मुनाफा कम हो । अध्यक्ष महोदय, यह वैलफेयर स्टेट है, यह कल्याणकारी राज्य है, इ सने तो यह देखना है कि लोगों को सुविधा कितनी पहुंची । आमदनी की बात पर इसका कोई ध्यान नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं है । हमने देखना यह है कि बिजली बोर्ड ने कर्जा लेकर या अपने रिसोर्सिज से, अपने साधनों से जो तमाम

हरियाणा के गांव-गांव के अन्दर बिजली पहुंचाई उससे लोगों को कितना लाभ हुआ, उससे कितना फायदा हुआ? टयूबवैल्ज को बिजली मिली । अध्यक्ष महोदय, हमारे तो कई इलाके ऐसे थे जिनमें नहरों का नाम निशान तक नहीं था लेकिन जमीन में सौभाग्य से मीठा रानी था, अब उनको बिजली मिल गई तो उन्होंने नल कूपों से अपने खेतों को पानी दिया और इस प्रकार इस इलाके को तरक्की हुई । अध्यक्ष महोदय, हमने तो यह देखना सै कि किस प्रकार लोगों को फायदा हम पहुंचा सकते हैं । दूसरी बात यह कि बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े व्यापारी भी इस बात को जानते हैं कि इनवैस्टमेंट किसे कहते हैं औबसी भी व्यापार में किसी उद्योग में हर व्यापारी और हर उद्योगपति चाहे वह विडला हो, चाहे वह डालमिया हो और चाहे वह टाटा हो वह कर्जा लेकर इनवैस्टमेंट करता है, चाहे वह शेयर होल्डर्ज का पैसा हो और चाहे फाइनेशल इस्टीच्यूशंज न हो, और वे यह भी जानते हैं कि दो-चार साल तक इनवैस्टमेंट के ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलती । जो सही व्यापारी होता है, सही उद्योगपति होता है वह दो दार साल तक लाभ न होने से घबराता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, हमारे बिजली बोर्ड ने या हरियाणा सरकार ने बिजली तथा नहरों पर या और चीजों पर कर्ज कर जो इनवैस्टमेंट की है हरियाणा के अन्दर, उसका परिणाम 4- 5 साल के बाद निकलेगा । मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा में जितने भी काम हैं जैसे बिजली का फैलाव, नहरों का निकलना, एम0 आई 0 टी 0 सी0 द्वारा टयूबवैल्ज लगाना और यह जो औगमेटेशन कैनाल

निकली है इन सब से हरियाणा में खुशहाली आएगी । अगले पाव-सात साल के बाद हरियाणा तमाम हिन्दुस्तान में सबसे पहला प्रदेश होगा जो खुशहाल होगा और सम्पन्न होगा । इसलिये मैं यह कहता हूँ कि इन भाइयों को हमेशा नुकताचीनी को तरफ नहीं जाना चाहिये, इनको दिखना चाहिये कि इसका रिजल्ट कब निकलने वाला है । जो भाई यह कहते हैं कि आपने कर्जा ले लिया ओर उस कर्ज पर इतना इंटैरस्ट देना पड़ेगा कि उससे हरियाणा सरकार का दिवाला निकल जाएगा या इस विजली बोर्ड का दिवाला निकल जाएगा । मैं यहां एक बात कहूंगा कि हरियाणा सरकार या बिजली बोर्ड का तो दिवाला निकलना नहीं बल्कि उन भाइयों के दिमाग का दिवाला निकल गया है जो इस प्रकार की बातें करते हैं । तो हमारी सरकार ने हर क्षे्र के अन्दर चहुमुखी विकास किया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें विकास का काम न किया हो । मैं अपने विपक्षी भाइयों को चौलेंज करता हूँ कि वे मुझे एक चीज बताएं कि सरकार को यह चीज करनी चाहिये थी और वह की नहीं । यह दो सकता है कि काम जितना होना चाहिये था उतना न हुआ हो । क्योंकि यह जो सदियों की, हजारों वर्षों की गरीबी है इसको एक दम से दूर किया जाना सम्भव नहीं, अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है कि छूमन्त्र किया और गरीबी दूर हो गई हमारी प्रधान मन्त्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था उस पर हमारे ये भाई एतराज करते हैं कि गरीबी कैसी हटी है ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, यह बजट डिसकस हो रहा है या प्रधान मंत्री कि स्पीच डिसकस हो रही है । अगर हम अपनी स्पीच में कही प्रधान मन्त्री का नाम ले दें तो कहते हैं कि प्रधान मन्त्री का नाम ले दिया । इसलिये मैं यह अर्ज करूँगा कि इन शब्दों को एक्सपंज कर दें ।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी स्पीच में जो प्वायटस रेज किए थे ये तो उनका ही जबाब दे रहे हैं । आपने गरीबी और नहरों के बारे में जिक्र किया था । इसलिये ये बिल्कुल रैलेवंन्ट बोल रहे हैं ।

श्री बनारसी दास गुप्त : स्पीकर साहब, बजट का उद्देश्य यही होता है कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए, गरीबी दूर करने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या काम करती है प्रधान मन्त्री का उदाहरण मैंने इसलिये दिया कि पिछले दिनों उन्होंने देश के अन्दर गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था और हमारे भाई उस नारे का मजाक उड़ाते हैं । लेकिन मैं इन भाइयों को यह बना देना चाहता हूँ कि हम प्रधान मन्त्री जी के नारे को कार्यान्वित करने के लिये क्या-क्या कदम उठा रहे हैं और कौन-कौन से उठाए हैं मैं यह बात आपके सामने कहने जा रहा हूँ जैसे कि अभी खेती की और पैदावार की बातें की गई । इस संबंध में अगर मैं आंकड़े देने लगू तो कहा जाएगा कि यह तो किताबों में छपा ही हुआ है मैं किताब से बाहर के आंकड़े कहां से लाऊँ? आंकड़े तो तमाम किताब में मौजूद हैं लेकिन पता नहीं ये

भाई जो आंकड़े यहां पढ़ते हैं वे कहां से लाते हैं? या तो इन्होंने उस किताब से वह आंकड़े पढ़ने की कोशिश नहीं की किसी और किताब से पढ़ आये और या फिर अगर पढ़े हैं तो उनको इन्होंने मोड़ तोड़ कर यहां सदन में रखा है, जो बात उनको सूट करती है उसे किसी तरह घुमा फिरा कर तथ्यों को तोड़ू मोड़ कर सदन में कह देते हैं । उसी किताब के आंकड़े में यहा सदन में प्रस्तुत करता हूं ताकि चौधरी दल सिंह जी को भी हकीकत का पता चल जाये अगर उनको उसका पता नहीं जसे कि उन्होंने कहा है कि अनाज की पैदावार बढ़ने की बजाये नीचे गिरी है । पता नहीं वह किस स्कूल से यह आंकड़े पढ़ आये कि पैदावार गिरी है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उसी किताब के आंकड़े बताना चाहता हूं । जैसे कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बड़े विस्तार के साथ यहां पर बताया था कि हरियाणा में काफी इलाके ऐसे हैं कि अगर वहाँ पर किसी साल सौभाग्य से बारिश ज्यादा हो जाये तो चने की पैदावार खूब हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और आपको याद होगा कि नबिये के साल में जब हमारा कोई चीज नह थी न नहर थीं, न ट्यूबवैल्ज थे परन्तु आसमान टूट कर गिर पड़ा और भारी बारिश हो गई और उससे इतना ज्यादा चना पैदा हो गया कि किसान उस चने को खेतों में से काट नहीं सका खेतों में ही बहुत सारा कुड़ गया, झड़ गया और जो फसल निकली भी तो उसे खरीदने वाला नहीं मिला । आए साल चौधरी दल सिंह जी ऐसे किसी साल की उन फिगरज को हाउस में बात कर देते हैं कि देखो उस साल इतना अनाज पैदा

हुआ था और अब इतना पैदा होता है तो अब मैं अनाज की पैदावार के बारे में करता हूँ कि इस सरकार ने अनाज बढ़ाने के लिये कितनी कोशिश की है और आज क्या पोजीशन है और पहले क्या पाजेशिन थी । पहले मैं गेहूँ की बात करता हूँ जो सारे भारत में काम आने वाला अनाज है 1966-67 के अन्दर गेहूँ की पैदावार हरियाणा में 10 लाख 59 हजार टन थी और 1972-73 में यह पैदावार बढ़कर 21 लाख 60 हजार टन हो गई । अब मुझे पता नहीं चौधरी दल सिंह जी अपने आंकड़े कहां से लाये कि पैदावार गिरी है आप खुद ही देखें कि कहा दस लाख टन और कहा 1 लाख टन । अब 1973-74 मैं हम आशा करते हैं कि 26 लाख टन गेहूँ हमारे प्रदेश में पैदा होगा आप देखें कि दस लाख टन से हमने शुरू किया था और अब 26 लाख टन तक पहुँच गये हैं यानी 1.6 लाख टन गेहूँ हमने इन सालों में ज्यादा पैदा करना शुरू कर दिया है । इसी तरह से आप चावल को लें । अध्यक्ष महोदय चावल हम सारे हिन्दूस्तान को आज देते हैं हम हरियाणा वाले चावल खद नहीं खाते हैं हम तो चावल वार त्यौहार को ही खाते हैं और सारा चावल उन इलाकों को देते हैं जो राइस ईटिंग हैं तो राइस के बारे में वह पोजीशन है कि 1966-67 में दो लाख 33 हजार टन चावल पैदा हुआ था और आज 1972-73 में हमारी चावल की पैदावार हुई है 4 लाख 66 हजार टन और 1973-74 में हमारा टारगेट है कि 5 लाख 40 हजार टन चावल पैदा होगा यानी दोगुना से ज्यादा पैदावार हो गई । मुझे नहीं पता वह भाई अपनी फिगरज कहां से ले आये? अब आप

बाजरा को ले लें 1966-67 में बाजरा पैदा हुआ 3 लाख 73 हजार न और 1972-73 में बाजरे की पैदावार हो गई 4 लाख 36 हजार टन यानी दो गुना मैं भी ज्यादा और अब 1973-74 में हम आशा करते हैं कि 6 लाख 60 हजार टन रसकी पैदावार होगी । तो सब प्रकार के अनाज की टोटल पैदावार कुल मिला कर 1966-67 में हुई 25 लाख 92 हजार टन और 1975-74 में यह टोटल पैदावार होगी 47 लाख 34 हजार टन । अब आप अंदाजा लगाये कि कहाँ 25 लाख टन और कहाँ 47 लाख टन आपको इन आंकड़ों से पता लग जायेगा कि कोई भी ऐसा आइटम अनाज का नहीं जिस में दो गुना से कम पैदावार बढी हो और कई-कई आइटमज में तो आप देखगे कि तीन गुना भी पैदावार हुई बै । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एक नवम्बर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना उस वक्त हरियाणा की जनता को एक लाख टन अनाज बाहर से मंगा कर गुजारा करना पड़ता था लेकिन आज यह हालत है कि न सिर्फ हम अपना गुजारा करते हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों को अनाज भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, पिछला साल हमारे लिए बहुत खराब था, बारिश भी कम हुई और नहरों में भी पानी कम चला लेकिन इसके बावजूद भी हमने तकरीबन 1 2 लाख टन अनाज दूसरे प्रदेशो को दिया इस प्रकार की हरित क्रान्ति, ग्रीन रैवोल्यूशन हमारे हरियाणा प्रदेश के अन्दर हुई है मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इ स अचीवमेट को नहीं मानते, क्या आप इन फैक्टस को झुटला सकते हैं? यह भाई फैक्टस को तोड़ू मरोड़ कर तरह-तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि इस

सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई पैदावार नहीं बढ़ाई है अब आप और आगे आये मैं अपिको बताना चाहता हूँ कि 1966-67 में राइस की हाई इल्लिडिंग वैरायटी के अंडर कुल चार हजार हैक्टेयर जमीन थी जिसमें इसकी काश्त होती थी लेकिन अब अध्यक्ष महोदय, एक लाख 25 हजार हैक्टेयर जमीन इसके नीचे है । आप देखें कितनी जमीन इन सालों में । हाई इल्लिडिंग वैरायटी के नीचे लायी गई है. यह तो हुई चावल की बात अब आप गेहूँ को लें । 1966- 67 में गेहूँ की हाई इल्लिडिंग वैरायटी के नीचे 15, 300 हैक्टेयर जमीन थी और आज है 12 लाख हैक्टेयर अब आप अंदाजा लगायें कि कहां 15, 300 हैक्टेयर और कहा 12 लाख हैक्टेयर । खाद का जहाँ तक सम्बन्ध है, कल एक भाई सदन में बोल रहे थे कि तरक्की तो करते जा रहे है, ट्यूबवैल्ज भी लग गये, नहरें भी बन गईं लेकिन बीज कहां से देंगे, खाद कहां से देंगे और पानी, कहां से देंगे? इनकी तो यह बात है कि कुछ करना धरना है नही खाली नुक्ताचीनी ही करनी है? किसी उन्से पूछा काजी जी दुबले क्यों हो रहे हो तो वह कहने लगे कि शहर की फिकर में. (हंसी) तो यह भाई भी इसी फिकर में माडे हो रहे हैं लेकिन मैं इन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यह सरकार हर चीज का प्रबन्ध करती है और कर रही है और सरकार को प्रदेश के विकास का बहुत ध्यान है । मैं अब खाद की ही बात करता हूँ हमारे प्रदेश में 1966- 67 में ह ह हजार 962 टन खाद किसान ने इस्तेमाल किया है और अब 1972- 73 में यह इस्तेमाल बढ़ कर 4 लाख 70 हजार 971 टन हो गया है । अब आप ही देख ले कि

कहां 66,962 टन और कहां 4, 70, 971 टन? 1974- 75 में हमारा टारगेट 7, 65, 000 टन खाद इस्तेमाल करने का है इस में शक नहीं कि इस वक्त देश में खाद की बड़ी भारी कमी है । देश में ही नहीं सारे संसार में ही इसकी कमी महसूस को जा रही है! हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में भी एक कारखाना खाद का लगाया जाये । पिछले दिनों रिवाड़ी के अन्दर मेरी केन्द्रीय मंत्री वरुआ साहब से मुलाकात हुई थी । हम एक फंक्शन में इकट्ठे गये थे । यह उनका महकमा था । मैंने उन से प्रार्थना को थी कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो सारे देश के अन्न भंडार को भरने में बड़ा योगदान करता है लेकिन खाद की यहां कमी थी । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वह बिचार कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में पानीपत के स्थान पर खाद का एक कारखाना खोल दिया जाये हम आशा रखते हैं कि खाद का कारखाना वहा पर खुलेगा (थम्पिंग) अध्यक्ष महोदय, मैं इन भाइयों से पूछ, मैं सीधे तो इन से प्रश्न नहीं कर सकता लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा इन से पुछनाचाहता हूं कि क्या उन्हीं ने इस खाद को बड़ाने को या इसके इस्तेमाल को ठीक ढंग से करने का सुझाव देने को कोई बात कभी कही है? सिवाये नुकताचीनी के कोई सुझाव इन्होंने नहीं दिया । हरियाणा का विकास कैसे हो सकता है और यह उस विकास में क्या योगदान कर सकते हैं कोई बात नहीं कही इन्होंने सिवाये नुकताचीनी के इतना विकास हो जाने के और इतनी खुशहाली आ जाने के वावजूद आज भी हमारे गांव गंदे है वहां गलियों में गोबर, कूड़ा करकट पड़ा रहता है और

मक्खियां भिनभिनाती है हमारे यह साथी नुकताचीनी की खातिर नुक्ता- चीनी करने की बजाये वहां गांव में जा कर लोगों को यह बात सिखायें कि वह गोबर को खुले में रखने को बजाये गड़े खोद कर रखे और गोबर गैस प्लांट लगायें क्योंकि उससे अच्छी खाद तैयार हो सकती हैं जो कि खेतों में काम आ सकती है । ऐसा करने से गांव में सफाई भी रह सकती है । लेकिन इन भाइयों ने कोई ऐसा तामीरी काम तो करना नहीं खाली नुक्ताचीनी ही करनी है अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी अचीवमेट की बात जे हमारी है उसका जिक्र किये बगैर मैं नहीं रह सकता । अध्यक्ष महोदय, आप किसान के घर में पैदा हुए हैं आप भली प्रकार जानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश के विकास की इसके सुन्दर भविष्य की कुंजी इस बात मे है कि हम अपने प्रदेश के किसान की जमीन को ज्यादा से ज्यादा पानी दे. आज हरियाणा सरकार ने निश्चय किया हुआ है कि प्रदेश के कोने-कोने में और एक-एक इंच जमीन को नहरों और टयूबवैल्ज से पानी दिया जाये । इसके बारे में भी अगर आप देखें तो आंखें खोल देने वाले आकड़े हैं । मैं पहले कैनल इरीगेशन के बारे में सदन को आंकड़े बताता हूं । 1966- 67 में नहरो से उठ लाख 81 हजार 589 एकड़ जमीन को पानी लगता था और टयूबवैल्ज से 8 लाख 51 हजार 422 एकड़ जमीन को पानी लगता था यानी कैनलज और टयूबवैल्ज से जो टोटल एरिया इरीगेट होता था वह था 42 लाख 32 हजार 821 एकड़ और आज 1972- 78 में कैनलज से 38 लाख 84 हजार 731 एकड़ और टयूबवैल्ज से 26

लाख 2 हजार 60 एकड़ जमीन को पानी लगता है यानी दोनो से जो एरिया इरीगेट होता है वह है 4 लाख 85 हजार 791 एकड़ नहरों से । सरकार ने 22, 52, 970 एकड़ से ज्यादा जमीन को पानी दिया । अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाएं कि अगर एक एकड़ जमीन को नहर या ट्यूबवैल से पानी मिल जाने से एक हजार रुपये को एडीशनल फसल पैदा हो तो वह इस प्रदेश को मालामाल करने के लिए काफी है, जो जमीन में अब तक पानी लगा है । आप जानते हैं कि आज किसान को पानी मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का किसान बड़ा मेहनती है, रात दिन मेहनत करता है और यहां की जमीन बड़ी अच्छी है अगर इसको पूरा पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, अच्छा बीज मिल जाए तो सारे हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या को हल कर सकता है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि किसान के घर अगर अनाज पैदा होता है, दो तीन फसलें पैदा होती हैं तो गांव के अन्दर जो भूमिहीन लोग रहते हैं कृषि-मजदूर है. उन को काम मिलता है । इनके इलावा मण्डियों और बाजारों के अन्दर रौनक आती है क्योंकि किसान जब अपना माल बेचने के लिए मण्डियों में आता है तो व्यापारियों का काम चलता है, किसान अपनी फसल बेचने के बाद दसों चीजें खरीदकर अपने बच्चों के लिए ले जाता है और इस तरह से सारे देश का विकास होता है डिवैल्पमेंट होती है । यानी बुनियादी बात यह है कि जो नहर और ट्यूबवैल का पानी है जो हरियाणा सरकार ने किसानों को दिया है, इससे विकास के कार्य चलते हैं । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने

नहरों के पानी का जिक्र किया । चौधरी दल सिंह ने कहा कि 90 परसेंट पैसा भिवानी के इलाके में खर्च किया जाता है मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि बह पैसा फजूल खर्च नहीं हुआ, उसका अपव्यय नहीं हुआ, वह तो उचित खर्च हुआ है । जुई कैनल से 20 हजार एकड़ भूमि को पानी लगा है, इंदिरा गान्धी कैनल से 25 हजार एकड़ जमीन को पानी मिला है, बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कैनल से 2 हजार एकड़ जमीन को पानी मिला और झज्जर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जिसका मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों उद्घाटन किया है, 4 हजार एकड़ जमीन को पानी मिला है । यानी कुल मिलाकर 61 हजार एकड़ भूमि को इन नहरों से पानी मिला है जिन के लिए मेरे भाई दल सिंह ने और उनके नेता ने कहा था कि यह खड्डे खुदवा दिए, इनमें आक पैदा होंगे, पानी कहां से आएगा अध्यक्ष महोदय, मेरी डेढ़ दो साल तक जबान बन्द रही मैं बोल नहीं सका वरना मैं बतलाता कि ये किस किस की बातें करते रहे जब बिजली लगी तो कह दिया कि इसमें करंट नहीं है, नहरे खुदी तो कह दिया कि पानी कहा से आएगा मैं कहता हूँ तुम सारे इस में डूब जाओ, इतना पानी तो आज भी जुई नहर में चलता है । आप देख रहे हैं कि इतनी जमीन को पानी लगा है, क्या जवाब कस इनके पास इस बात का हजारों एकड़ भूमि को इन नहरों से पानी लगा जिन को ये कहते थे कि इनमें आक जामेगा फजूल में खड्डे खुदवा दिए पिछले दिनों जब से यह महकमा मेरे पास आया, मैंने ये सब नहरे देखीं । इनको देख कर कितना चित्ता प्रसन्न हुआ यह मैं ही जानता हूँ । मैंने इस इलाके

की एक-एच इंच जमीन अपने पैरों से नापी है । इन नहरों में दरियाओ जैसा पानी चल रहा है, बिजली भी है, सड़के भी हैं, पीने का पानी गांव-गांव के अन्दर है यह मैंने खुद देखा है बापोडा के अन्दर वाटर सप्लाई की स्कीम है जिससे 85 गांवों को पानी दिया सैं यह स्कीम तमाम एशिया मे प्रथम नम्बर पर है । इस स्कीम को हरियाणा और हिन्दुस्तान के लोग तो क्या, तमाम दुनिया के लोग आकर देखते हैं । इसके अतिरिक्त ये टूरिजम की बातें करते है कि बड़खल लेक बना दी, यह बना दिया, वह बना दिया । मैं पूछता हूं कि इनको क्या सिरदर्द हैं? आप अध्यक्ष महोदय इतवार के दिन बड़खल लेक पर चले जाइए, इतनी भीड़ होती है कि आपको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल सकती, तमाम दिल्ली के लोग बड़खल लेक पर पधारते हैं । इन चीजों के कारण इस प्रदेश की चची सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी चलती है । पिछले दिनों स्विटजरलैंड और यूगोस्लाविया से डैलीगेशन आये और ये डैलीगेशन इस लेक को देखने के लिए गए । उन्होंने कहा कि ऐसा सुन्दर कम्पलैक्स तो हमने विदेशों में भी नहीं देखा जितना यह है अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मुझे 12 देशों में जाने का मौका मिला वहां मैं यह वताने में संकोच करता था कि मैं हिन्दुस्तान के एक प्रदेश हरियाणा का रहने वाला हूं लेकिन मैं यह कह देता था कि मैं हिन्दुस्तानी हूं । जब कभी मैं हरियाणा का नाम लेता था तो वे समझ जाते थे वे जानते थे कि हरियाणा एक प्रदेश है जहां बहुत तरक्की हुई है । वे हरियाणा प्रदेश को जानते हैं । ता इस किस्म

की चर्चा तो सारे विश्व के अन्दर होती है । सारे विश्व के अन्दर या सारे हिन्दुस्तान के अन्दर हरियाणा की तरक्की की तकलीफ किसी को है तो इन भाइयों को है और किसी को नहीं है । मैं कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कहता । पता नहीं इनके क्या दर्द है? इन्होंने कह दिया कि मसूरी में रैस्ट हाउस से लिया है । पिछले दिनों मुख्य मन्त्री जी मसूरी गए थे । उन्होंने किसी काम मुझे भी बुला लिया और मैं भी चला गया । हमारी आपस में बातचीत चलती रही । मे आपको कह देता हूँ भले ही आप इस बात का मजाक करें कोई आदमी जो काम करने वाला है, जिसके दिमाग में एक ही चिन्ता है कि किस प्रकार इस प्रदेश को खुशहाल बनाया जाए, किस कोने में क्या-क्या कमिया है उनको किस प्रकार दूर किया जाए, वह भाई अगर एक कोने में, एकान्त में बैठता है तो भलाई को बीसों चीजें अपने दिमाग से निकालता है,

एक सदस्य : गाव में बैठ कर निकाली जा सकती थी (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब इसी काम को डिसकस करने के लिए मुझे भी मुख्य मन्त्री ने वहां बुला लिया । अब हम वापिस आ रहे थे तो देहरादून में हमारे हरियाणा के एक भाई ने वहां थे ए 0 डी 0 एम 0 लगे हुए थे हमें इन्वाइट कर लिया । उस वक्त हम रैस्ट हाउस में ठहरे हुए थे अध्यक्ष महोदय, देहरादून की जो क्रीम थी जिस में हर पार्टी के नेता थे, बड़े-बड़े आफिसर थे, तकरीबन 100 के

करीब आदमी वहा चाए पर आये हुए थे । हमारी आपस में डिवैल्पमेंट की बातें चलने लगीं । कई तरह की बातें चलीं । एक भाई कहने लगे कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कोई चीफ मिनिस्टर आन-डैपूटेशन मिल जाए । अगर ऐसा तरीका निकल सकता हो तो दो चार साल के लिए हम भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को डैपूटेशन पर ले मैं ताकि हमारे यहा भी विकास हो जाए जिस तरह से हरियाणा का विकास हुआ है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हू, सिर्फ एक ही बात है जिस के अन्दर अपोजीशन के भाई सहयोग दे सकते ह और वह बात यह हो सकती है जिससे हरियाणा का पतन हो, गिरावट हो, उस बात के अन्दर सहयोग देने के लिए तैयार हैं इनके मुकाबले में दूसरी तरफ दूसरे भाई भी हैं जो अच्छे काम करने वाले के लिए लालायित रहते है, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अच्छे काम किए है उन कामों की सराहना करते हैं । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आपने उखलचिडे का नाम सुना होगा इसी तरह पालिटिक्स में भी उखलचिडे होते है । उखलचिडे का मतलब है कि जब अनाज के दाने कूटते हें तो उखल के चारो तरफ चिडे बैठ जाते हैं, बहुत सारे चिडे इकट्टे हो जाया करते हैं । लेकिन यह चीफ मिनिस्टर ऐसा है जिसने एक भी उखलचिडा अपने पास नहीं लगने दिया ये ऐसे मुख्य मंत्री हे जो किसी की धांधली नहीं चलने देते और जिन्होंने धाँधली चलाने की कोशिश की वे अपना पिंडा छुडाने को कोशिश करते है जिन भाइयों को बिजली मिलती है, सड़के मिलती है, नहरें मिलती हैं इस सरकार द्वारा और इस मुख्य मंत्री द्वारा, वे

यह चाहते हैं कि जिन्दगी भर यह आदमी मुख्य मंजे बना रहे अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि बमाम दुनियां के अन्दर यह एक उदाहरण है कि चौधरी बंसी लाल पिछले दिनों इलैक्शन में, एक दिन भी अपने इलाके में वोट मांगने के लिए नहीं गए । मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर यह बात गलत हो तो या तो वे डूब कर मर जाएं या मैं मर जाऊं, अगर बे इस बात को गलत साबित कर दें अध्यक्ष महोदय, सामने लिखा है कि सदर्थ में जो आदमी झूठ बोलता है वह पाप का भागी होता है । अगर चौधरी दल सि। सामने आ कर बैठें तो पढ़ सकते हैं. ?

चौधरी राम लाल वधवा : यह तो सामने वालो के लिए है । (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता : यह आप लोगों के लिए भी है अध्यक्ष महोदय, ये भाई एक बात का बार-बार जिक्र करते हैं । जब देखो तो कहते हे चार्जशीट । पता नहीं इन भाइयों ने पचास लाख कापियां छपवाई अथवा एक करोड़ छपवाई । जिस गांव में देखो हजारों चार्ज शीट की कापियां पड़ी हैं । वह चार्ज शीट इन्होंने गांव के एक-पक वोटर को दी जितना लम्बा चौड़ा कैंडिडेट ये ढूढ सकते थे उसे छांट कर लाए और ये मारे । भाई उसके साथ लग गए लेकिन मुख्य मंत्री जी एक दिन भी अपनी कांस्टिचुएंसी में नहीं गए, एक पोलिंग एजेंट नहीं बनाया, एक कांउटिंग एजेंट नहीं बनाया और बीस हजार वोटो से जीत गए वह चार्ज शीट लोगों ने तोशाम के टिब्बो में फाड़ कर फेंक दी ।

जनता ने जब स्पीकर साहब इस बात का फैसला कर दिया तो वह चार्जशीट क्या है? ये तो स्पीकर साहब, इस किस्म के इलजाम लगाते हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं है । यह चरित्र हनन का एक सिलसिला है जो कि विरोधी दल के भाई उठाए हुए हैं । जब इन्हें बात कहने को कोई नहीं मिलती तो करैक्टर असैसिनेशन का सहारा लेते हैं और बदनाम करने को कोशिश करते हैं । अगर ये अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें तो पता लगे कि हम कितने पानी में हैं । एक भाई को छापने का शौक लगा हुआ है । हर तीसरे दिन वे किताब छाप देते हैं । पता नहीं क्या-क्या बातें उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है । बेचारा इस बार तो गायब ही है । पता नहीं सदन में आता भी है या नहीं आता है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं उनका क्या जिक्र करूँ? मैंने उन्हें बड़े नजदीक से देखा है । मेरे शहर में वर्षों तक वे रहे हैं और क्या करते रहे और क्या नहीं करते रहे, इस बात को मैं क्या जवान पर लाऊँ क्योंकि उसे कहने से जबान अपवित्र हो जाएगी, नापाक हो जाएगी । अध्यक्ष महोदय, अगर कीचड़ के अन्दर पत्थर मारो तो छींटे लगते हैं । अगर उनकी फैमिली लाईफ को बात को देखें, अगर उनके घरेलू जीवन की बात को देखें, अगर उनके राजनैतिक जीवन को देखें तो अध्यक्ष महोदय, महसूस होता है कि वे भगवे कपड़े उन्होंने शौक से नहीं पहने हैं बल्कि इसलिए पहने हैं क्योंकि उनके सफेद कपड़ों पर इतने अधिक दाग लग गए थे कि वह उन्हें छुपा नहीं सकते थे बिना भगवे कपड़ों के वह व्यक्ति आज किताब छापे, दूसरों पर आरोप लगाए और कांच के महल में

बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंके! अगर हिम्मत है तो आए मैदान के अन्दर और बतलाए कि उसका अपना क्या हाल है उसने अपने जीवन के अन्दर क्या किया है? यही हाल स्पीकर साहब दूसरे उन भाइयों का है जो संघर्ष समिति बनाए फिर रहे हैं

स्पीकर साहब, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इसे मैं अपने प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात कहूं या क् कहूं । कुछ लोग ऐसे हैं जब उनकी नौकरी लग जाती है तो सरकार भी अच्छी, मुख्य मंत्री भी अच्छा, अफसर भी अच्छे काम भी अच्छा और जनता भी अच्छी । उस वक्त इन सबकी वे बड़ी तारीफ करते हैं लेकिन जिस दिन नौकरी छूट जाती है उस दिन मुख्य मंत्री भी बुरा, सरकार भी बुरी, और जनता भी बुरी और हरियाणा भी बुरा हो जाता है । तो यह सारी नौकरी की बात है और कोई बात नहीं, कोई उद्देश्य नहीं और कोई पोलिटिकल लक्ष्य नहीं । उनका एक ही तरीका है कि नौकरी मिली तो सब ठीक और नौकरी छूटी तो फिर किसान संघर्ष समिति या हरिजन संघर्ष समिति, लोगों की आंखों में धूल झोंकना, चन्दा इकठा करना और उसके बाद उसे हजम करना । मैं पूछ ना चाहता हूं कि वे संघर्ष किस बात का करना चाहते हैं? असली बात तो मेरे नोटिस में कल आई । असली संघर्ष तो परसों हुआ जब कि इनका आपस में तू-तू मैं-मैं हुई — (विघ्न)

एक सदस्य : कृपया नाम ले दें कि आपका मतलब किस संघर्ष समिति से है

श्री बनारसी दास गुप्ता : मेरा अभिप्राय दोनों से ही है क्योंकि मैंने दोनों के चौधरियो को देखा हुआ है । आज आप इन्हें नौकरी दे दें आज से ही तरक्की की तारीफ करना शुरू कर देंगे ।

चौधरी दल सिंह : फिर नौकरी दिला ही दो ।

श्री बनारसी दास गुप्त : जिस आदमी को कसौटी पर कस कर देख लिया हो और जो बिलकुल खोटा हो उसको कौन नौकरी दे दे?

तो अध्यक्ष महोदय, ये जो नई-नई नहरें बनी इनसे कितनी बड़ी भारी इरीगेशन हमारे प्रईश के अस्दर हुई यह आप भली भांति जानते है । इनमें से जुई कैनाल पैरीनियल हो गई है और बाकी की नहरें भी उस दिन पैरीनियल हो जाएगी जिस दिन हमें रावी और ब्यास का पानी मिलेगा । इस बात पर भी ये भाई बहते है कि रावी व्यास का पानी कब मिलेगा ? रावी व्यास का पानी हमें जरूर मिलेगा हमारा किसी के साथ झगडा नही है । न हमारा पंजाब के साथ झगडा सै और न ही किसी और के साथ झगडा वै । हम सब भाई हैं पड़ोसी प्रदेशों के साथ पानी आदि में जो हमारा हिस्सा है, हमारा जो हक है वह हक हमें जरूर मिलेगा और जिस दिन मिलेगा उस दिन इंदिरा गांधी केनाल चक्रवर्ती कैनाल और झज्जर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम आदि सभी पैरीनियल हो जाएंगी इसके अलावा ए क खुशी की बात, अध्यक्ष महोदय, मैं

और बताऊं । शायद चौधरी दल सिंह खुश न हो वह बात यह हूँ कि हम तुक और बड़ा भारी प्रोजैक्ट हाथ में लेने जा रहे हैं । वह प्रोजैक्ट है जवाहरलाल नेहरू कौनाल । वह 30 करोड़ रुपए की लागत से बने गा अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रोजैकट बन कर तैयार हो जाएगा तो जिला महेन्द्रगढ, भिवानी जिल का इलाका और रोहतक का वह इलाका जिसमे पानी नहीं लगता, इन सभी जिलों की लगभग 8 लाख सकड़े जमीन को पानी मिलेगा अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता नहीं लगता कि अब ये कहते क्या हैं? चर्चा किस बात को करते हैं? पानी की करते हैं, तो क्यों करते हैं, बिजली की करते है तो क्यों करते है? हस्पतालों की बात भी अगर देखे तो आज सवेरे प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर 80 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से दवाई के ऊपर केवल हरियाणा में ही खर्च किए जाते हैं आज हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वे सारे प्रदेशों से ज्यादा विकसित हैं कई जगहों पर हस्पतालों का नवनिर्माण किया गया है (विघ्न)..

चौधरी दल सिंह : यह सिर्फ कागजों पर है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : कागजों में ही नहीं है, बीमार होकर देखो अभी दवाई दिलाई जाएगी, अभी इंजैक्शन और शीशी तैयार मिलेगी

अध्यक्ष महोदय, हमने सारे बजट का 62.3 परसेंट नहरों और पावर के लिए रखा है क्योंकि असली चीज जो है प्रदेश के

विकास की है वह यह है इस सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, जो बुनियादी बातें हैं उन्हें प्राथमिकता दी जिससे प्रदेश खुशहाल हो और इस इलाके के लोग खुशहाल हों आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि हम पक्षपात के शिकार होने रहे हैं जिन दिनों हम पञ्जाब में थे उस समय हमारे साथ कैसा व्यवहार होता था और उस दुःख से हम कितने दुःखी थे, यह भी अध्यक्ष महोदय. आप भली भाँति जानते हैं लेकिन आज यह वक्त आया है कि इन पाँच छः साल के अन्दर हरियाणा में बड़ा भारी विकास का काम हुआ है । इसके इलावा अध्यक्ष महोदय, हम और काम भी कर रहे हैं । हम वैस्टर्न जमना कैनल की री-मॉडलिंग कर रहे हैं, इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली से सभी चरणों का कार्य पूर्ण करने वाले हैं, दिल्ली रजवाहे के सिरे दिल्ली शाखा भालोट अप-शाखा और हांसी शाखा की लाइनिंग कर रहे हैं. गुडगांव नहर को पक्का बना रहे हैं, बीवीपुर बंध बना रहे हैं, लडोहा का जो बाढ़ नियंत्रण कम्प्लैक्स है उसका इंतजाम कर रहे हैं, कोटला लेक जो दस वर्ग किलोमीटर भी है उसका बांध बना रहे हैं और औगमेंटेशन कैनल पिछले दिनों बनाई गई है । यह सारा प्रबन्ध किया जा रहा है और स्टेट को खुशहाली के लिए किया जा रहा है । ये फ़ैक्टस एंड फिगरज हैं, ये तथ्य हैं और केवल जबानी जमा खर्च नहीं है । स्पीकर साहब, हरियाणा में एक कहावत है कि—

‘जिसकी उतर जाए लोई उसका क्या करे कोई ।’

इन भाइयों की तो लोई उतर गई है और इनका इलाज किसी के पास नहीं है, दमके पश्चात, अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात मैं पावर की बता दूँ क्योंकि यह मेरा महकमा है सन् 1967-68 में 57 लाख यूनिट्स की खपत थी लेकिन आज 119 लाख युनिट्स की खपत है । यह मैं पर-कैपिटा के हिमाब से बता रहा हूँ । 1967-68 के अन्दर हमारे विजली बोर्ड को 8 करोड़ रुपए की आमदनी थी लेकिन आज 30 करोड़ रुपए को सै, जिसका कि ये दिवाला निकला हुआ बताते हैं, । यह अध्यक्ष महोदय उन्हीं किताबों की बात है जिसको ये उल्टे बल पकड़ते हैं, सुल्टे बल नहीं पकड़ते । (विघन) एक तारीफ की बात, अध्यक्ष, महोदय, यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर खेती के लिए बिजली के उपयोग की परसेंटेज जो है वह सारे मुल्क के अन्दर हाईयस्ट सैं । हम 41 परसेंट बिजली ट्यूबवैल्ज और खेतों पर इस्तेमाल करते हैं । गांव को बिजली देने की बात तो मैं क्या बताऊं क्योंकि वह तो सैट परसेंट रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन हो चुकी है । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री निहाल सिंह पदासीन हुए) ट्यूबवैल्ज का जहां तक सम्बन्ध है. वे 20,190 थे जिस वक्त यह सरकार बनी थी लेकिन आज 1, 25232 ट्यूबवैल्ज हैं जिनसे तमाम खेतों वे पानी दिया जाता है ।

एक बात सभापति जी, जो ये कहते हैं कि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन के अन्दर पता नहीं क्या कुछ हुआ, करोड़ों रुपया बनाया गया । जो कुछ भी पहले हुआ वह प्रदेश के भले के लिए

हुआ । मैं इन भाइयों को बतलाना चाहता हूँ कि उस टाईम पर इलैस्ट्रीफिकेशन पर कुल 54 करोड़ रुपया खर्च हुआ । इतने ट्यूबवैलज को अनरजाइज करने के लिए और इतने गावों को बिजली देने के लिए यह पैसा खर्च हुआ सभापति महोदय आज चार साल के बाद यही काम हम अपने हाथ में ले तो बहुत ज्यादा रुपया खर्च करना पड़े । क्योंकि आज हरेक चीज को 30 और 40 परसेन्ट तक कीमतें बढ़ गयी हैं । अगर हम आज का हिसाब-किताब लगाये तो हमारा 22 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हो । चौधरी दल सिंह जी तो दुकान करते हैं वे तो हिसाब-किताब लगा कर देख सकते हैं आज अगर इस काम को हम अपने हाथ में लेते तो बड़ा खर्चा होना था । हमें रूरल इलैस्ट्रीफिकेशन तो जरूर करना था और ट्यूबवैलज के लिए भी बिजली प्ररूर देनी थी तो इस पर हमें 22 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ता । इ स चार साल के अन्दर जो बिजली से खेती को पानी मिला है, जो उद्योग धन्धे और कल-कारखाने चले हैं उससे भी करोड़ों रुपये का लाभ हुआ है । यह भाई उसका तो हिसाब लगाते ही नहीं है ये नुक्ताचीनी तो रोज करते है लेकिन हिसाब नहीं लगाते है कि क्या कुछ लाभ हुआ है । यह बिजली बोर्ड का हिसाब मैंने सदन के सामने रखा है ।

चेयरमैन साहब, ओर भी बहुत सारी बातें हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली की बड़ी भारी शार्टेज आजकल हमारे प्रदेश में है । वह केवल हमारे ही प्रदेश में नहीं है बल्कि पंजाब

प्रदेश में भी सै और दूसरी जगहों पर भी है । इस कमी को पूरा करैन के लिए पूरी चेष्टा की जा रही है । जैसा कि आपको और सदन को पता है कि फरीदाबाद के अन्दर हम 60 मैगावाट का थर्मल प्लांट लगाने जा रहे है जो कि अप्रैल में शुरू हो जायेगा और 60 ही मैगावाट का ए क और अगले साल शुरू हो जायेगा । इसी प्रकार से पानीपत के अन्दर भी 110-110 मैगावाट के दो थर्मल प्लांट लगा रहे है उन में एक 1976-77 में बन जायेगा और दूसरा उससे एक साल बाद बन जाये गा । हमारे प्रदेश को सतलुज-ब्यास लिंक से भी बिजली मिलने वाली है हमारा जो पडौसी हिमाचल राज्य है जहां पर बड़े स्कोप हैं बिजली पैदा करने के । वहां पर बड़े-बड़े हाइड्रो इलैक्ट्रिकि प्रोजैक्ट बन रहे हैं हम उनके साथ बातचीत कर रहे है कि कोई ऐसा ही प्रोजैक्ट चम्बा के दास लगाया जाये जिससे हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके । उसके लिए अभी दो दिन पहले मैंने और हमारे मुख्य मंत्री जी ने वहां के एक मिनिस्टर से बैठकर बातचीत की हे । यह बात नहीं है कि इस तरफ से आखें मूंदे हुए बैठे हैं । हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में बिजली की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये ।

सभापति जी यहां पर सड्कों का सवाल भी आया है हरियाणा के अन्दर 60 प्रतिशत गांवो को सड्कों सेमिला दिया गया है । हिन्दुस्तान का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर 60 प्रतिशत गांवों को सड्कों से मिलाया गया हो हमारे प्रदेश के

अन्दर हर क्षेत्र में उन्नति हुई है । हरिजन भाइयों की ही बात लीजिए । हरिजन कल्याण निगम बनाई गई है । उससे हरिजनों को कर्जे दिए जाते हैं ताकि जो ' कमजोर वर्ग के लोग हैं वे अपना धन्धा कर सकें । अभी हमारे समाज कल्याण मंत्री महोदय ने कुछ घोषणाएं की हैं कि कुछ ऐ से उद्योग धन्धे लगाये जा रहे हैं जो केवल हरिजनों के लिए ही होंगे । वे हरिजन कल्याण निगम लगायेगी उससे हरिजनों को रोजगार मिलेगा ।

जहां तक जमीन की बात है, उसके बारे में भी मैं निवेदन कर देना चाहता कि हरियाणा में जो भी सरप्लस जमीन होगी वह भूमिहीन और हरिजन भाइयों का मिलेगी । यह दूसरी बात है कि कोई भाई चन्दा इकट्ठा करने के लिए ला ही आन्दोलन कर दे तो उसका कोई इलाज नहीं है सरकार हरिजन और वीकर सेक्शन के लिए काफी कुछ कर रही है हरियाणा में वाटर सप्लाई की बड़ी भारी समस्या है । सभापति महोदय हमारे हरियाणा में 4120 गांव ऐसे हैं जिनका पानी पीने के लायक नहीं । आपको यह जानकर खुशी होगी कि 31 मार्च 1974 तक हम 750 गांवों को मीठा पानी पाईपो के द्वारा पहुंचा पायेगें यानी 31 मार्च तक 750 गांवों को मीठा पानी पहुंच जाएगा । अगली पंच-वर्षीय योजना में 1400 गांवों को मीठा पानी और देंगे । इसी प्रकार से हमारी चेष्टा है कि मीठा पानी हर गांव में प्रायरिटी दे कर पहुंचाया जाए । हमने कुछ कामों की प्रायरिटी फिक्स की है । पहली प्रायरिटी बिजली और पावर की है दूसरी पीने के पानी को और तीसरी

स्वास्थ्य की । इसके बाद और प्रायः रीति हैं । इसी प्रकार से खर्चा किया जा रहा है । कहने का अभिप्राय यह है कि आलराउण्ड. चहुंमुखी विकास हरियाणा प्रदेश में हुआ है । कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है चाहे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, नहर का, खेती का हो जहां पर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तरक्की के काम न किए हों । इस सरकार ने काम इतने ज्यादा किए हैं कि अगर मैं वर्णन करता रहूं तो घण्टों लग सकते हैं मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो मेरे विभाग से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं उनके बारे में मैंने सभी बातें बता दी हैं । इन शब्दों के साब मैं आपका धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह कितना शानदार बजट है जो हरियाणा प्रदेश को सरकार ने बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए रखा है यह बड़ा भारी कदम है । ऐसे बजट की पूरी तरह से सराहना की जाय तो अच्छा ही है, मैं विपक्षी दल के भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे कोई रचनात्मक सुझाव दे बजाय इसके कि नुक्ताचीनी केवल नुक्ताचीनी की गर्ज से करें । धन्यवाद ।

ब्यक्तिगत स्पष्टीकरण—चौधरी दल सिंह द्वारा

चौधरी दल सिंह : आन ए प्वांयट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर । श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने जो बातें कहीं हैं उनके बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में मेरा नाम पचासों बार लिया है । (विधन)

सिचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :
मैंने आपका नाम भलाई में लिया है । आप पर कोई आरोप नहीं लगाया । (विधन)

चौधरी दल सिंह : बेशक आपने भलाई में लिया, लेकिन मेरा भी तो राईट है अपनी स्पीच में बार-बार इन्होंने मेरा नाम लिया है (विधन)

श्री सभापति : गर्वनर ए डूस के वक्त आपने अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन में ये सभी बातें कह दी थीं । अब भी वही एक्सप्लेनेशन होगा । (विधन)

चौधरी दल सिंह : चौयरमैन साहब, मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जो बातें मैंने बजट स्पीच के बारे कहनी थी वे कह ली हैं । मैं तो इ तना ही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ मेरी वात को समझा है, मेरे ख्याल में वे बड़ी गल्ती पर हैं । मैंने कभी यह बात नहीं कही कि भिवानी में और महेन्द्रगढ में पानी नहीं देना चाहिए. मैं बिल्कुल यह बात अब भी कहने के लिए तैयार हूं कि वहां पानी जाना चाहिए । मैंने और जो बातें कही हैं, वे उन्होंने मानी हैं कि हम पंजाब से अलहिदा क्यों हु ए? मैंने यही बातें कहीं कि हरियाणा प्रान्त के और भी ऐसे इलाके है जहा पानी की जरूरत है । मैंने खासतौर पर अपने इलाकों के गांवों के नाम भी बताए हैं । (विधन)...

श्री बनारसी दास गुप्त : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । मैं तो यह समझता हूँ कि इस में कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने वाली बातें नहीं हैं । जो बातें बजट के अन्दर थीं उनके बारे में उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और मैंने भी अपने विचार ब्यक्त किए हैं । मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप चौधरी दल सिंह पर नहीं लगाया है जिसके लिये वे अपना स्पष्टीकरण दे । (विधन)

श्री सभापति : चौधरी दल सिंह अब आपका स्पष्टीकरण हो गया है और मान लिया गया है ।

चौधरी दल सिंह : इन्होंने कहा कि हम झूठ बोलते हैं । मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो फिगरज पढ़ी हैं, अब मैं भी फिगरजु पढना चाहता हूँ । जो मैंने फिगज पहले दी हैं वे गलत नहीं हैं । मैं तो यह समझता हूँ कि ये जिस स्कीम को हाथ लगाते हैं वे किसी चीज को की भावना के तहत लगाते हैं । (विधन)

श्री सभापति : ये का शब्द ऐक्सपंज कर दिया जाए । (विधन)

चौधरी दल सिंह :

श्री सभापति : ये सब रिमार्क्स ऐक्सपंज कर दिये जायें । आपका पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो गया कि महेन्द्रगढ और भिवानी को पानी मिलना चाहिए । आपने यह माना है । आप बैठिए (विधन)

चौधरी दल सिंह : चेयरमेन साहब यह तो बड़ी गलत बात हुई (विघ्न)

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिए । (विघ्न)

चौधरी दल सिंह : इन्होंने जो कुछ कहा है, यह बड़े गलत ढंग से कहा है (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता : अगर चेयरमैन साहब ये अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देंगे तो उस के जबाब में मुझे भी फिर ऐक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा । (विघ्न)

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिए, आपका ऐक्सप्लेनेशन आ गया । (विघ्न)

वर्ष 1974— 75 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी चान्द राम : सभापति महोदय, मैं न तो गवर्नर एड्रेस पर बोला हूँ और न ही मुझे कभी बजट स्पीच पर टाईम मिला है । क्या मुझे भी टाईम मिलेगा?

श्री सभापति : आपको भी टाईम मिलेगा ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : चेयरमैन साहब क्या मेरा भी नाम लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि बजट स्पीच पर मैं नहीं बोला हूँ ।

श्री सभापति : हां आपको टाईम मिलेगा ।

चौधरी श्याम लाल (पलवल) : माननीय सभापति जी सदन के समक्ष वर्ष 1974-75 के बजट अनुमान प्रस्तुत हैं । इन पर कल से डिस्कशन जारी है । वित्त मंत्री महोदय ने वर्तमान व्यापक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी कठिनाइयों पर काबू पा लेने की जो आशा व्यक्त की है उससे हमें उनपर पूरा विश्वास है कि यह सरकार जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में समर्थ होगी मैं ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से बजट के बारे में अपना भाषण दिया है मैं तो केवल अपने ही क्षेत्र में सम्बन्धित कुछ समस्याओं को विभागवाइज आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं ।

सिंचाई के विषय में काफी कुछ कहा जा चुका है । बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने उठान सिंचाई योजना का वर्णन किया है । मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं और यह बात सब को विदित है कि हरियाणा एक नवम्बर, 1966 के बाद भारत के नक्शे पर उदय हुआ है और इससे पूर्व इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण था वह सिंचाई के साधनों का अभाव था इस क्षेत्र के लिए सिंचाई योजनाएं बनाने की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था । गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से यहां पर बताया कि ज्वायंट पंजाब व किस प्रकार से हमारे इलाके के साथ सलूक होता रहा है । हरियाणा एक कृषि- प्रधान प्रदेश है और यहां के 82 फीसदी लोग किसान हैं । जब तक इन 82 फीसदी किसानों की उन्नति

और उत्थान नहीं होगा तब तक इस प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता । जो योजनायें हमने बनायी हैं, उनके द्वारा जब तक हम भूमि को पानी नहीं दे पाते, जो एक अति आवश्यक कार्य है, तब तक हम यह कैसे आशा रख सकते हैं कि किसान उभरेंगे? सिंचाई के लिए हमने बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई हैं । एक जवाहरलाल नेहरू कैनल योजना हूँ जिस पर 30 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है. मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इन बड़ी- बड़ी योजनाओं के अन्दर कुछ छोटी-छोटी योजनाये भी शामिल की जानी चाहियें ताकि जो क्षेत्रीय मांगे हैं, वे दब कर न रह जायें । मेरे हल्के मे एक रजोलाका का माईनर है । वह तीन साल पहले स्वीकृत हुई थी लेकिन अभी तक भी उस पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । वह एक ऐसा बदकिस्मत गांव है कि जहां पर आज के युग में भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता । लोग जाहड का पानी पीते है । जोहड़ का पानी समाप्त होने के बाद वहां के लोगों की बड़ी दुर्गति होती है । उन्हें कई-कई मील से पानी लाना पडता है । यदि इस माईनर को पूरा कर दिया जाए तो जहां इस माईनर से खेतों की प्यास बुझेगी वहां लोगों का पीने का पानी मुहैया। होने से तकलीफ दूर हो जायेगी । कुछ समय पहले की बात है उन लोगों में आपस में एलाईनमेंट का झगड़ा था । मुझे खुशी है कि हमारे ही इलाके की राज्य मंत्री ने बीच में पड कर वह ठीक करवा दिया । हालांकि अब वह झगड़ा समाप्त हो चुका है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, उस योजना को पूरा नहीं किया जा रहा है

मेरा बिल्कुल यह मुद्दा नहीं है कि मैं यह चाहूँ कि यह माईनर कैसे और कहां से निकले । मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गाव को इस माईनर का पानी मिले । इसके अलावा एक और धतीर माईनर है, जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ । इस माईनर को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है यह माईनर सिकन्दरपुर गांव के पास अधूरी छोड़ दी है । यह माईनर जहां तक पहुंचनी थी, वहां तक नहीं पहुंची है और अधूरी पड़ी हुई है जहां पर अधूरी छोड़ी हुई है, वहां पर भी कोई आउटलैट नहीं है उसका नतीजा यह हुआ है कि जब वा माईनर चलती है तो लोगों के हरे-भरे खेतों में पानी भर जाता है और लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं । यहीं तक नहीं, उस माईनर के चलने से गांव की गलियों में भी पानी आ जाता है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है । जहां तक वह माईनर पहुंचनी है, वह माईनर वहां तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो और उस माईनर का पूरा लाभ हो सके । हमारे रुलाके पलवल-बल्भगढ़ में यू. पी. की आगरा नहर का कुछ हिस्सा गुजरता है । यह बहुत देर से हमारे लिए एक सिरदर्दी बनी हुई है इस नहर से हमें पूरा पानी नहीं मिलता है । वे लोग बड़ी चालाकी बरतते हैं । पहले तो पूरा पानी देते हैं और यह जाहिर कर देते हैं कि हमने इतने ए रिया को पानी दिया लेकिन बाद में पानी नहीं देते । लोग इस उम्मीद में नई किस्म की वैराइटीज बो देते हैं कि उन्हें पूरा पानी मिलेगा लेकिन उन्हें पूरा पानी नहीं मिलता मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गा तो लोगों को पूरा

पानी दिलवाने के लिए उनसे अश्योरैन्स लिया जाए या फिर जहां जहां से यह नहर हमारे प्रदेश में से गुजरती है, उसका कंट्रोल हरियाणा सरकार अपने कब्जे में ले ले ताकि लोगों की यह तकलीफ दूर हो सके । इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि एक-दो गांव ऐसे हैं जहां पर सैकड़ों-हजारों एकड़ रकबा है लेकिन वहां तक कोई माईनर नहीं पहुंचती है मेरे ख्याल में स्टेट-ट्यूबवैलज कारपोरेशन से उस हजारों एकड़ जमीन में पानी देने की कोई प्लान बनायी जाये ताकि वहां पर आबपाशी हो सके । ऐसा ही एक जनौली न् है जहां पर हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है । वहां पर माईनर इरीगेशन ट्यूबवैल कारपोरेशन की ओर से ट्यूबवैल लगवाये जाने चाहिये इसके अलावा एक अहरवा गांव है जिसका हजारों एकड़ रकबा सूखा पड़ा है इसके अलावा एक गोन्धी डेन हमारे एक बड़े लम्बे चौड़े एरिये से गुजरती है, उस पर जगह जगह पुल न होने की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी है । वहां पर पुल बनने चाहिये कई गावों में तो पहले आर्टीफीशियल पुल बने हुए थे लेकिन अब वे भी टूट चुके हैं जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त के पूरे साधन मुहैया नहीं हैं । एक छपरोला गांव, मेरी कास्टाच्यएसी में तो नहीं है लेकिन बहिन शारदा जी की कांस्टीच्यूएसी में पडता है इस में भी ऐसी ही तकलीफ है, वहां पर भी पुल होना चाहिए । सिकन्दरपूर में भी हालांकि एक आर्टीफिशियल पुल सरकार ने बनाया हुआ है लेकिन वहां पर भी एक पुल होना चाहिए इसी तरह से मेरा कहना यह है कि जहां-जहां पर लोगों को जरूरत है वहां पर पुल बनाए जाने

चाहिए) अब मैं कृषि के बारे में कुछेक बातें कहना चाहता हूँ । कृषि एक ऐसा उद्योग है जिसकी सफलता और असफलता अधिकतर प्रकृति पर निर्भर करती है । सरकार की सैट-परसैट योजनाएँ कभी भी सफल नहीं होती । जब किसान खेती करता है तो पूरी मेहनत से खेत तै-यार करता है, ऐग्रिकल्चर इन्सपैक्टरो की हिदायतों के मुताबिक खाद डालता है पानी देता है, लेकिन पकी हुई फसल पर गर्म हवा चल जाने या कई बार जब प्रकृति रुष्ट होती हूँ तो ओले पड़ जाना जैसी महावारी आ जाती है उसकी मेहनत का फल ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर करता है फिर भी हरियाणा में कृषि के मामले में सतोषजनक प्रगति हुई है । हरियाणा की हिसार ऐग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे लिये बड़े गौरव का विषय बनी हुई है. पिछले साल केरल से ऐस्टीमेटस कमेटी आयी तो हमारी उनसे जब डिसकशन हुई तो उन्होंने हरियाणा की प्रगति के बारे में और विभिन्न विषयों के बारे में जानना चाहा । हमने उन्हें कृषि में, उद्योग में, और दूसरे विषयों के बारे में जो प्रगति हमारे यहां हुई थी, वह बतायी उनका एक सदस्य यह बोला कि आपकी जो ऐग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी है वह देश में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया जो कि भारतवर्ष में एक अजूबा बनने जा रही कब. दूसरे प्रान्त के विधायक की जबानी यह बात सुनकर हमें बड़ा गर्व हुआ ऐग्रिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए ऐग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन की तरफ से 17 सैटर्ज और 30 सब-सैटर्ज हरियाणा प्रदेश में खोले गये हैं । यह एक सराहनीय कार्य है । इस बारे में मेरी अपनी सलाह यह है कि

ऐग्रो-इडस्ट्रीज कारपोरेशन जो ट्रैक्टर देती है, कम से कम उन ट्रैक्टरों के स्पेयर पार्ट्स इन सैटर्स में अवश्य होने चाहिये और काफी तादाद में होने चाहिये क्योंकि कृषक हमेशा इन स्पेयर-पार्ट्स के मामले में बड़ा लुटता है । यह नहीं होना चाहिए कि सैटर्स में ट्रैक्टर खड़े कर दें और वे जुताई के ही काम आये । वहाँ ट्रैक्टरों के सब स्पेयर पार्ट्स मिलने चाहिये और ट्रैक्टरों की पूरी सर्विस ताकि किसान लुटाई से बच सके । आज बाजार में यह हालत है कि उन्हें रुपये के काम के सौ रुपये देने पड़ते हैं । मेरा यह भी सुझाव है कि जहाँ पर इस किस्म के सैटर्स नहीं हैं, वहाँ पर सैटर्स खोले जायें ।

अब मैं पशुपालन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । पशुपालन में भी हमने नुमाया तरक्की की है । हमने जगह-जगह सैटर्स खोले हैं । मैं एक बात सरकार के नोटिस में ला देना चाहता हूँ । हमारे देहात के इलाकों में जो सांड या भैंसे मौजूद होते थे, वह तो सरकार ने सारे पकड़वा लिए लेकिन गर्भाधान के सही और पूरे साधन वह स्टेट में नहीं दे सके । इससे लोगों में बड़ी बेचौनी है । कई लोगों ने तो यह घन्धा ही बना लिया है कि भैंसा ले लेते हैं और हरेक भैंस के पीछे 5- 5 रुपए चार्ज करते हैं हालांकि वह कोई अच्छी नस्ल नहीं होती । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कम से कम जहाँ पर सैटर्स हैं वहाँ पर कुछ प्रबन्ध किया जाए या पंचायतों को यह आज्ञा होनी चाहिए कि वे अपनी तरफ से अच्छी नस्ल के भैंसे रख सकें । वही पर जो भैंसे या सांड मौजूद

हैं, उन्हें तो आप पकड़ लेते हैं लेकिन अच्छी नसल के पशु मौजूद नहीं है इस के लिए जल्दी ही कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिए । मैं यह मानता हूँ कि हरियाणा जिस प्रकार से हरित क्रांति के रैवोल्यूशन में अग्रसर हो रहा है उसी प्रकार में इसे सफेद क्रांति में भी पूरी सफलता मिलेगी ।

यहां पर वनों का या फारेस्ट्स का भी काफी जिक्र किया गया । फारेस्ट के बारे में केवल दो-एक शब्द ही कहना चाहता हूँ । पिछले वर्ष हमारी ऐस्टीमेट्स कमेटी भी मौरनी हिल्ज गई थी । वनों के लिए 60,000 चीड़ के नए वृक्ष लगाए गए थे, हम उनके बारे में जानने के लिए वहा गए थे । वह बड़ा सुन्दर स्थल है । टूरिजम की तरफ से एक लाल मुनिया नाम का छोटा सा रैस्ट हाउस बनाया गया है, जो वड़ा आकर्षक है । जैसे गुप्ता जी ने इस बारे में बताया है, उसी प्रकार को इसके पीछे भावना है । यह सुविधा अब सब लोगों को प्राप्त है । यह एक ऐसी सुविधा है जिससे पहले हम लोग वंचित थे । अब जब एक आम आदमी भी दिल्ली से चलता है तो वृक्षों की कतार को देखकर यह अंदाजा लगा लेता है कि हरियाणा शुरू हो गया है । हरियाणा को हरियाली के लिए यह एक बहुत जरूरी चीज है । अब मैं सहकारिता पर आता हूँ । सहकारिता जिस उद्देश्य से चलाई गई थी, पूर्ण रूप से उद्देश्य को पूर्ति नहीं हो रही है । सहकारी आज फर्जकारो बन गई है । जैसा कि पहले भी कहा गया है कि वो लोग कर्जा लेने वाले हैं उन में एक-एक आदमी पचास-पचास

फर्जी अंगूठा लगाकर इकट्ठी रकम ने लेता है और इस बात से लोग परेशान होते हैं जिन्होंने कर्ज नहीं लिया होता । उनको पता ही नहीं होता कि किसी ने फर्जी अंगूठा लगाकर उनके नाम से पैसा ले लिया है । इसलिए सरकार को चाहिए कि सहकारिता को पापुलर करने के लिए, सर्व प्रिय बनाने के लिए जो बीच में बैठे हुए गड़बड़ करते हैं उनको दूर किया जाए ।

उद्योग के विषय में मुझे कोई लम्बा चौड़ा नहीं कहना क्योंकि उद्योग से मेरा सम्बन्ध नहीं है । मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर जनरल आफ एम्पलायमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री आफ लेबर एण्ड एम्पलायमेंट की तरफ से हमारे डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के नाम पत्रक लैटर आया है जिसमें फरीदाबाद में उनसे 30 एकड़ जमीन मागी गई है । वहाँ पर सोवियत संघ की सहायता से एक ऑटोमैटिव ट्रेडज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन लगाना चाहते हैं । इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए आन्ध्र प्रदेश और दूसरी कई स्टेटों ने अपने यहाँ लगाने के लिए आफर किया लेकिन वे दिल्ली के नजदीक लगाना चाहते हैं सरकार इस सेंटर के लिए जल्दी से जल्दी 30 एकड़ जमीन फरीदाबाद में उपलब्ध कराए । यह स्टेट के इन्ट्रैस्ट में है उससे लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी और एम्पलायमेंट भी मिलेगा । सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

सड़क परिवहन—ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करके सरकार ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है, जहाँ पर इतना बड़ा

आर्गेनाइजेशन, हो, इतना बड़ा काम हो वहाँ पर कुछ त्रुटियों का होना स्वाभाविक है, इसमें कोई द राय नहीं हो सकती । मैं ट्रासपोर्ट मिनिस्टर के नोटिस में अपने यहाँ की क्षेत्रीय समस्या लाना चाहता हूँ । हमारे यहाँ का जो सव-डिपो है वह बहुत छोटा सा है और वह म्युनिसिपल कमेटी की जमीन पर है । म्युनिसिपल कमेटी चालीस पैसा प्रति बस के हिसाब से चार्ज करती है लेकिन फिर भी लोगों को कोई सुविधा नहीं हूँ । बैठने के लिए भी कोई स्थान नहीं है । ड्राइवरो और कंडक्टरों के लिए कोई सुविधाजनक जगह नहीं है । खुले में बसे खड़ी होती हैं और म्युनिसिपल कमेटी ने वहाँ पर खुले में खोके खड़े कर दिए हैं और वे खोके म्युनिसिपल कमेटी का आय का साधन हैं । म्युनिसिपल कमेटी वहाँ पर कोई इन्वैस्टमेंट नहीं करना चाहती । इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी बस-स्टैंड बनाया जाए । बस-मटैंड के लिए जमीन सिलेक्ट हो चुकी है ऐक्वायर भी हो चुकी है । उसकी जल्दी से जल्दी सरकार को पेमेंट करनी चाहिए । आज हर जगह लैंड की कीमत बढ़ रही है इसलिए जल्दी ही पेमेंट करके बस-स्टैंड बनाने का कार्य आरम्भ कर देना चाहिए क्योंकि पलवल ऐसी जगह है जहाँ से यू० पी० को, दिल्ली को और बल्लभगढ़ तथा कई दूसरी जगहों को बसें जाती हैं इसलिए वहाँ पर बस-स्टैंड होना निहायत जरूरी है । बड़े संतोष की बात है कि साठ प्रतिशत गांव पक्की सड़कों से मिला दिए हैं और अब जो सड़कों का काम स्लो-डाउन किया गया है वह भी स्टेट के इन्ट्रस्ट में किया गया है । सरकार ने सड़कों से ज्यादा इर्म्पोटैस

पानी को दी है । नहरों में पैसा इन्वैस्ट किया जा रहा है लेकिन फिर भी कई सड़कें ऐसी होती हैं जो जनता के हित में होती हैं उनका बनाया जाना बहुत जरूरी है । हमारे यहां पलबल से घोड़ी की एक सड़क एं । वह सड़क आधे से ज्यादा बन चुकी है केवल एक लाड को इन्वैस्टमेंट के लिए वह सारी सड़क अधूरी पड़ी है इस सड़क के बन जाने से पांच छह गांवों को फायदा पहुंचता है । वह पुरानी सड़क है इसलिए उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाये ताकि वहां सड़क परिवहन का काम हो सके । एक सड़क कलुआका से दुर्घटना की सड़क है यह सड़क अस्सी प्रतिशत कंडीशन पूरी करती है । पता नहीं यह क्यों पूरी नहीं हो रही है?

शिक्षा के विषय में शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि को स्कूल अपग्रेड नहीं होगा यह कोई सन्तोषजनक बात नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि किसी स्कूल को अपग्रेड करने का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कई ऐसे स्कूलों को अपग्रेड कर दिया है जिनमें विल्डिंग नहीं हैं, लड़के नहीं हैं उनको तो अपग्रेड कर दिया है लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो सारी कंडीशन को पूरा करते हैं लेकिन गवर्नमेंट की पालिसी के कारण उनको अपग्रेड नहीं किया गया है । क्राइटेरिया तो यह होना चाहिये कि जो सारी कंडीशन पूरी करें उनको अपग्रेड किया जाए और जो कंडीशनुज पूरी न करें उनको न किया जाए । एक गवर्नमेव हाई स्कूल अलावलपुर में है और एक लडकियों का हाई स्कूल पलवल कैम्प में इन दोनों की बिल्डिंगजु को दो-दो साल

से पी 0 डब्ल्यू 0डी 0 विभाग ने अनसर्विसेवल करार किया हुआ सै ऊपर से सफेदी आदि कराकर उसको ठीक शो किया जाता है लेकिन अन्दर से बिल्डिंग की हालत खस्ता है । सर्दी में हवा आती है, बारिश से कोई बचाव नहीं है । इसलिए जिन बिल्डिंगों को महकमा ने अनसर्विसेवल बल करार दिया हुआ है कम से कम उन बिल्डिंगों को अवश्य ही पूरा किया जाए ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा ने काफी प्रगति की है लेकिन हम तो असली प्रगति तब समझें जब पलवल का अस्पताल बने वह अस्पताल तीन साल से मंजूर पड़ा है लेकिन धनाभाव में वह बिल्डिंग स्थगित कर दी गई है जबकि उस समय के स्वास्थ्य मन्त्री उसका शिलान्यास भी कर आए और उन्होंने वहां की जनता को एक साल के बाद उसके उदघाटन का भी आश्वासन दिया था । तीन साल से उसकी बाउन्डरी भी वनी हुई है लेकिन बिल्डिंग को धनाभाव के कारण नहीं बनाया जा रहा है । आज जमीन की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं । कम से कम उस जमीन का पैसा तो दे दिया जाए और इमारत आरम्भ कर दी जाये । वहां पर बहुत सारी इंटें थीं जिनको कि लोग उठा भी ले गए हैं अगर उस जमीन के मालिकों को पैसा दे दिया जाए तो लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि वह अस्पताल वहीं बनेगा । कहीं ऐसा न हो कि फाउंडेशन स्टोन को किसी दूसरी जगह ले जाए । पहले वहा पर एक क्रिश्चियन अस्पताल था लेकिन जब से वह बंद हुआ है लोगों को काफी असुविधा हो गई है इसलिए वहां पर अस्पताल

का होना बहुत जरूरी है । जब भी कोई मंत्री पलवल जाते हैं तो वहां के लोगों की सबसे पहली डिमान्ड अस्पताल की होती है । वह डिमान्ड धनाभाव के कारण स्थगित कर दी जाए यह कोई अच्छी बात नहीं है । स्वास्थ्य जो है उसके लिए धन का अभाव कोई अच्छी बात नहीं है । एक नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य है कि निरोग रहे, अगर कभी बीमार हो जाएं तो मैडीकल सुविधाएं पूरी तरह उसको मिल सकें । इसी से देश उन्नति की तरफ चल सकता है । इस क्षेत्र में कटौती करना कोई अच्छी बात नहीं है और किसी में चाहे कटौती कर दी जाए लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमी नहीं करनी चाहिए ।

अब मैं सिवरेज सिस्टम यानी पब्लिक हैल्थ पर आता हूँ । पलवल म्युनिसिपल कमिटी ने सिवरेज सिस्टम के लिए 24- 8- 1971 को 5 9 लाख रुपए की एक स्कीम बनाकर गवर्नमेंट को भेजी और बाद में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने 6- 4- 1973 को 84 लाख रुपए का उस स्कीम का एस्टीमेट बनाकर म्युनिसिपल कमिटी को भेजा और म्युनिसिपल कमिटी ने 28- 6- 1973 को उस 84 लाख रुपए के एस्टीमेट को एप्रूव कर दिया और गवर्नमेंट को दस लाख रुपए का लोन और 15 लाख रुपए की ग्रांट के लिए लिखा लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है । परसों मेरी सप्लीमेंटरी के जवाब में बताया गया कि पलवल वाले तो सिवरेज चाहते ही नहीं हैं क्योंकि उन्होंने तो लिखा ही नहीं है, पता नहीं उन्होंने ऐसा किस आधार पर कहा जबकि उपरोक्त हवाला इस बात

का सबूत है कि पलवल वालों के इस विषय में कितनी रुची है । चेयरमैन साहब, यह जो सारा सीवरेज का सिस्टम है, इसके लिये प्रायरिटी दी जानी चाहिये । पलवल में एक रिजरवायर बना हुआ है लेकिन उस में पानी भरने का कोई इन्तजाम नहीं है और जो वहां पर लाखों रुपया खर्च हुआ पड़ है

उसका उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसको भरने का कोई इन्तजाम न हो । तो इस तरफ सरकार को जल्दी ही ध्यान देना चाहिये । इसके साथ ही यहां पर पुलिस की भी चर्चा हुई । आजकल चोर उचक्के इतनी तेजी से कारों में चलते हैं और हमारी पुलिस के पास केवल साइकिल होते हैं तो आप ही देखिए कि कारों में सवार और साइकिलों पर सवार का क्या मुकाबला? इसकी रोकथाम के लिये जिससे कि चोर को जल्दी पकड़ा जा सके, हर स्टेशन पर जीप होनी चाहिये डी ० एस ० पी ० हैंड क्वार्टर पर तो ये दे रखीं हैं । इसके साथ –साथ मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार कुछ स्टेशनों पर वायरलैस सैट भी दे रखे हैं, उसी प्रकार हर स्टेशन पर यह वायरलैस सैट सप्लाय किये जाने चाहिये ताकि चोरों को, कातिलों को शधि से शोध इतलाह देकर पकड़ा जा सके । थोड़े दिन की बात है कि रेवाड़ी के निकट तावडु, धारूहेडा इत्यादि कई स्थानों पर डाका डाल कर भागने में सफल हुए । इस घटना को इतला तुरन्त वायरलैस द्वारा सब पुलिस स्टेशनों को दी गयी । और पलवल के पास सभी को हथियारों समेत पकड़ लिया गया था, यह सारा काम वायरलैस सैट

के हारा ही हुआ । इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि क्राइमज वगैरह को कम करने के लिये हर पुलिस स्टेशन पर वायरलैस सैट सप्लाई किये जाए, इस से पुलिस को बहुत सहायता मिल सकती है । इससे आगे चौयरमैन साहब, मैं पुलिस को दी जाने वाली वर्दियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । हमारी पुलिस के पास वही वर्दियां वे, जो वर्दियां हमारी जब स्कूलों में पढ़ते थे तो उस वक्त देखा करते थे । पहले वक्तों में तो लोगों को खाने को घी मिलता था, दूध मिलता था, और वे पहलवानों की तरह दिखाई देखे थे, ऐसे-ऐसे जवान उस वक्त पुलिस में हुआ करते थे लेकिन आज वैसा नहीं है ओर वही पुरानी तरह की निक्कर बेचारे पहने हुए होते हैं, उनकी पतली टांगो से ही उसकी पहलवानी नजर आ जाती है । मेरा यह सुझाव है कि गवर्नमेंट उनको इन निक्करों की बजाये पैन्टस सप्लाई करे क्योंकि निक्सरो के पहनने के बारे वे बेचारे अपनी टांगों पर लम्बी-लम्बी पट्टियां बांधते हैं तो इस से सरकार के खचे में कोई कमी नहीं होती है । अतः उन्हें पैन्ट्स वगैरह सप्लाई की जाए ताकि उन बेचारों की पहलवानी भी छुप जाए और हमारी पुलिस को शान भी बड़ जाए । इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो अपने अभिभाषणो में गवर्नमेंट सर्वेन्टस को इनटैरिम रिलीफ देने का आश्वासन दिया है, तो इन आश्वासनों को दे देने से ही बात नहीं बनती, एक तरफ तो हम अपने गवर्नमेंट सर्वेन्टस की तारीफ करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं किया, जैसा कि हमारी पड़ोसी सरकार के कर्मचारियों

ने किया है, इन्होंने कितनी स्वामीभक्ति दिखाई है, हमारे कर्मचारी कितना पीसफुली काम करते हैं? तो इस लिए उन्हें इन्टैरिम रिलीफ भी मिलनी चाहिये, लेकिन सिर्फ आश्वासनों से बात नहीं बनती । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह जो आश्वासन उन्होंने कर्मचारियों को दिया है, उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए ताकि जिन अफसरों की, जिन कर्मचारियों की बड़ाई करते है उन्हे इस बड़ाई के अनुरूप कोई इन्टैरिम रिलीफ भी मिलनी चाहिये । इसलिये मैं सरकार से इस बारे मे पुरजोर अपील करता हूं कि सरकार इस बारे में जल्द से जल्द अनाउसमैन्ट करे । इन शब्दों के साथ मैं सभापति जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां कुछ कहने का मौका दिया ।

लाला रूलिया राम : चेयरमैन साहव, मेरा प्यायट आफ आर्डर है । अर्ज यह है कि बजट पर हर आदमी ने बोलना है, परसो भी यह डिसकशन होती रही है कि हरेक को 15 या 20 मिनट बोलने के लिये दिये जाएंगे ।

श्री सभापति : आप गर्वनर एड्रेस पर बोल चुके हैं ।

लाला रूलिया राम : ठीक है, गर्वनर एड्रेस एक चीज है, बजट पर बोलना दूसरी बात है ।

एक आवाज : आपको उनको टाईम देना चाहिये जिनको पहले टाईम नहीं दिया

लाला रुलिया राम : चेयरमैन साहब, अगर उनको टाइम मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिये?

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : चेयरमैन साहब, ये तो इन्डीपेंडैन्टस में हैं, न यह कांग्रेस में हैं, न अपोजीशन में हैं, इनकी गिनती कहां आती है? इ सका तो कोई हिसाब ही नहीं है ।

श्री राम धारी गौड़ (गोहाना) : माननीय सभापति जी, इस सदन के सामने सन् 1974-75 का बजट पेश है । इस पर बहुत से साहिबान ने अपने ख्यालात का इजहार किया है । एक अच्छे बजट की यह खूबी होती है कि उस में कितनी रकम विकास के लिये रखी गई है, कितनी भलाई के लिये रखी गई है । क्योंकि जितनी ज्यादा रकम विकास के कामों के लिये रखी होती है, उस से उतना ही अधिक विकास ज्यादा होता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, वही अच्छा बजट कहा जाता है । ऐसे बजट को बैलेन्सड बजट कहते है क्योंकि उस से सरकार की और आमदनी बढ़ती है । ऐसे बजट से और आय आयेगी, उससे टैक्स आएंगे, गवर्नमेंट खुशहाल होगी । आप जानते हैं कि हरियाणा में 82 परसेन्ट आदमी खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं उनका गुजारा तो केवल खेतीबाड़ी पर चलता है, और इसके इलावा 18 परसेन्ट आदमी हैं उनको अगर खाने को नहीं मिलेगा तो उनका भी काम नहीं चल सकेगा । तो आप देखिये कि इस बजट में कितना पैसा खेतीबाड़ी की डिवैल्पमेंट के लिये रखा गया है । कुछ

अच्छी-अच्छी योजनाएं हैं आप देखेंगे कि अच्छी खेती करने के लिये तीन चार फैक्टर्स होते हैं, सब से पहले भूमि, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद अच्छे बीज, अच्छी खाद और पानी वगैरह । (इस समय उपाध्यक्षा विराजमान हुई) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप अच्छी प्रकार जानती हैं कि इस समय हरियाणा के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद में ऐसी भूमि है, जिस में सेम हो गई है या होने वाली है, कम से कम 8 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो सेम के कारण नाकारा बन चुकी है और 8 लाख एकड़ भूमि ही ऐसी है जिसको बीमारी लग चुकी है और जिसको सेम होने का खतरा है लेकिन वह नाकारा नहीं हुई है क्योंकि सरकार ने उस तरफ ध्यान रखा है, उसको रिक्लेम करने के लिये जो सरकार ने पैसा रखा है, वह अभी थोड़ा हूँ । इस बात के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूँ । जिस आदमी के पास 5- 8 किल्ले भूमि होगी, अगर उसमें सेम होगी तो वह कहां से गुजारा चलाएगा । इसलिये इस की रोकथाम के लिये सरकार को और पैसे की प्रोवीजन करनी चाहिये लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि फिर भी सरकार ने इस तरफ काफी कदम उठाये हैं । मुझे उम्मीद है कि इस काम के लिये अगले बजट में इससे ज्यादा रकम रखी जाएगी । इसके अलावा खेतीवाडी के लिये इस बजट में 5 करोड़ 55 लाख 66 हजार रुपया रखा गया है, इससे अच्छे बीज आएं, खाद आएगी और आप जानती हैं कि इससे अच्छे पौधे लग सकते हैं खेती- बाड़ी हो सकती है । आप जानती हैं कि कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जोकि खेती बाड़ी को नष्ट कर देते हैं, इसके लिये भी बजट में

प्रोवीजन रखी गई है, जिस से कि कीटाणुओं से बचाव के लिये दवाइया खरीदी जाएंगी । जब तक हम खेतीबाड़ी की हिफाजत नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उस समय तक हम बीमारियों से नहीं बचा सकेंगे चाहे कितने ही अच्छे बीज क्यों न डालें, तब तक अच्छी खेती नहीं हो सकती । मुझे तो खुशी है कि इसमें बीमारी नाशक दवाइयो के लिये प्रोविजन किया गया है । इसके अलावा इसमें एक हार्ड पावर कैनल एरिया डिवैल्पमेंट अथोरिटी संस्था कायम की गई हूँ उसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता है कि लोगों ने बहुत मंहगे भाव पर, अपना पेट काट कर ट्रैक्टर खरीदे । लेकिन देहातो में हालत ऐसी है कि वे आदमी बेचारे पैसे की कमी के कारण उन ट्रैक्टर को चलाने के लिये ड्राइवर नहीं रख सकते । वे खुद चलाने लग जाते हैं । क्योंकि उनको ट्रैक्टर चलाने का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता इसलिये ट्रैक्टर जल्दी खराब हो जाते हैं । खराब हो जाने की बजह से उनका सारा काम बन्द हो जाता है और कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि किसान ट्रैक्टर की किश्तें भी नहीं दे पाते हैं । क्योंकि उनकी आमदनी कम होती है । तो बस चीज के लिये भी इसमें प्रोवीजन रखा गया है कि लोगों को ट्रैक्टरों की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे अपने ट्रैक्टर को ठीक रख सकें । एक बड़े दुख की बात है कि किसानों को जो डीजल दिया जाता है वह शुद्ध नहीं होता । अब कैरोसीन आयल की कीमतें बढ़ने से तो यह शिकायत कुछ कम हुई है लेकिन पहले क्या होता था कि पेट्रोल पम्प वाले किसानों को डीजल में

कैरोसीन आयल मिला कर दे देते थे जिससे कि उनके ट्रैक्टर जल्दी खराब हो जाते थे । मैं चाहूंगा कि सरकार अपने पम्प लगाए और वहां से किसानों को शुद्ध डीजल सप्लाई किया जाए । दूसरी बात पानी की है पानी के बारे में यहां गुप्ता जी ने बड़ी विस्तारपूर्वक बातें बताई कि हरियाणा बनने से पहले यहां पानी की क्या हालत थी । जमुना का पानी आता था, या भाखड़ा का पानी आता था, इसके अलावा और कोई प्रबन्ध नहीं था । पानी की कमी की बजह से हमारी खेती कामयाब नहीं रहती थी । लेकिन जब से हरियाणा बना मौजूदा सरकार ने एक ही बात को भांपा है कि यह प्रान्त तभी खुशहाल हो सकता है जब यहां के जमींदारों को काफी मात्रा में पानी दिया जाएगा ताकि वह अपनी खेती पूरी कर सकें और उसे कोई दिक्कत न पेश आए । अब से पहले यह होता था कि जिस इलाके में ज्यादा नुमांयदगी आ गई वहां पानी पहुंच जाता था बाकी इलाके खाली रहते थे । इस मौजूदा सरकार ने यह नहीं किया कि बंटवारा किया जाए बल्कि इसने नया पानी पैदा किया । रावी ब्यास का पानी मिलने से पहले आपको पता होगा कि आगुमेंटेशन कैनल बनी । पहले पानी जमीन के नीचे था जो किसी काम नहीं आता था । उस पानी को ट्यूबवैलों के जरिये पक्की नहरों में डाला गया । तो इससे उन जमीनों को फायदा हुआ है जो सेम की जूद में आ जाती थी और दूसरी ओर ट्यूबवैलो द्वारा जो पानी निकाला जाता है वह उन इलाकों को भेजा गया जहां लोग पानी को तरसते थे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि हमारी पुरानी नहर जिसको

ओल्ड जमुना कैनल कहते हैं अब आगुमेंटेशन कैनल बनने के बाद वह खाली कर दी गई, उसमें हम पानी नहीं छोड़ते हैं लेकिन फिर भी पांच सौ क्यूसिक पानी उस नहर में आ गया है । वह कैसे आया? बहुत सालों से आस पास के इलाको में पानी फैला हुआ था । जब वह नहर खाली हो गई तो वह पानी उसमें आना शुरू हो गया । इस प्रकार पांच सौ क्यूसिक पानी तो ट्यूबवैलों की वजह से बढ़ा, पांच सौ क्यूसिक पानी रेनोवेशन में आ गया है और उम्मीद है कि पांच सौ क्यूसिक पानी की बचत हो जाएगी । जैसे मैंने बताया कि सेम रक बहुत बड़ी प्रोब्लम थी तो इन पक्की नहरों के होने में वह प्रोब्लम खत्म हो जाएगी । पहले जिन इलाकों में पीने का पानी नहीं मिलता था आज वहां पीने का पानी तो क्या सिचाई के लिये भी पानी पहुंच गया है । तो आप ही बताएं कि इससे ज्यादा खुशहाली और क्या हो सकती है? मैंने बजट को देखा है इसमें सभी इलाकों के बारे में ध्यान रखा गया लूँ लेकिन पहले यह होता था कि बजट में किसी इलाके की बात आ जाती थी और किसी की नहीं आती थी यानी उनको वंचित रखा दिया जाता था । समाजवाद का मतलब यही है कि एक आदमी का पेट न भरे बल्कि सब में बांटा जाए । सो इस बजट में यह प्रोवीजन रखा गया है कि तमाम इलाके खुशहाल हों । यह समाजवादी बजट है । क्योंकि आप देखें कि इसमें किसी इलाके को भी नहीं छोड़ा गया जिसके लिये पैसे न रखे गये हों । यह भाई बिजली बोर्ड की बात करते थे । लॉकैन ये यह नहीं देखते कि प्रान्त में पहले जहां केवल 29,000 ट्यूबवैल थे अब वहां

129000 ट्यूबवैल है जो बिजली में चलते हैं । आप बताएं कि इन ट्यूबवैलों से जो पानी आता है वह कहा जाता है? यह पानी जमींदारों के खेतों में पहुंचेगा जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी, ने खुशहाल होंगे और सरकार को भी टैक्स आयेगा । मगर हम कहीं पर पैसा खर्च करते हैं तो उससे आमदनी जरूर होती है । उसमें सरकार को भी फायदा होता है और जनता को भी फायदा होता है । इसके अलावा इन्होंने कहा कि बिजली का ठीक इंतजाम नहीं किया गया जेनरेट करने का । मैं इनको बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में 60-60 मैगावाट के दो यूनिट लग रहे हैं । और इसी प्रकार से पानीपत में 110- 110 मैगावाट के दो यूनिट लग रहे हैं । इस वास्ते कि बिजली गांव-गांव में पहुंचा दे । हमारे बिजली बोर्ड के पास काफी साधन नहीं थे । 9 करोड़ रुपया तो बिजली बोर्ड ने एक दो साल में लगाया और 13 करोड़ रुपया सरकार ने उसको लोन दिया है । बिजली बोर्ड के कुछ तो अपने साधन हैं और कुछ इसको लोन मिल जाएगा । लोन मिलने के बाद फरीदाबाद और पानीपत के दोनों यूनिट चालू हो जाएंगे तो जमींदारों को काफी मात्रा में बिजली मिलेगी और ज्यादा ट्यूबवैलों का विस्तार होगा तथा खेती भी ज्यादा होगी इन सब से प्रदेश में खुशहाली आएगी । यह बिजली गांव-गांव में पहुंच जाए, सरकार सिर्फ इतना ही काम नहीं करेगी बल्कि उससे आगे भी इंतजाम किया जाएगा । अकेले खम्भे गाड़ने से या तारे' लगाने से मतलब नहीं था बल्कि बिजली पहुंचाने का मकसद था । हमने थर्मल प्लांटस भी लगाए लेकिन थर्मल प्लांटस से जो हमें बिजली मिलती

है वह मंहगी पड़ती है । और जो पानी से बिजली पैदा की जाती है वह सस्ती पड़ती है । लेकिन हमारे यहां कोई ऐसा फौल नहीं है जिससे कि ऊंचाई से पानी पड़ता हो । लेकिन ताजेवाला से लेकर दादुपुर तक तीन फाल बन सकते हैं जो डेढ़ सौ फुट तक के हो सकते हैं । उसके लिये भी योजना बना रहे हैं कि वहां जैनरेटर लगा कर 45 मैगावाट बिजली वहां से भी पैदा की जाएगी । उसको भी हमारे नहीं छोड़ा कि यह जाया न चली जाए । हमारे पास एक साधन था जहां से कि हम पानी से बिजली पैदा कर सकें....

17.00 बजे

श्री अमर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर मेडम । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि इस वक्त जो आनरेबल मेंबर साहिब हाऊस में बोल रहे हैं उन्हो लाईनज पर और एक्चुअली यही वर्डिंग थी जब वे गवर्नर के एड्रैस पर बोले थे । सारी उसी चीज को ही वे फिर से यहां पर रिपीट कर रहे हैं । इस लिए अगर उन के पास कोई ओर नई बात कहन को नहीं है तो आप उनको बैठा कर किसी और मेंबर को समय दे ।

Deputy Speaker : I will just see. It is my duty.

श्री रामधारी गौड़ : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि मैंने बताया था ड्राई फारमिंग के लिए गवर्नर के एड्रैस में कोई बात नहीं थी लेकिन बजट के अन्दर इस के विकास के लिए कुछ

रुपया रखा है । यह भी बहुत अच्छा कदम है । इस से जहां पर पानी कम है वहां के लिए लोगों को खेती करने में सुविधाएं मिलेगी और उनका उत्पादन बढ़ेगा और वहां पर अच्छी फसलें पैदा हो सकेंगी । इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा यहां पर इस बात की बहुत नुक्ताचीनी की गई कि हमारी स्टेट में बसों की बहुत कमी है और बसें ओवरलोड चलती हैं । लेकिन जैसा कि पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी एक दिन बताया था कि बसें 'अच्छी कम्पनी की तरफ' से उतनी नहीं मिल रही जितनी कि हमें जरूरत है वरना गवर्नमेंट चाहती है कि बसें और बढ़ाई जाएं ।

अब मैं कोआप्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । इस के बारे में आमतौर लोग यह कहते हैं कि यह कुर्रप्शन का डिपार्टमेंट बन गया है । कोआप्रेशन दरसल एक मूवमेंट और भावना थी लेकिन उसके बाद यह महकमा बन गया है यह तरह से सहकारिता आंदोलन था जिस की भावना यह थी कि लोगों का दिमाग ऐसा बनाया जाए जिस से वे मिलजुल कर काम करें और जो चीज पैदा करें उस को आपस में बांट कर खाएं । लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर कोआप्रेशन का जो महकमा है उस में नानकेआप्रेशन प्रवेश कर गई है । इस में ऐसा हो रहा है जिस किसी के हाथ में कोई काम आ जाता है वह उस को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका हलवा माडापूरा नहीं हो जाता है और महकमे के कर्मचारियों का भी उस हाथ होता हूँ । एक दो

आदमी जो चलते पुर्जे होते हैं वे मिलजुल कर साजिश के साथ ताकत में आ जाते हैं और किसी संस्था को जब अपने हाथ में ले लेते हैं तो उस में किसी दूसरे को आने नहीं देते और उस में बिलकुल धांधली चलती है । मैंने गोहाना मे देखा सै, वहां पर दो तीन आदमी ऐसे है जो महकमें के कर्मचारियों से मिलकर वहां चुनाव नहीं होने देते । अक्वल तो किसी की हिम्मत ही नही पड़ती कि उन के मुकाबले में खड़ा हो सके । अगर कोई खड़ा होने का ईरादा बनाता है तो इन्सपैक्टर उसकी रोक देते हैं, उसको डराया जाता है कि अगर तुम फुला आदमी के खिलाफ खड़े होंगे तो हम तुम को सीधा कर देंगे । नतीजा यह होता है की वह बेचारा डर कर बैठ जाता है क्योंकि उसने भी लोन वगैरा लेने होते है । वहां सेंट्रल कोआप्रेटिव बैंक का इलैक्शन होना था । उस में क्या हुआ कि जो प्रोसिडिंग बुक थी उस में कार्यवाही जैसा रैजोल्यूशन वे तीन आदमी चाहते थे उसके मुताबिक हो गई । ऐसा करने के बाद वह कार्यवाही कमेटी उन तीनों आदमियों के पास पहुंची । तो आप ही बताएं कि जहां पर कार्यवाही कमेटी ही उनके पास पहुंच जाए तो फिर बाकी कौन खड़ा हो सकता ते? जहां पर ऐसी बाते हों वहां पर लोगों को फायदा कैसे पहुंचेगा? सहकारिता का तो मतलब यह है कि सब का सहयोग ले कर काम चले, यह नहीं कि चन्द चलते पुर्जे आदमी हावी हो जाएं और किसी आदमी को नजदीक न फटकने दें । गोहाने में सोसायटी का एक चौयरमैन था, जहा पर गोदाम के लिए जमीन खरीदनी थी तो गोहाने से एक सवा मील फासले पर जा कर जमीन खरीदी गई और उस की

कीमत तो 24 हजार फी एकड़ की अदा की गई लेकिन कागजात में 40 हजार रुपया लिखवाया गया हांलाकि वहां पर अब भी 20 हजार रुपए फी एकड़ के हिसाब से जमीन मिल सकती है लोगों ने काफी शोर मचाया लेकिन कुछ नहीं बना । उसने मिलजुल कर सारे मामले को ठप्प करवा दिया था । जहां ऐसी बातें हों वहां किस की हिम्मत पड़ेगी कि उन के खिलाफ कोई बात कर सके? तो मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा यह कहूंगा कि इस कौआप्रेटिव के महकमें को ठीक ढंग से चलाया जाए, अगर इस का ठीक इन्तजाम हो दो उस से समाजवाद आएगा । अगर हम कोई चीज इकट्ठे हो कर पैदा करें और उस का बंटवारा ठीक करें तो उस से लोगों को फायदा हो सकता है वर्ना नहीं हो सकता । जितनी पैदावार हो वह एक ही जगह रहे और उसकी खपत एक पर हो जाए तो उस से लोगों में खुशहाली नहीं आ सकती । खुश हाली तभी आ सकती है जब बटवारा मसावी हो । अगर यह महकमा ठीक और से काम करे तो यह प्रान्त की खुशहाली मैं बहुत बडा पार्ट प्ले कर सकता है लेकिन मौजूदा ढंग से जैसे यह चल रहा है 'उर्स से कोई फायदा नहीं है बल्कि उससे लोगो निराशा फैल रही है और धड़ेबंदी होती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा मेरे कुछ साथी उतावले हो रहे हैं और वे बोलना चाहते हैं । खैर उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए है मैं कई बातें और कहना चाहता था लेकिन हमारे गुप्ता जी ने बहुत बाते कह ली हैं । इस लिए मैं और ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ इतना ही कहता हूं कि बजट बहुत बैलैसड और इस के अन्दर उन्नति की झलक दिखाई देती है ।

तौ ऐसा अच्छा बजट पेश करने के लिए मैं अपने वित्त मंजे साहब को बधाई देता हूँ किन्होने इतना बढिया बजट पेश किया । अन्त में मैं उनको एक बार किर बधाई दे कर बैठता हूँ ।

चौधरी चांद राम (बबैन एस० सी०) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं क्षमा चाहूंगा क्योकि मेरा गला कुछ बैठा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि मुझे आप बोलने के लिये समय अच्छा देंगी । क्योकि अभी मेरे मोहतरिम दोस्त जो मंत्री हैं और अध्यक्ष पद पर भी रहे है उन्होंने भी कहा कि मेरे भाई काफी देर से बोले नहीं हैं और अब अगर बोले तो जिम्मेदारी से बोलें । वह इल्जाम भी लगाते रहे और उन लोगो पर भी इल्जाम लगाते रहे जिन्होने उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही थी । खैर उन्होंने एक बात शुरू कर दी लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इतने शानदार सत्याग्रह और आन्दोलन के बाद जो 113 दिन तक चला जो सदभावना बनी उसके बारे मे कोई बात कही जाये । मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारत में पहला ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें एक पैसे की भी सरकारी या गैर-सरकारी प्रापटी को कोई नुकसान नहीं हुआ । यह हरिजनों का मैं समझता हूँ सारे हिन्दुस्तान में पहल प्रोटैस्ट था, नाराजगी थी और अगर मैं इसे ऐतिहासिक कान्ति कहूँ तो मैं मुवालागा नहीं करूंगा । मैं समझता था कि हरियाणा गवर्नमैट के चीफ मिनिस्टर ने एक सद भावना का ब्यान दिया है और मैंने भी उस व्यान को माना है और प्रधान मन्त्री जी की विसातत से, गृह मंत्री दोक्षित जी को विसातत से, राज्य मन्त्री मिर्धा जी की

विसातत से, हमारे जो भाई पार्लियामेंट के मैम्बर सरदार बूटा सिंह हैं देनकी विसातत से और श्री बी 0 एस 0 मूर्ति जी, जो पहले राज्य मती होरे थे उनको मदद से यह सत्याग्रह समाप्त हुआ । सदभावना की दृष्टि मे मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी नही बोला और मैंने कोई ब्यान भी नहीं दिया लेकिन 13 तारीख को हांसी में एक जलसा हुआ जिसका इन्होंने जिकर किया कि वहां पर चंदे का सवाल आया या और कुछ आया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जांच करवायें कि एक ही जगह पर पहले हमारी संघर्ष समिति के जो आदमी थे उनको इजाजत दे दी लाउड स्पीकर लगाकर जलसा करने की और वह प्राइवेट जमीन थी । फिर एक दूसरे आदमी को इजाजत दे दी जिसके साथ तीन आदमी है एक वह वकील, एक उसका मुन्शी और एक वह खुद । दोनों लाउड स्पीकर वहां पर लगवा दिये । मौ जाने से पहले वहां झगड़ा हुआ उसका मुझे पता नहीं । मेरे से पहले इस हाउस के मुआजिज मैम्बर चौधरी अमर सिंह उस जलसा को प्रीजाइड कर रहे थे और मेरे साथ ही चौधरी पीर चंद भी मौजूद थे । मेरे जाने से पहले झगड़ा भी बताते हैं कि हुआ, जिसका मुझे पता नहीं लेकिन फिर भी मैंने अपील की कि 10/15 हजार आदमी हैं जो यहां आये हैं, इनके नाम से ही शान्ति करो मैंने पुलिस को भी अपील की डी 0 एस 0 पी 0 वहां दर मौजूद थे, इन्सपैक्टर वहा पर मौजूद था, मैंने कहा कि जब कोई मीटिंग हो रही हो, प्रजातंत्र में, तो आपका फर्ज है कि कोई आदमी अगर उसमें विध्न डालता है तो आप कम से कम इसी दृष्टि से उसे कन्ट्रोल कर लीजिये कि

कल को मिनिस्टर्ज के भी जलसे होने हैं, कल को सरकार के जलसे भी होने है । मैं कभी भी किसी को भी मीटिंग में विधन डालने की शिक्षा नहीं देता हूं और न विधन डालने का आदी हूं । लेकिन फिर वहा अगर पुलिस ने हमारी मदद की तो कब की? उस आदमी को लोगों ने कहा कि भाई चले जाओ जलसा होने दो । यह क्या कम बात है कि लोग ऐसा कहते है कि ऐसा न करो । डिप्टी स्पीकर साहिबा, साढे सात हजार रुपये की मेरे गले मे नोटों की मालाये डाली । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाजरी वहां थी । किसी गांव से पचास की और किसी गांव से सौ की इस हिसाब से मालायें आई । जब थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसमें बीसियों आदमियों को चोटें आई । न उनके हाथ मे कोई लाठी थी न कोई और चीज थी ऐसे ही पीट डाला निहथे लोगों को । किस के साथ मुकावला था? दो तीन आदमियों के साथ । क्या दो या तीन आदमी गडबड़ फैला सकते है इतने बड़े जलसे में क्या पुलिस इन्तजाम नही कर सकती थी और क्या ऐसा वक्त आ गया है कि हमको गैंग किया जायेगा और हमें बोलने नही दिया जायेगा? इस हाउस में इल्जाम लगाया जाता है कि भाई चांद राम कांग्रेस में आना चाहता है और इस हाउस में यह इल्जाम लगाया जाता है कि चांद राम अपोजीशन में हरिजनों को उकसाता है । मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं । यह देख कर मुझे एक शेर याद आता है कि:

न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की

घुट के मर जाऊं यही मजी है मेरे सैयाद की ।

आज हरिजनों की यह हालत हो गई है । क्या आज कांग्रेस को यह मालूम नहीं कि आज बम्बई में क्या चुनाव का नतीजा निकला है? वहां दलितों ने वोट नहीं दिया दलितों ने पग बाइकाट किया । कांग्रेस है क्या हरिजनों के बगैर? आप ताकत के नशे में घमंड करते हैं और कहते हैं कि जाने दो हरिजनों को 12 मैम्बरी कमेटी बनाई डिप्टी स्पीकर साहिबा... ।

Deputy Speaker : Chaudhri Chand Rain, you should not forget that you are speaking on the Budget.

चौधरी चांद राम : मैं वजट पर ही बोल रहा हूं और यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं । तो मैं अर्ज कर रहा था कि 12 मैम्बरी कमेटी बनी जिसका हमारे हाउस में ऐलान हुआ अभी जनवरी में जब श्री मिर्धा साहिद यहां पर मौजूद थे तो मैं उन से मिला और मैंने कहा कि कमेटी का ऐलान करवा दीजिये क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई कड़वाहट पैदा करूं । मिर्धा साहब ने कहा था कि भाई कमेटी जरूर बनेगी और कोई सैंटर का आदमी, पार्लियामेंट का मेंबर उसको हैड करेगा और मैंने कहा ऐसा करा दीजिये । प्राईम मिनिस्टर सैत्रोटोरिएट से भी मुझे यह आश्वासन आया कि आप से सलाह करके कमेटी बनेगी । मैं नहीं चाहता था कि मैं उस कमेटी में शामिल होऊं क्योंकि मैं तो कम्मलेनैट था, शिकायत कुनिन्दा था । हमारी संघर्ष समिति का

भी कोई आदमी उस कमेटी में नहीं जाना चाहता था । हम तो उस में गवर्नबेट के सामने कुछ फ़ैक्ट्स रखना चाहते थे । यह अन्दोलन क्या था? बड़ा मामूली था और यह आंदोलन ऐसा था कि जिस में जमीनों के बारे में और नौकरियों के बारे में और किसी ऐसी बात के बारे में जो हुक्म पिछली कांग्रेस सरकारों के थे चांद राम के नहीं पिछली कांग्रेस सरकारों के जो हुक्म थे वह हुक्म मैंने नकल करके पेश किये थे । चाहे मैंने राड़पति को मैमोरैंडम दिया चाहे स्पीकर साहव को या गृह मंत्री जी को दिया इ स गवर्नमेंट को भेजा या राज्यपाल महोदय को भेजा उस में वह पिछले हुक्म थे । कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी । आज भी वह हुक्म सरकार के सामने हैं । कोई 12 दंबरी कमेटी बनाने को जरूरत नहीं थी बड़ी मामूली बात थी उन हुक्मों को देख लेते और उन हरिजनों को इन्साफ़ देते जिन हरिजनों ने इस सरकार को बनाया बावजूद सोशल बाइकाट के और दूसरी तकलीफों के डर के 2 ह साल तक बनाते रहे । क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि उन हरिजनों को गले लगाते लेकिन आज यह उन हरिजनों पर लाठी चार्ज कराते हैं । मुझे यह भी मालूम हुआ और चाहता हूं कि वह बात गलत होऔर उन्होंने सुबह यह कहा कि तुम ऐसा करना और डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारी लाउड स्पीकर को इजाजत बीच में कैंसल कर दी और इस तरह बीच में कैंसल करने के बाद अगर 10/15 हजार आदमी इधर उधर बदअमनी में फैल जाते हैं इधर उधर जा कर कोई बात करते हैं तो कुछ वर्कर उनको कैसे कन्ट्रोल कर सकते हैं । जब बीच में

इजाजत कैंसिल कर दी तो थानेदार से कहा कि आपने बीच में इजाजत कैसे कैंसिल कर दी और चौधरी पीर चन्द जी थानेदार के पास गए कि बीच में आपने क्यों इजाजत कैंसिल कर दी, अब कोई गड़बड़ नहीं है जलसा चलने दो । आज मेरा गला बैठ रहा है उसकी वजह यह है कि मुझे बगैर लाउड स्पीकर के' बोलना पडा । खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता इस मामले पर बजट पर डिस्कशन है, लेकिन मैं इतना ही कहना षाहता हूँ कि बनारसी दास गुप्ता जी आप मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं उन जैसा आदमी जो इतने जिम्मेदार पद पर है और रहे हैं उनको जिम्मेदारी की बात कहनी चाहिए उन्होने कहा कि चांद राम या कोई और हरिजन संघर्ष समिति का हिसाब किताब नहीं देते । जो चंदा देते है वह कमी हिसाब किताब नही मांगते बिचारे । डेढ़-डेढ़ गज लम्बे इश्तेहार मेरे खिलाफ निकले तो लोगों ने कहा कि चांद राम क्या चांद राम बन गया? इ सके बावजूद भी 20,027 आदमी जेल में गये और सवा लाख के करीब वहां रुपया भेंट हुआ यह क्या कम बात हूँ कि लोग मुझे वहां आकर रुपया भेंट करते थे । मैं किसी हरियाणा के गांव में नही गया देहली छोड़ करके । औरतों ने भी हजारो की तादाद में आदोलन में हिस्सा लिया और चार पांच हजार औरते जेल में गई । 6/7 औरतों के जेल मे बच्चे जन्मे हैं और कुछ आदमियों की मौते भी हुई हैं लेकिन उसके बाद भी हरिजन पीछे नहीं हटते थे । अगर मैं आंदोलन खत्म न करता तो मेरा ख्याल है कि गांव गांव मे यह आंदोलन फैलता लेकिन मंने कहा कोई बात नही

नैशनल इन्ट्रैस्ट की बात है, इस देश में क्राइसिस हैं देश में आर्थिक क्राइसिस हैं और देश को दूसरी चीजों का सामना है तो मैंने नैशनल इन्ट्रैस्ट में कहा कि कोई बात नहीं । मेरे ऊपर इल्जाम लगवाया और जिस भाई ने गड़बड़ करी उस भाई से इलजाम लगवाया सरकार ने पैसे दे करके कि चांद राम ने ट्रेचरी की बै । उसने इलजाम पैसों के हिसाब किताब का नहीं लगाया उस ने यह लगाया कि चांद राम ने अकेले ने फ़ैसला कर दिया । मैंने स्टेट के मुख्य मंत्री के ब्यान पर अगर वह आंदोलन वापिस ले लिया तो इस हकूमत को खुश होना चाहिये था । यह सरकार को खुशी होनी चाहिये थी कि अच्छा किया है और रक चीज जो बिटरनैस फैला रही थी, कड़वापन करवा रही थी वह सुखद वातावरण में बदल जाए लेकिन क्या हुआ कि मेरे खिलाफ इल्जाम लगाए गा! थे । 12 मैबरो की कमेटी बनाई और उनको यह कहा कि साल डेढ़ साल में कमेटी को रिपोर्ट देना तो यह बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी । खैर या तो चीफ मिनिस्टर साहब जाने या सैन्ट्रल सरकार जाने जिनकी वजह से मैंने इस आन्दोलन को खत्म किया । जहां तक मेरे हिसाब का ताल्लुक है, इसके बारे में इस अखबार में सब कुछ दिया है, यह 1953 से चालू है इसमें हिसाब दिया हुआ है, सारे का सारा इसमें छाप दिया हूँ, हरेक गांव का चन्दा छाप दिया है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, कितना चन्दा आया है, कितना नहीं आया यह इस में छाप दिया है अगर कोई भाई हिसाब लेना चाहे वह हिसाब ले सकता है । इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ।

जहां तक सवाल बजट का है, वह हमारे सामने हूँ । यह ऐसा बजट है जो क्राइसिस का बजट है, कंट्राडिक्शन का बजट है, कन्फ्लिक्ट का बजट है और कन्फ्यूजन का बजट है क्राइसिस को तो हमारे मंत्री महोदय ने खुद माना है । उन्होंने कहा है वे कहते हैं बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, मेजर समस्याएं हैं । तो इसका मतलब यह हुआ कि क्राइसिस का बजट है । जिस बजट में 18 करोड़ रुपये का घाटा हो और इसके अन्दर यह भी न बताया जाए कि इसको कवर कैसे किया जाएगा तो यह बजट किस बात का हुआ सैन्ट्रल गवर्नमेंट तो कह सकती है कि हम रिजर्व बैंक से करंसी छापेंगे और भी कई चीजें करेंगे क्योंकि उनके पास बड़े रिसोर्सिज हैं । इस छोटी सी स्टेट में जिसमें करीब-करीब सारे रिसोर्सिज खत्म कर दिए हैं और जो सिर्फ शराब पर डिपेंड करती हो, सेल्ज टैक्स पर डिपेंड करती हो, वह कैसे घाटा पूरा कर सकती है । इसके सबसे बड़े दो रिसोर्सिज हैं - एक सेल्ज टैक्स और एक एक्साईज टैक्स । इस किताब में यह बताया गया है कि किस तरह से हमारी आमदनी अलग-अलग सालों में वटी है । स्टेट एक्साईज ड्यूटी का आमदनी 1967-68 में 6.21 करोड़ थी जो कि हरियाणा का नौरमल इयर था और आज वह आमदनी 15.50 करोड़ रुपया है । यूनियन एक्साईज ड्यूटी 1967-68 में 4.26 करोड़ थी और आज 44 करोड़ है । इसी तरह से सेल्ज टैक्स में 1967-68 में 9.5 करोड़ थी और आज 30 करोड़ है । यह है हमारी आमदनी । जैसे एक मुअजिज अखबार ट्रिव्यून में त्रिखा है कि कितना औबियसली

कंट्राडिक्टरी है इनका कांऊंटिंग का तरीका । उनके कांऊंटिंग में आठ-आठ, सोलह-सोलह करोड़ का फर्क है । रिसीट में भी नहीं बता सकते कि इनकी कितनी रिसीट हुई है । नौ-नौ, दस-दस करोड़ के बजट में 100 परसेंट की बेरिएशन है । यह तो कोई तरीका नहीं कि कभी फिगर जमा कर ली, कभी घटा ली और फिर उनको यह कह दिया कि यह बजट है । अगर आपने चीजों के नाम लिख लिए कि हम डेरी डिवैल्पमेंट कारपोरेशन बना रहे हैं, हम दूध प्लांट लगा रहे हैं, हम औगमेंटेशन नहरें बढ़ा रहे हैं, हम बिजली बढ़ा रहे हैं, फरीदाबाद में थर्मल प्लांट लगा रहे हैं, यह कोई बजेटिंग नहीं होता । बऑटिंग का तरीका क्या - होता है? हमेशा जो विकासशील प्रदेश होता है उसमें चीजों की प्रायरिटीज होती है, उसमें नान-प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कभी नहीं होता । लेकिन आपने गैर-पैदावारी खर्च कर दिया और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि हम मंसूरी में भवन लेंगे । हैलीकाप्टर भी लेंगे लेक को जस्टिफाई करते हैं । लेको के नाम हमारे किसी देशभक्त और हीरो पर नहीं आते । हमारे सरदार भगत सिंह है और इसी तरह के और भी हैं जो फांसी के तख्ते पर चढ़ गये हैं । एक हमारे रिटायर्ड आई 0 ए 0 एस 0 आफिसर के नाम पर आते हैं । मैं गवर्नर साहब के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन पब्लिक रिलेशन डिपाट मैट जो गवर्नर स्पीच छापता है. उसको तो वे छापते ही है । लेकिन गवर्नर तो कभी बोलता ही नहीं क्योंकि उसकी तो जवान बन्द होती है, गवर्नमेंट बोलती टेप, चीफ मिनिस्टर बोलता हूँ, मिनिस्टर बोलते हैं । चीफ मिनिस्टर साहब

या हमारी हकूमत गर्वनर महोदय को राजी करती है क्योंकि वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है । मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक ठीक है, कहां तक नहीं है, ये जाने और गवर्नर साहब जाने, लेकिन मैं एक बात सुनता आया हूं कि जिन्दा आदमियों के नीम कभी किमी चीज के साथ वाबस्ता नहीं किए जाते । बाद में किए जाते हैं, लोग वाद में याद करते हैं कि अच्छे काम किए मुमकिन जिन्दा आदमियों को कभी एप्रिशिएट बाद किया जाता । यह हम वर्षों से सुनते आये है. बैर इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, यह हमारा बजट है । स्टेट के ऊपर 300 करोड़ के करीब कर्जा है और 18 करोड़ रुपया ब्याज बैठता है । इतना ब्याज है कि इतना खर्चा तालीम पर या किसी और सोशल सर्विस पर नहीं है इतना हमारे ऊपर ब्याज है । कौन देगा इस कर्जे को? यह छोटी सी स्टेट है । जिसके रिसोर्सिज न हो और रिसोर्सिज पैदा करने की कोशिश न की गई हो वह स्टेट तीन सौ करोड़ रुपया समेत व्याज के कैसे देगी? क्या उसका कोई तरीका है? अगर प्रोडक्टिव कामों पर इन्वैस्टमेंट की हो तो रिटर्न आएगी लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है । अगर इस से इनकम आएगी तो ठीक है कि यह रिटर्निंग कपैसिटी में है और दे देगी । आज इस साल में री-पेमेंट वगैरा का रुपया लगा कर 21 करोड़ और हो जाएगा । अगर यह हालत हमारे बजट की हो और फिर हम यह कहें कि स्टेट का प्रोग्रेसिव बजट है तो बिल्कुल गलत है ओं प्रोग्रेसिव किस बात में? किस बात की प्रगतिशील स्टेट बनी है? हमारे बजट में कहा गयीं कि हमारी नैट इनकम, नैशनल इनकम

बढ़ी है । कल राम लाल जी ने कहा कि ' हमारी नैट-इन्कम स्टेटिक है । पिछले सालों में तो हमारी नैट-इनकम और पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है लेकिन चार साल के बाद फूल स्टाप लग गया । और वे चार साल वो है जिन में इन्वैस्टमेंट नहीं हुई । इन चार सालों में औगमेंटेशन कैनल बनी, इन चार सालों में और कई काम हुए लेकिन उरुका नतीजा क्या हुआ कि नैट इन्कम नहे' वड़ी । जैसा कि उन्होने कहा कि 1969- 70 तक तो बढ़ती रही । 1965- 66 में 319 थी और 1969- 70 में 427 पर आ गई । लेकिन इन सालों के अन्दर इन्वैस्टमेंट नहीं हुई स्टेट की तरफ से । जब स्टेट की तरफ से इन्वैस्टमेंट हुई और यह रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन हुई, औगमेंटेशन कैनल से सिचाई का पानी दिया, हमारी एकडेज बढ़ी है, हमने इतने रकवे में पानी दिया हैं' हमने इतना अच्छा बीज दिया है, स्प्रेइंग किया तो नैट इंकम कम हो गई । स्प्रेइंग की कहानी भी कल रावौर हलके के लोग कह रहे थे कि हवाई जहाज से गन्ने के ऊपर जब स्प्रे किया तो सिर्फ पानी गिराया । मैं उस हैलीकाप्टर के नीचे खड़ा था और दवाई होती तो मर जाता । सरकार अपने आप वह । पर इन्कवारी करवा ले कि पानी छिड़का है । मेरे पास भी एग्रीकल्चर का महकमा था और मुझे पता था कि लोग क्या-क्या करते है, लेकिन मैं थोड़े ही दिन रहा, सीधा तो हम कर देते लेकिन मेरे भाई भजन लाल जी इक्वायरी करें कि क्या वह पानी था या दवाई थी । रादौर हलका दूर नहीं हूँ । डिप्टी स्पीकर साहिबा वहां गन्ना इतना होता है जितना सारे हरियाणा में नहीं होता । यह बात अखबारों में भी आ

चुकी है । एक मील गन्ने की खपत भी सरकार नहीं कर सकी । अब कह रहे हैं कि पावर क्रैशर की इजाजत दे रहे हैं, गन्ना पेलने की मशीन लग जाएगी । अब अगर मशीन लगेगी तो उसके लिए बिजली नहीं है । तो यह कहां से एक महीने में पेलेंगे? एक महीने में तो पावर क्रैशर चलता है, उसकी पेलने की कैपेसिटी होती है । इसलिए स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि गन्ने के लिए लोग चार पांच साल से चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है इसलिए गन्ना पेलने के लिए कारखाने लगाओ, मशीन लगाओ लेकिन इंजन लगाने की सरकार को कहां फुर्सत है । स्टेट में तीन चार चीजे प्रोग्रेस की परिचायक हैं । एक तो यह कि आज किसी स्टेट में बिजली बढ़ी । बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता क्योंकि हरियाणा बनने के बाद भाखड़ा डैम से तो मिलनी ही थी और वह बिजली कहा जाती? जब हमारे पास आ गई तो इसका वितरण तो होना ही था । हरियाणा बनने से पहले उसका वितरण नहीं होता था । स्पीकर साहब, आप तो बहुत पुराने हैं । उस वक्त हम और आप लड़ा करते थे कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करो । सरदार प्रताप सिंह कैरो के साथ लड़ा करते थे कि हरियाणा के साथ सौतेली मां का सलूक होता है । आज जब बिजली आई तो तकसीम तो सरकार ने करनी ही थी । सवाल यह है कि उसकी तकसीम कैसे को जानी चाहिए थी? जहां बिजली की वजह से पैदावार बढ़ती, जहां इस्तेमाल होती वहां लगाते । जैसे करनाल जिला कुरुक्षेत्र जिला है । जीद का इलाका है, हांसी का इलाका है, यहां बिजली देनी चाहिए । मैंने परसों हांसी में पूछा

कि क्या तुम को रानी वगैरा मिलता हँ तो उन्हेने कहा कि पहले से भी कम मिला है । कुछ जमींदार हरिजन हैं जो जमीन के मालिक है, जाट वगैरा भी आये हुये थे मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई बता सकता हँ कि तुम्हारी जमीन में पानी बढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि पहले से कम हो गया । मुझे नहर के पानी के बारे में मालूम नहीं है लेकिन मैंने पूछा कि ट्युबवैल से पानी मिलता है, बिजली मिलती है तो मुतफाबाद के एरिये के लोग कहते हैं कि पहले 12 घंटे विजली मिलती थी, उसके बाद 9 घंटे मिलती है कागजों में चाहे कुछ भी हो । (विघ्न) आपको तो चान्द राम का फोबिया लेकर डूबेगा । आपको तो लौबी में, दफतर में, जलसे में, असैम्बली में और दूसरी जगहों में भी चौधरी चांद राम बाद आता हँ । आपको तो चौधरी चांद राम का फोबिया हो गया है और यह आपको लेकर डूबेगा । (विघ्न) कोई बात नहीं । आप (श्री बनारसी दास गुप्त) अभी इलैक्शन की बात कर रहे थे लेकिन आप ही बताएं कि क्या आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़े?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

चौधरी खाद राम : आपको टिकट मिल गया, कांग्रेस में आ गए

श्री बनारसी दास गुप्ता : मैंने .. तरह बिजारत के लिए नहीं छोड़ी । (विघ्न)

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, ये अध्यक्ष रहे हैं । जरा इनसे पूछे कि क्या हाउस के अन्दर के बोलने को इजाजत है? मैं तो आप-आप कह रहा हूँ लेकिन ये कह रहे हैं जैसे ये बहुत पढ़े तो

श्री अध्यक्ष : लफज ऐक्सपंज कर दिया जाए क्योंकि यह पार्लियामेंटरी, ऐक्सप्रेशन नहीं है ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मश्कूर हूँ । आप जितना मुझे देंगे उसमें यदि इंटरप्शन न हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कोई कडुवी बात न करू । हां अगर सच्ची बात भी इनको कडुवी लगे तो उसमें मेरा कसूर नहीं है लेकिन एक बात जरूर है कि कूनीन अगर आप खा लें तो बुखार उतर जाता है और कोई अगर उसे चबा ही ले हो सकता है कि कोई अंग यदि खराब हो तो ठीक ही हो जाए और सेहत बन जाए । इलैक्शन का जहा तक स्पीकर साहब सम्बन्ध है, मैं यहां बैटूंगा, कोई भी हरिजन वजीर किसी हल्के से खड़ा हो जाए (विघ्न)

Mr. Speaker : Is it your budget speech ? This is not relevant.

चौधरी चांद राम : मैं तो स्पीकर साहब उनका जबाब दे रहा था । चलो

समाज कल्याण एवं कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) : स्पीकर साहब, इनको कुछ भी कहने की फीडम दे दो ।

Mr. Speaker ; No interruption please.

चौधरी चांद राम : ये एक जिम्मेदार वजीर है जो कि चन्दा खाने की बात रहे है । मैंने पिछली बार भी कहा था.....

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर बोले ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैं बिजली का जिक्र कर रहा था । हमारी स्टेट के अन्दर 450 मेगावाट बिजली की जरूरत है । यह हमारे गवर्नर महोदय के एड्रैस में भी लिखा है और बजट स्पीच में भी लिखा है कि 450 मैगावाट बिजली को जरूरत है । लेकिन हमारी स्टेट में बिजली पैदा कितनी होती है, केवल 232 मैगावाट । तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 10 मई, 1968 के बाद जो वजारत बनी उसने इस दिशा में क्या किया है? जिस वक्त सन् 67 का बजट पेश हुआ था उस वक्त दो नहीं तीन थर्मल प्लांटस लगाने का जिक्र बजट स्पीच में था । उसमें लिखा था कि एक थर्मल प्लांट यमुनानगर में, एक पानीपत में और एक फरीदाबाद में लगाएंगे । क्या आज इस स्टेट की जनता जिसने इस हकूमत को बनाया इस सरकार से यह पूछ सकती है कि इम पांच छह साल के अर्से में इस सरकार ने इस सिलसिले में क्या किया है? चीफ मिनिस्टर साहब वडे जोरों से कहते हैं कि नहरे खोद दीं । यह कर दिया और वह कर दिया । उन्हे यह नहीं पता कि उन नहरों के खोदने में रात-रान में लाईट के लिए साठ-साठ हजार युनिट खर्च होते थे उस समय में जबकि बिजली की जरूरत थी खेती में । रात को नहरों में खुदाई होती रही जबकि दिन को

काम हो सकता था और ज्यादा मजदूर लगाए जा सकते थे । इससे अनाज भी कम हुआ और लोगों द्वारा बिजली कंजम्पशन भी नहीं हुई । क्वालिटी क्या बनी है इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूं मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि पर्सनल होकर के इल्जाम लगाऊं । उन इल्जामों की तो किताब छपी है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा । लेकिन हम यह पूछने का हक रखते हैं कि ये पावर थर्मल प्लांट्स पांच छः साल में क्यों नहीं बने? स्पीकर साहब जिस स्टेट में 60 परसेंट कट इंडस्ट्री पर हो, साठ-साठ हजार आदमी बेकार होने जा रहे हों और ऐग्रीकल्चर में जिसमें पहले 18 घंटे बिजली मिलती थी उसमें भी नौ घंटों पर आ गए हों, उस स्टेट का क्या होगा? जब जनवरी के महीने में यह हाल है तब मई और जून के महीनों में जब वरसात नहीं होगी और जब भाखड़ा के रिजरवायर में पानी कम होगा तब बिजली का क्या होगा? ये बिजली के बारे में रोज यहां कहते हैं कि गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी है । आप भी स्पीकर साहिब गांव के रहने वाले हैं और आपने देखा होगा कि आज भी किसी हरिजन के घर में बिजली नहीं है पता नहीं उनकी करैसिटी नहीं है या वहां खम्भे नहीं पहुंचे हैं । (विधन) पैसा मैं नहीं लाता, मेरे पास तो चढ़ावा होता है, आप रोक सकें तो रोक लें । (विधन)

Mr. Speaker : Please address the Chair.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, आप जरा उनको भी रोक दे । तो स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि आज बिजली

की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किसके लिए है थोड़ी बहुत ट्यूबवैल्ज के लिए होगी या थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज के लिए होगी लेकिन गरीबों के लिए, मिडल क्लास के लिए, आम किसान और जमींदार के लिए कितनी बिजली है, घरों के लिए कोई लेता होगा या नहीं लेता होगा इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन इतना मुझे पता है आप भले ही इंकवायरी करवा लें कि कोई बिजली का कनेक्शन बिना पैसे दिए मिलता नहीं है ।

Chaudhri Dal Singh : Shame, shame.

चौधरी चांद राम : तो स्पीकर साहिब हर घर में बिजली लगने की बात तो दूर रही यहां तो हरिजनो की गलियों में खम्भे भी नहीं लगे । तो किस बात का यह बजट है, किस बात को यह सराहना है? हमारी इकौनोमी स्पीकर साहिब बड़ी लौप-साइडिड है, हमारी डिवैल्पमेंट बड़ी लौप-साइडिड है और इल-बॅलैशड है । इनका बजट इवन कील पर नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस स्टेट का जहाज कैसे चलेगा? इस बात का पता तो आगे आने वाले नौजवानों को लगेगा जो इस कर्ने को देंगे । मुझे किसी से कोई पर्सनल एज नहीं है लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वे हरियाणा के फाइनेंसिस पर जरा रहम करे और रैकलैस ऐक्सपेंडिचर न करे। जब 18 करोड़ का घाटा हो तीन करोड़ आपका कर्जा हो, अनप्रोडक्टिव ऐक्सपेंडिचर हो तब स्टेट का क्या होगा इसका अन्दाजा स्पीकर साहब आप स्वयं ही लगा सकते हैं। आज भी बड़ी-बड़ी कारे

वजीर साहिबान ने नही छोड़ी । हरियाणा भवन में पचासों कारे रोज घूमती फिरती है (विधन) आप क्यों कार की बात कहते हैं? मैंने कार भी छोड़ी थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टरी भी छोड़ी थी । (विधन) तो स्पीकर साहब मैं यह कह रहा था कि स्टेट के वजीर साहिबान को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । आज पेट्रोल मंहगा हो गया है और खर्चा घटाने की जरूरत है लेकिन आज भी हरियाणा भवन में आप देखें अफसरों की और वजीरों की कितनी कारें खड़ी रहती हैं । यह हालत जहां हो वहां बैठकर फैसला करना चाहिए कि किस तरह से इकौनोमी हो । जब तक घर से इकोनोमी नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा ।

इसके बाद स्पीकर साहब मैं इरीगेशन की तरफ आता हूं । औगमेंटेशन कैनाल इन्होंने बनाई थी लेकिन सवाल यह है कि औगमेंटेशन कैनाल मे पानी कहां से आए? ये कहते हैं कि इतने हजार ट्यूबवैल्ज डीप बोरिंग करके लगाए जाएंगे । लेकिन स्पीकर साहब, इस हाउस में कई बार कहा गया कि जब वे ट्यूबवैल्ज लगेंगे तो प्राईवेट ट्यूबवैल्ज का पानी खुश्क हो जाएगा । स्पीकर साहब एक गांव किरमिच है । वह मेरे हल्के का गांव नहीं है । वह गांव कुरुक्षेत्र के पास है । मैं वहां गया । लोगों ने मुझे बताया कि नहर के किनारे सरकार ने जो ट्यूबवैल्ज लगाए हैं उनसे हमारे ट्यूबवैल्ज सूख गए है । आप इस बात की भले ही इंकवायरी करा लें । भाई फूलचन्द जी भी कहते हैं कि सोनीपत में नहर के किनारे सरकारी ट्यूबवैल्ल लगाने से वहां न सिर्फ

प्राईवेट ट्यूबवैल्व खुशक हुए हैं बल्कि पीने का पानी भी खारा हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार औगमेंटेशन कौनाल पर घमंड करती है । परन्तु किसे बताएं? ठीक है, जहां सेम है वहां औगमेंटेशन ट्यूबवैल्व लगा सकते है कुछ देर तक काम कर सकते हैं लेकिन ऐसे इलाके में जहां अक्वल दर्जे का गन्ना पैदा हो, अक्वल दर्जे का आलू पैदा हो, अक्वल दर्जे का धान पैदा हो, अक्वल दर्जे का गार्लिक (लहसुन) पैदा हो वहां इस तरह के ट्यूबवैल्व लगाना कोई शोभा की बात नहीं है । स्पीकर साहब इनके इन ट्यूबवैल्व की बजह से आज राडौर, बबैन इन्दरी लाडवा, जींद और पुंडरी आदि के इलाके में किसानों के प्राईवेट ट्यूबवैल्व खुशक होते जा रहे हैं । यह तो "To rob peter to pay Paul" वाली बात हुई यह तो वह बात हुई कि एक जमींदार को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे जमींदार को खत्म कर दो । परसों मैं हांसी में गया था और जब मैं भिवानी से गुजरा तो मैं देखना चाहता था कि वहां कितनी सरसराहट है, कितनी सबजात है, लेकिन वहां पर अब भी अकाल पड़ा हुआ है । खेतों के खेत पड़े हुए हैं, वहां पर पानी पहुंच ही नहीं सकता । आप पानी एक तरह से पहुंचा सकते थे वह इस तरह से कि जमुना पर डैम बनाते । जमुना पर डैम बनाना चाहिए था, प्रायरिटी होनी चाहिए थी । उस डैम की बात तो मुकम्मल हो गई थी जब पंजाब सरकार थी । वहू डैम बनना चाहिए था और आपको इन्सिस्ट करना चाहिए था । अगर बन जाता तो वह मल्टीपरपज योजना, बनती, बिजली भी पैदा होती और आपको पानी भी मिलता । यह जो फलड आता है यह भी

ढकता । जमुना जो हर बार तबाही करती है यह भी न होती । लेकिन आपने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । आपने कहा कि नहर खोदेंगे, जमींदारों का रकवा लेंगे और नहरों को चौड़ा करेंगे, पक्का करेंगे, बकायदा लाइनिंग करेंगे तो रुससे क्या हुआ स्पीकर साहब कि आज हालत यह पैदा हो गई है कि जमींदार को जो वहां का पानी दिया है वह जमींदार आज नहीं तो पांच साल में बेकार हो जाएगा । दो-दो तीन तीन एकड़ के जमींदार बेकार हो जाएंगे । आज एक भाई ने कहा कि यह जमींदारों का वजट है । कहा होगा किसी भाई ने, चलो ठीक है, मगर मैं क्या कहता इन्होंने ठीक ही कहा होगा कि नैट इन्कम बढ़ी । (घंटी) स्रुकिर साहब, मैं तो गवर्नर ऐड्रेस पर भी नहीं बोला था और मैं कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं कह रहा हूँ

श्री अध्यक्ष : बात तो ऑए कुछ भी कहे, लेकिन आपने आधे घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया है ।

चौधरी चाद राम : यहा तो लोगों ने घंटा-घंटा, डेढ-डेढ घंटा लिया है ।

श्री अध्यक्ष : और भी मैम्बर बहुत हैं जिन्होंने बोलना है ।

चौधरी चाद राम : मैं तो गर्वनर ऐड्रेस पर भी नहीं बोला हूँ. जब आप कहेंगे तभी बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट दिए जाते हैं । '

चौधरी चांद राम : तो स्पीकर साहब, अगर करंट प्राईसिज को देखें तो हमारी पर-कैपिटा इल्वम 1972- 73 में 906 है । ऑज रुपये की कीमत चौहान साहब ने अलाउस की है कि 33 परसैंट रह चुकी है । अगर 33 परसैंट की डीवैल्यूएशन रिडक्शन देखें तो तीन सौ रुपये हमारी पर-कैपिटा इन्कम है । यही नहीं जो इन्कम बढ़ी है वह अपर-लैवल पर बढ़ी है, कुछ बड़े-बड़े जमीदारों को गई है, कुछ बड़े-बड़े ट्रेडर्ज को गई, जो बड़े -बड़े कोटा होल्डर हैं, परमिट होल्डर है, जो लोन लेते है उनको गई है । यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है । इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चीज है? मुझे मालूम है कि हमारा एक भाई यहां पर बार-बार बोलता है, एक्साइज का बड़ा मिनिस्टर है,(व्यवधान)

Mr. Speaker : Order please. Nothing personal.

चौधरी चांद राम : मैं पर्सनल नहीं कहता हूं ।
..... (व्यवधान)

Mr . Speaker : These words should be expunged. No personal remarks please.

चौधरी चांद राम : मैंने जो कहा है वह उनके खिलाफ कहा है । जो इंडस्ट्री लगती है उसके कोटे बलैक में बेचे जाते हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं । मैं कोई इनके अकेले की बात नहीं कहता । आज आप फरीदाबाद में जाओ और पानीपत में जाओ, और कहीं जाओ, क्या वह इंडस्ट्री लगाने का तरीका है?

अगर इंडस्ट्री लगानी थी तो पब्लिक सैक्टर के अन्दर लगाते । हमारी स्टेट के अन्दर सीमेंट फैक्टरी थी सूरजपुर में, उस फैक्टरी की म्याद हो गई थी, उसको सरकार को चलाना चाहिए था । उसमें जो इन्वैस्टमेंट होती उससे सरकार को आमदनी होती, सरकार के रिसोर्सिज बढ़ते । शुगर मिल जमुनानगर को भी सरकार को कावू करना चाहिए था, उसका नेशनेलाइजेशन करना चाहिए था । उसका नेशनेलाइजेशन करने में क्या डिफिकल्टी थी? केवल एक मील का राष्ट्रीयकरण किया था, अगर उसका नेशनेलाइजेशन करते तो करोड़ों रुपये का मुनाफा सरकार के खजाने में आता और कम से कम जमींदार को यह तो होता कि मुझे कम कीमत मित्र रही है गन्ने की तो मेरी सरकार को तो मुनाफा जा रहा है । लेकिन यहां पर मिल को नेशनेलाईज करने की बात नहीं है, यहां तो यह कहा जाता है कि साहब हम इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर रहे हैं । इंडस्ट्रीज का और ऐग्रीकल्चर का नतीजा आज हमारे सामने है । मेरे भाई अमर सिंह ने कहा था कि आज हरिजन भूमिहीन बेकार हैं । क्या स्पीकर साहब यह बात आपकी दृष्टि में नहीं हूँ कि जूतियां बननी बन्द हो गई हैं । आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि चमारो ने जूतियां बनानी छोड़ दी है । मैं कहना चाहता हूँ कि चमारों ने जूती बनानी नहीं छोड़ी, डेढ़ डेढ़ दो-दो रुपये की चप्पलें प्लास्टिक और रबड़ की चल गई, बाटा कम्पनी का जूता आ गया, मशीन का मुकाबला आ गया लेकिन सरकार ने जूती बनाने के लिए कुछ भी नहीं दिया । आज दे बेचारे बेकार हैं । आज जुलाहे गांव के बेकार हैं ।

दिल्ली क्लोथ मिल का जब टंरेलीन और पापलीन चले तो आज जो खट्ट का कपड़ा जै उससे धानक और हरिजन जो जुलाहे का काम करते थे उनका कपड़ा कौन पहने, इसलिए वे आज बेकार हैं । उकलाने की स्पनिंग मिल का 2 करोड 25 हजार रुपये का लाईसैंस हमने लिया था । वह लाईसैंस इस स्टेट के पास था जब चौधरी बंसी लाल ने चार्ज लिया था लेकिन वह स्पनिंग मिल चालू नहीं हो पाया । वह मिल कोआप्रेटिव सैक्टर में था, उसके हिस्से बिकने लग गये थे । हमारा ख्याल था कि गांव-गांव में बिजली की खड्डी लगाएगे और हरिजनो को सूत देंगे और उससे काम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । आज कुम्हारों को क्या हालत है? आज जो लुहार है उनकी क्या हालत है, जो बढ़ई है उनकी क्या हालत है? जो आटर्जिन क्लास है वह बेकार है और इसी तरह से आप जमींदारो की हालत देख लीजिए क्या है? आज 56.6 परसैंट जो काश्तकार है उनके बारे में सरकारी रिपोर्ट है, ये हमारी अपनी सरकार की रिपोर्ट है कि वो इतना खर्च करते हैं कि कमाते कम हैं और खर्च ज्यादा करते हैं । यानी उनका गुजारा नहीं होता । उन्होंने कहा "They actually live on bankreuptey or on the verge of bankruptey." दीवालिएपन में रहते है या दीवालिएपन के किनारे पर रहते हैं । यह हमारे 57 परसैंट जमींदारों को हालत है । हम स्टेट मे व्वायंसी पैदा न करे । हम इस तरह की बात पैदा न करें जिससे न बिजली की तरफ ध्यान दे, न नहरों की तरफ ध्यान दे । हमको 30 परसैंट पानी मिलता रहा नहर का । वह पानी ज्यादा एरिये के अन्दर फ़ैलने लगा ज्यादा जगहों पर जाने लेगा गुडगाव

में, महेन्द्रगढ में, भिवानी में, ठीक है, वहां जाना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह है जिस एरिया में वह पानी ज्यादा लगकर के ज्यादा पैदा कर सकता वह प्रिया तो महरूम हो गया । यह आप जानते हैं कि गेहूं को अगर पांच छः पानी नहीं लगाएंगे तो पैदा नहीं हो सकता । क्या कभी एक –दो पानी में गेहूं पैदा हो सकता है? जिस एरिया में तीन पानी लगते हैं उसको चाहिए था कि चार पांच पानी कर देते । वह एरिया हरियाणा के अन्दर इतना ज्यादा अनाज पैदा कर सकता था जितना सारे हरियाणा में भी नहीं हो सकता था ये दो तीन जिले ही ज्यादा पैदा कर सकते हैं लेकिन इनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया । अब मैं लैंड रिफार्म की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । इनको लैंड रिफार्म का बड़ा भारी घमंड है । 22 दिसम्बर 1972 को कहा कि यह पहली स्टेट होगी जहां पर लैंड रिफार्म का बिन पास हुआ है । 5 मार्च 1973 को गवर्नर की स्पीच में कहते हैं कि साहब एक लाख या डेढ़ लाख एकड़ जमीन निकलेगी । लेकिन अब कहते हैं कि 40 हजार एकड़ के करीब निकलेगी । डेढ़ लाख से 40 हजार पर ठौपल-डाऊन हुए । 40 हजार से कितने आदमियों को खुश करेंगे? ये कहते हैं कि हरिजनों को भी जमीन दे देंगे, एक्स सर्विसमैन को भी देंगे, बैकवर्ड को भी देंगे । एक बात का और घमंड करते हैं फूडग्रेन का । बताईये आप फूडग्रेन में पिछली बार कितनी प्रोक्योरमेंट हुई? किस तरह से ड्राउट कंडीशन थी, क्या हालात थे वे हमारे सामने हैं । लेकिन आज फूड ग्रेन की यह हालत है कि गांव-गांव के अन्दर हमने डिपो खोल रखे हैं करीब साढ़े तीन हजार । मैं एक

गांव में गया, वहां बहुत बड़ी हाजरी थी और मेरे साथ तीन एम 0 एल0 एं 0 थे जिसमें एक्स-एम 0 एल 0 ए 0 भी थे । मैंने वहां जाकर पूछा कि तुम्हारे गांव में अनाज मिलता है' क्या राशन की कोई दुकान है, क्या तुम्हें 85 पैसे फी किलो के हिसाब से राशन मिलता है? उन्होंने कहा कि नहीं मिलता । मैं रौहाणे गांव में गया, वह इतना बड़ा गांव है' उन से पूछा कि तुम को मिलता है तो उन्होंने कहा कि नहीं । मैं कलानौर में भी गया उन्होंने भी कहा कि नहीं मिलता । कलानौर और काहनौर बड़े बड़े गांव है, पक एम 0 एल 0 ए 0 का गांव है, उसमें भी राशन की दुकान नहीं है और राशन नहीं मिलता । आज आपने जमींदार का अनाज स्पीकर साहब 76 रुपये लिया और 76 रुपये क्विंटल खरीदने के लिए तो पुलिस भिजवा दी, फूड इन्सपेक्टर लगवा दिए और उन्हें कहा कि जमींदारों का पीछा करो, उनके घरों से उनके गोदामों से अनाज निकालो लेकिन आज वही अनाज बाजार के अन्दर 110, 120, 140, रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है । जमींदार की कष्ट की कमाई से पैदा किया हुआ अनाज 76 रुपये- क्विंटल के भाव से खरीदा गया और आज वही 130- 140 के भाव बिक रहा है, खुले आम बिक रहा है' उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं, कोई पुलिस नहीं । लेकिन आप कहते हैं कि नहीं-नहीं कोई बात नहीं है, जमींदारों की सरकार है, मेहनतकशों की सरकार है ।

अब इम्प्लॉयर्स को बात है । टीचर्स को कहा गया है, उनको उस टाइम पर तसल्ली दी गई कि तुमको राहत देगे । बड़ी

अच्छी बात हैं. हम तो चाहते सै कि कोई वर्ग न भड्के । लेकिन उनके लिए कोर्टू कंक्रीट वात लाओ । टीचर्ज के बारे में समझौता हुआ, कुछ दिनों के वाद कह दिया कि हमारे से कोई समझौता नहीं हुआ । कल को यह भी कह देंगे कि हरिजनों की कोई बात नहीं हुई । 12 मैम्बरी कमेटी बना करके वहां कहा भी गया है कि नही मैने कुछ नहीं करना है । कोई बात नहीं है भाई, और भी पीछे रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे । (घंटी) स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने समय दिया है । लेकिन जो हालात हमारे दरपेश हैं उनमें ऐ सा काम करना चाहिए जिससे स्टेट के रिसोर्सिज बढे इस स्टेट की क्षमता बढे' इ न शब्दों के माथ मैं अपिका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हरिजन वैल्फयर के काम है, पुराने जो हु कम हैं गवर्नमैट के है उनकी भी इम्पलीमैट किया जाए । रिजर्वेशन के आर्डर्ज है कि उस डेट से दो । फर्स्ट वैकेन्सी न देकर यह कहते है कि हम तीसरी वैकेन्सी देंगे । थे आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार मे भी उनको फर्स्ट वैकेन्सी देते कब । लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले साले से 1956 से उखाडो । जब इन्हें यह पता लगा कि 1956 के केसिज तो री- ओपन नहीं हो सकते, बड़ी डिफिकल्टी होगी, फिर यह कहा अव पीछे के रहने दो आगे के लिए पब्लिक सर्विस कमिशन से यह कहो कि सीनियरिटी डिटरमीन करे ।

Mr. Speaker : You have begun to deliver a second speech now. Please resume your seat.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन में और प्रोमोशन के बाहए में हुक्म है तो कम से कम वे ही लागू कर दे । आज हालत यह है कि एक हीरा लाल वर्सिज प्रताप सिंह के केस में इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील की । सुप्रीम कोर्ट ने 18- 12- 1970 को ब्लाक सिस्टम की और क्लास-वन की रिजर्वेशन भी वेलिड करार दे दी लेकिन पंजाब में तो 11 जनवरी 1971 से पीछे से लागू हो गयी और हरियाणा जिसने अपील की थी उसमें आज तक क्लास-वन में वह आर्डर लागू नहीं हुए । जो शैडयूल्ड कास्ट आफिसरज के बारे में बात है, वह मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उनको और ज्यादा मार पड़ेगी । उनकी विक्टैमाईजेशन की जायेगी इसलिये इसके बारे में मैं कुछ और नहीं कहना चाहता । स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने से रोका है मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि अमल में तो वे मेरे ऊपर कोई इल्जाम ला नहीं सकते, उनके पास एक ही है, जो वे मेरे ऊपर लगाने हैं, अगर वे चाहें तो मेरे ऊपर मुकदमा करें । मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर मुकदमें भी बनेंगे । एक मुकदमा क्या, कई मुकदमें बनेंगे । इस स्टेट में तो यह है कि कभी दल सिंह के पीछे हो जाओ, कभी दौलता के पीछे हो जाओ, कभी हरद्वारी लाल के पीछे हो जाओ क्योंकि एक सेशन में एक आदमी लेना होता है वह कोई बात नहीं है.....(घंटी व शोर)

Mr. Speaker : Order please. Please resume your seat.

वित्त मंत्री (श्री राम मरन चन्द मितल) : स्पीकर साहब, मैं रुक निवेदन करना चाहता था । चौधरी चाद राम जी ने अपने भाषणा के अन्दर सी 0एम 0 की बुआ के लड़के को मौजूदगी का रैफरैन्स दिया है । क्योंकि वे यहां हाउस में डिफैन्ड नहीं कर सकते इसलिये चौधरी बंसी लाल जी की बुआ के लड़के से सम्बन्धित जो पोरशन है, उसको ऐक्माग्ज करवा दिया जाए ।

Mr. Speaker : That should be expunged.
(Interruptions)

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में 1974-75 के विषय में चर्चा चल रही है । इसमें बहुत से हमारे साथियों ने भाग लिया है । कई विरोधी दल के साथी कुछ आर्गुमेंट्स के सामने आये फि हरियाणा में जो यह बात कही जाती हूँ कि हरियाणा तरक्की कर रहा है, वह उचित नहीं है । उनको हरियाणा की तरक्की की बात पसन्द नहीं आयी । यह एक बड़े दुःख की बात है कि कोई आदमी अपने प्रांत को तरक्की को देखकर खुश नहीं हो सकता । मैं समझता हूँ कि ऐमे आदमी को प्रांत में रहने का अधिकार नहीं है । मुझे एक कपलैट याद आ रहा है—

"Breathes there the man with soul so dead.

Who never to himself bath said, this is my own, my native land."

उन लोगो को जो अपने प्रांत की तरक्की ही को देखकर, प्रांत की खुशहाली को देखकर खुश नहीं होते हैं, क्या अधिकार है कि वे प्रांत में रहे? वे ऐसी पिक्चर हाउस के सामने पेश करते हैं जो बिलकुल बे-मायने है और फैंक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है । एक सदस्य यहां पर यह कहने लगे कि जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें यह साफ जाहिर है कि बड़े भारी टैक्स लगने । इससे मुझे बड़ी हैरानी होती है । अध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है कि बजट की बात तो दूसरी है उन्होंने हमारे वित्त मंत्री महोदय का जो भाषण है, उसकी भी ठीक ढग से नहीं पढ़ा हूँ । वित्त मंत्री महोदय के भाषण में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि यह अनुमान अभी पूर्ण नहीं है । हमें उम्मीद है कि हमें जो सैट्रल अस्पिटैस मिलती है, जो प्लानिंग कमिशन की रिकमैण्डेशन्ज होनी है, उससे हमें शायद और पैसा मिले । इससे घाटा कम होने की सम्भावना है । यह बात बिल मंत्री जी के भाषण में पूर्ण रूप से साफ को हुई है । अध्यक्ष महोदय, मुझे उन सदस्यों पर बज दुःख होता है जो बिना कुछ पढ़े हुए और बिना तैयारी किए हुए क्रिटीसीजम करने के लिए खड़े हो जाते हैं । क्रिटीसीजम फार दी सेक आफ क्रिटीसीजम दे करते हैं । (व्यवधान) अभी-अभी मेरे से पहले एक सदस्य बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए । वे बजट की बात तो भूल गए । उन्होंने सबसे पहले संघर्ष समिति और हांसी वाला मामला शुरू कर दिया । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में काफी दिनों से आप ने भी चर्चा सुनी होगी । वे भाई एक संघर्ष समिति के नाम से हरिजनों को मिस गाईड करसे रहे । मुझे भाई अमर

सिंह जी की एक मिसाल याद आती है । वह गधे को जैसे मूली दिखा कर दूर तक ले जाते थे ठीक वैसा ही एक तरह का ढांचा उन्होंने भी रचा । क्या हुआ कुछ अर्से से हरिजनों के पास कुछ जमीनें थी पहले तो बे भाई उन जमीनो को बटाई के रूप में उन लोगों से खाते रहे किसी की अलाटमेंट पक्की करते रहे और किसी की अलाटमेंट कच्ची करते रहे लेकिन जब सरकार ने अपनी कदम उठाया और बताया कि वह अलाटमेंट तो कच्ची है, इसकी जगह उन्हें दूसरी जगह जमीन देंगे तो इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई, हमारे पास आओ हम आपको दो-दो किल्ले फी आदमी जमीन देंगे । इन्होंने उन्हें कहा कि आइए, इसके लिए आप हमारे साथ संघर्ष समिति में शामिल हो जाइए । अध्यक्ष महोदय, हमारे गरीब आदमी और खास तौर पर चमारों में यह वीकनैस है कि उनको जमीन का लालच देकर चाहे कुओं में गिरादो, वे कुओं में भी गिर जाएंगे । यह हकीकत आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि प्रदेश में कितनी फालतू जमीन है यह बात दिगर है कि जो जमीन देहात में फालतू निकलनी है, उसको हमने हरिजनों में बांटना है और सरकार उसके लिए कमिटिड है । अगर चौधरी चांद राम ने उनके लिए कुछ प्लॉट्स कटवा रखे हों तो अलग बात है, हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते । हो सकता है कि वह लोगों से यह कहकर चन्दा लेते हों कि आप हमें चन्दा दो, हम आपको प्लॉट्स देंगे । ऐसे आदमी अभी हरिजनों का और कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे । मैं उनसे यह प्र छना चाहता हूँ कि कांग्रेस उन्होंने बनाई है या

कांग्रेस ने उन्हें बनाया है? वह तो ऐसे कलेम कर रहे थे जैसे हरियाणा के अन्दर चौधरी चांद राम ही हरिजन है और वही कांग्रेसी है, और कोई दूसरा नहीं है

स्पीकर साहब, साफ तौर पर यह बता देना चाहता हूँ कि हमारे वे माननीय सदस्य उस कांग्रेस संस्था के प्रोडक्ट हैं, जिसने उनको बनाया है, उनको पढाया—लिखाया है उसके बाद वे वजीर भी रहे हैं । लेकिन आज आदमी कुर्सी का मारा हुआ होता है उसका दूर कोई प्रिन्सिपल या कोई असूल नहीं होता । उसके लिए कुर्सी ही मां, कुर्सी ही बाप, कुर्सी ही पार्टी और कुर्सी ही सब कुछ होती है । वह तो कुर्सी के लालच में यह देखता फिरता है कि किसी तरह से कुर्सी मिल जाए । उनका कोई असूल नहीं है वे लोगों को मिस—गाईड करते हैं । कभी चन्दा इकट्ठा करते हैं तो कभी कुछ और करते । स्पीकर साहब, यह रिकार्ड को चारु है । उनके सहयोगियों ने कुछ एम० एल० एज० ने भोर लोगों ने उनकी भरी मीटिंग में जो संघर्ष के लिए इकट्ठे हुए थे यह कहा कि यदि आप चन्दे का हिसाब नहीं देते तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे । आखिर में आकर वे पर्चा सा दिखा रहे थे और यह कह रहे थे कि यह मैंने लिस्ट बना रखी है जिसमें चन्दे का हिसाब—किताव दिया हुआ है पता नहीं यह कहां तक सही है....

चौधरी चांद राम : प्वायंट आफ आर्डर सर । स्पीकर साहब, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जो बात ये कह रहे हैं, वह बजट पर है या हरिजन संघर्ष समिति पर है? (व्यवधान)

Mr. Speaker : If a member brings in an irrelevant thing, then the other member also tries to drag that subject and make it relevant. Please try to be relevant

Chaudhri Phool Chand (Mullana) : I am definitely relevant. I am replying to the objections raised by him. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : बात दरअसल यह है कि पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन से मामला लैन्थी हो जाता है और उसका यह हशर होता है कि दूसरा सदस्य भी उसके बारे में कहना शुरू कर देता है । personal explanation should be confined only to the words It should be confined to the words which an Hon'ble Member wants to explain, (Interruptions & Noise) Order please. No comments.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब मैंने तो आपको प्वायंट आउट कर दि है, आगे आपकी मर्जी है । आप चाहे तो पूरी तकरीर मेरे ऊपर करा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है । (व्यवधान)

Mr. Speaker : No interruptions please.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर आक्षेप किया । मुझे इस मोके पर एक शेर याद आ गया वह मैं कह देता हूँ :

“खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं,

साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं । ”

हमें इनके बहुत से साथी यह कहते हैं कि हमने तो इनको कांग्रेस में जाते जाते पकड़ कर खींच लिया है । किस बिना पर वह क्लेम करते हैं ... (व्यवधान)

18.00 बजे ।

Mr. Speaker : Please confine yourself to the Budget.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : जहां तक इस बात का ताल्लुक है इन्होंने कोशिश की कांग्रेस में आने के लिए और ढनका इरादा था कि संघर्ष समिति के द्वारा अपनी ताकत दिखाकर कांग्रेस पार्टी के अन्दर शामिल हो जाएं लेकिन हमारी प्रधान मंत्री जानती हैं ये हरिजनों के हितैषी नहीं है । ये हरिजनों को बरगलाकर, उनकी धोखा देकर अपने साथ रखना चाहते हैं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इन्होंने बार प्रधान मंत्री से मिलने का समय मांगा लेकिन इनकी मिलने का समय नहीं दिया गया । मैं एक और इस्टांस बताना चाहता हूं । एक बार यह अपना डैपूटेशन...

Mr. Speaker : Order please. Please confine to the Budget.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : मैं इनका एक उदाहरण दे रहा था । जब यह संघर्ष समिति के मामले को लेकर प्रधान मंत्री की कोठी पर गए ।

Mr. Speaker : Order please. Please come to the Budget.

Chaudhri Phool Chand (Mullana): I am coming to the budget. But I am replying to the objection raised by him.

Mr. Speaker : It is not relevant.

चौधरी फूल चन्द मुलाना : मैं बता रहा था कि यह कांग्रेस में कैसे आना चाहते थे । स्पीकर साहब, मैं यह बता रहा था कि यह प्रधान मंत्री से मिलने गए.....

Mr. Speaker : Please confine yourself to the Budget. It will lead to further personal explanation and it will not end.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : स्पीकर साहब, जमीन के बारे में चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि हमने जमीन अलाट नहीं की । स्पीकर साहब, यह साफ तौर पर रिकार्ड की चीज है । रिकार्ड मंगवा कर देगब लिया जाए । जब यह वजीर थे तो इन्होंने अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन आक्शन करा ली । अगर आज उसके बारे में इनक्वारी कराई जाए तो वह जमीन सरप्लस निकलेगी । यह कहते हैं कि मैं गरीबों का भला चाहता हूँ । मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि वह गरीबों का भला नहीं चाहते । जो आदमी अपने जाती मफाद के लिए गरीब लोगों को अनपढ़ लोगो को बहकाने में माहिर हैं क्योंकि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई बढा लिखा हरिजन इनकी स्पोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे । पढ़े लिखे हरिजन से तो इनको नफरत है.....

Mr. Speaker: Order please. You are speaking irrelevant.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा था । वैसे इन्होंने संघर्ष आपके सामने भी दिखा दिया । जैसा कि गुप्ता जी ने ध्यान किया कि दो-तीन दिन पहले हांसी के अन्दर हरिजनों को आपस में लड़वा दिया और संघर्ष पूरा करा दिया..

Mr.Speaker : Order please. This is all irrelevant.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : स्पीकर साहब, बजट की बात चल रही थी । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो अपनी स्पीच और अनुमान बजट के पेश किए हैं वे बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, मैं तो कहूंगा कि वे गरीबी हटाने वाले हैं । आज हम उस प्रान्त पर तर्क करते हैं जो कुछ दिन पहले, हमारे इस सदन के कुछ साथियों की वजह से आया राम गया राम की वजह से बदनाम हो गया था लेकिन आज हम अपनी मौजूदा सरकार और मौजूदा चीफ मिनिस्टर पर गर्व कर सकते हैं जिन्होंने इस प्रांत को इतने अच्छे ढंग से चलाया है । हम अपना सर आज गर्व से ऊंचा कर सकते हैं । हमारा नाम केवल प्रान्त में ही नहीं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऊंचा है । वित्त मंत्री महोदय ने इतने अच्छे ढंग से बजट पेश किया है कि किसी भी पहलु को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा । सारी समस्याओं का पूरी तरह हय। न रखा है । इसके अन्दर पहले यह माना है कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण

उत्पादन कम हुआ। लेकिन जो इन्होंने अब अनुमान पेश किए हैं कृषि के लिए, पानी के साधन उपलब्ध कराने के बारे में, खाद के साधन उपलब्ध कराने के बारे में वे काफी उत्साहजनक हैं। वैसे तो हमारी स्टेट पहले ही अन्न के मामले में सरप्लस हो चुकी है लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं कि इस साल के अन्दर हम और भी ज्यादा अन्न पैदा कर पाएंगे। स्पीकर साहब, हमारा प्रान्त रूरल है और हमारी सारी इकनामी खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है और देश को खुशहाल करने के लिए यह जरूरी है कि हम खेती-बाड़ी की ओर अधिक ध्यान दें। हमारी सरकार इस ओर पुरजोर प्रयत्न कर रही है। मेरे बहुत से साथियों ने सरकार के प्रयत्नों के बारे में बहुत कुछ बताया है मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। हमारी सरकार ने इरीगेशन को सब चीजे उपलब्ध कराई हैं और उन साधना में से एक साधन पानी है जिसके लिए सरकार ने अर्थक प्रयत्न किए हैं और कर रही है। पहले कुछ पानी बरसात का इकट्ठा होकर बाढ़ के रूप में खराब करता था। उस पानी को रोककर उसमें हमें सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए हैं, बहुत सी नहरें बनाई हैं और मैं एम ० आई ० टी ० सी ० को दाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी जगह पानी पहुंचा दिया जहां किसान ट्यूबवैल लगाकर पानी लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस कारपोरेशन ने 900- 900 फुट नीचे तक बोर करके ट्यूबवैल लगाए हैं। स्पीकर साहब, अम्बाला जिले में नहर तो असम्भव है अगर सरकार नहर दे दे तो बहुत मेहरबानी लेकिन ट्यूबवैल खूब लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हर

खेत को पानी न मिल जाए इस प्रयास को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए । हर खेत को पानी देने के लिए अधिक से अधिक ट्यूबवैल लगाए जाएं जिससे कि किसान को पानी मिल सके और प्रान्त के अन्दर अन्न का उत्पादन बढ़ सके । इसके साथ ही साथ हमारे एरिया में जहां इरीगेशन के साधन उपलब्ध हुए हैं, मैं एक सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं कि कुछ नदी नाले विशेष रूप से मेरे इलाके मुलाना में जैसे टांगरी, मारकंडा हैं, हर बार बरसात के दिनों में उनसे कुछ गांव अफेक्ट होते हैं जैसे सैहला, कनिपला, मरावा, खेड़ा काकडकुंडा और तंदवाल । इन नदी नालों की बाढ़ से खेती भी खराब हो जाती है । और आबादी भी खराब हो जाती है । मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि उन पर कोई बांध लगाकर उस पानी को रोक दिया जाए । उससे यह लाभ होगा कि एक तो बरसात के दिनों में लोग बाढ़ से बच जाएंगे और बाद में उस रुके हुए पानी को खेतीबाड़ी के लिए दे सकेंगे ।

इसके साथ ही साथ दूसरा । पहलू जो मैं टच करना चाहता हूं वह अस्पताल है । सरकार ने इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है । नए अस्पताल खोले गए हैं, और मैडिकल फैसिलिटीज दी गई है । मिनिस्टर महोदय ने बताया है कि 80 पैसे प्रति व्यक्ति दवाइयों पर जो खर्चा किया जाता है वह देश की उच्चतम दरों में से तक है । लेकिन मेरी राय है कि देहाती इलाकों में मैडिकल फैसिलिटीज अभी भी इनएडिक्वेट हैं । उनको पूरा करने के लिए देहाती इलाकों से अस्पताल और

डिस्पैसरिया खोलना अति आवश्यक है । इसके साथ ही साथ हमारा जो स्वास्थ्य पर खर्चा है, जो मैडिकल एक्सपैन्सिज है वे बहुत ज्यादा हैं । एक गरीब आदमी मे डाक्टरी एड लेना बहुत महगा पडता है । मैं मुझाव दूंगा कि उनको ?? न किसी ढंग से इतना सस्ता कृर दिया जागृ कि सारे आदमी उसे प्राप्त कर सकें । मुलाना के अन्दर एक बहुत पुराना बना हुआ हूँ, वह प्राईमरी हैल्प सैन्टर भी नहीं है पता नही कि उसको क्या कहने हैं । उसमें कुछ नई बिल्डिंगें बनाने का विचार था । पिछली बार मैंने कहा था कि वह बिल्डिंग अधूरी बनाकर छोड दी गई हूं और अधूरी जो बिल्डिंग छोड दी गई, न तो इनको बनाने का विचार किया जा रहा है, और न ही इस तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा ठे । तो मेरा सुझाव है कि इस बिल्डिंग को पूरा करके मुलाना में 25 बैड्ज का हस्पताल बना दिया जाए क्योकि इसके इर्द गिर्द कम से कम 50 गांव लगते हैं और इन गांवों के लिए पास ही कोई ऐसा हस्पताल नही है जिससे इस इलाके के लोग कोई फायदा उठा सकें । इस बेकार की सुविधाएं हर देहात में होनी चाहिएं ऐसा मेरा विचार है । कालिज भी यदि वहां पर एक खोल दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी । शिक्षा के बारे में तो इतगा ही कहूंगा कि इस क्षेत्र में हमारे हरियाणा प्रांत ने बहुत तरक्की की है, कई इन्स्टीशून्ज खोली गई है । यहां मेरे कई भाई रोहतक मैडिकल कालेज की तारीफ करते हैं, कई तो यहां तक भी कह जाते हैं कि रोहतक मैडीकल कालेज तो यहां के पी० जी०आई 0 से भी बढ कर हैं लेकिन रोहतक के मैडीकल हस्पताल से दूर-दूर के लोगो

को (जैसे अम्बाला, कुरुक्षेत्र) कोई आराम नहीं मिल सकता क्योंकि यह इन इलाकों के लोगों के बस का नहीं कि इतनी दूर जा कर अपना इलाज करवा सके । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का हस्पताल अम्बाला और कुरुक्षेत्र में भी बनाया जाए ताकि यहां के लोगो को हर तरह को सहायता मिल सके । यहां पर टूरिजम की बात भी हुई, इस बारे में' यह कहा गया कि टूरिजम एक बहुत आवश्यक पहलू है हमारे जीवन में । हमारे हिन्दोस्तान में बंगाल के लोग इस टूरिजम के लिए माने हुए हैं । कुछ लोग कहते हैं कि टूरिजम डिपार्टमेंट का मुकाबला तो हम स्विटजरलैंड से कर सकते हैं । पिछले दिनों मुझे बंगाल जाने का मौका मिला और कई लोगों से मेरी बातें हुई तो स्पीकर साहब हमारा सिर फखर में ऊंचा हो जाता है । जब वे लोग बात कहते है कि वहु हरियाणा जिसको हभ जोहड़ कहा करते थे, बहां आज रैस्टोरैन्ट्स हैं, झीले हैं, सड़के हैं, बिजली है । स्पीकर साहब, टूरिजम ने तो हमारे प्रांत का नाम ही ऊंचा किया है और ऐसे-ऐसे स्पोट्स स्पीकर साहब, किसी प्रांत की तरक्की के होते हैं । कोई किसी के घर मे जाकर तो नही देखता कि क्या वै, एक आदमी बाहर से आता अप, सड़कों से गुजरना है, उसकी असैसमेंट करने के उपरांत ही वहां की हालत को असैस करता है । स्पीकर साहब, टूरिज्म डिपार्टमेंट को हम दाद देते हैं कि देसने बड़े अच्छे ढंग से प्रांत को खुब सजाया है । स्पीकर साहब, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हुं कि दूध की क्रान्ति ने तो हमारे प्रान्त में कमाल ही कर दिया है । मैं इस को विशेषकर

कितना अच्छा समझता हूँ कि हमारे हरियाणा में मिलक प्लांट खोल-कर कुछ सोसायटीज मिलक की बनाई गई हैं और उस में हरिजनो को ग्रान्टस दी गई हैं, कुछ कर्जे दिये गये है, जिस से कि वे लोग अपनी गाय भैस खरीद कर अपना गुजारा कर सकते हैं । मैं तो इसको वास्तव में गरीबी हटाओ प्रोग्राम कहता हूँ कि वास्तव में यह ही एक गरीबी हटाओ का प्रोग्राम है कि जिस आदमी के पास, जिस गरीब के पास कोई कमाने के साधन न हो, उसके लिये इतना हीकर देना बहुत अच्छी बात है । गरीबी कब हटती है कि जब हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे, आजादी हमें मिल गई लेकिन आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिली है उस को आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके आमदनी के साधन कोई न कोई अवश्य हों, एजुकेशन अच्छी हो, तो गरीब आदमी खुद व खुद ही आगे बढ़ता चला जाएगा । स्पीकर साहब, इस प्रकार के प्रोग्राम हमारी सरकार ने जुटाये है । स्कूलों की बाबत मैंने पहले जिकर कर दिया, लेकिन एक सुझाव मेरा रहता है कि पिछले दिनों से कई स्कूल अपग्रेड नहीं हुए है, उनकी अप-ग्रेडेशन का ध्यान देना चाहिए क्योंकि कच्चों को दूर-दूर जीने में कठिनाई महसूस होती है और आजकल तो सकूल में बच्चों को सख्या भी बढ़ती जाती है जिस मे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अकमोडेट नहीं हो सकते । अपग्रेडेशन के बारे मे मर हल्के में जो स्कूल है वह हैं -

गदौली

मिडल से हाई स्कूल

मनका मनकी प्राइमरी से मिडल

टेपला प्राइमरी से मिडल

रामपुर प्राइमरी से मिडल

स्पीकर साहब, इन ऊपर बताए गए स्कूलों की अपग्रेडेशन बहुत ही आवश्यक है, इस लिये सरकार को इनको अप-ग्रेड करने की तरफ शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये । रोड्ज के नाम पे र भी हमने नाम कमाया है । हमने 60 परसैन्ट गांवों को लिंक रोड्ज दे दी है और इस मौजूदा बजट के तहत हमारे फायनैन्स मिनिस्टर साहब ने यह जाहिर किया कद कि 60 परसैन्ट से अधिक 8 हजार 500 किलो मीटर लम्बी सड़कें और बना दी जाएंगी । यह बहुत अच्छी बात है । और-धीरे धीरे हम सभी गांवों तक सड़कों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन इस बारे में मेरा आप के द्वारा सरकार से अनुरोध है कि जो सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, चाहे मैटिरियल की कमी हो, उसके इर्द-गिर्द जो सामान पड़ा हुआ है, उसको ध्यान रखते हुं वे सड़कों का कार्य को कम्प्लीट किया जाए । स्पीकर साहब, हरिजनों की भलाई ने लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं । हरिजन कल्याण निगम चलाकर सरकार ने उन लोगों के लिए, जिन के पास कोई साधन नहीं थे, यह बात कर दी है कि वह यहा से लोन लेकर अपना काम चला सकेंगे, जिस से कि उनकी आमदनी बढ सकेगी और इस के साथ-साथ उन्हें जो हमारा सोशल वेलफैयर आफ शैडयूल्ड

कास्ट डिपार्टमेंट है, वहां से भी कई किस्म के लोन मिलते हैं, ग्रान्ट्स मिलती तो इस कर्ज 'मे लेकर भी हरिजन लोग अपना काम चला सकते है । दुसरी इस बार में जो बातें -हुई है स्पीकर साहब, यह बड़ी रिमार्कबल बातें है । वह यह है कि पहले हरिजन बच्चो को स्टाइपैन्डस स्कूल टाईम में, जब क्लास खत्म हो जाती थी, मतलब साल के बाद मिला करना था लेकिन अब उनको हर महीने यह स्टाइपैन्ड देने को सरकार की तजवीज हँ, यह बहुत अच्छी बात है, इमसे गरीब हरिजन वजीफे लेकर अपना काम घना सकता है । लेकिन वजीफे के बारे में मेरा एक सरकार मे सुझाव है कि वजीफे को रकम जो दी जाती है वह बहुत पहले समय से तय की हुई ही चली रही है, आजकल महगाई का जमाना है, सोने मंहगी है. तो इम बात को ध्यान में रखते हुए यह वजीफे की जो रकम दी जाती है, इस को वजा दिया जाए ऐसा करने से और भलाई का कान होगा । स्पीकर साहब, जो रिजर्वेशन की बात हुई हूँ वह भी बहुत माके की हुई है और यह जो रिजर्वेशन हुई वह कारपोरेशंज और सैमी-गवर्नमैट बाडीज में की है, उससे सर्विसिज में हमारे लोगो को और भी हौसला मिलता है । स्पीकर साहब, इस में कोई शक की बात नही है कि हमने हर पहलु पर उन्नति की सै, हरिजन समाज जो मुदतो का दबा चला आ रहा था, और पूजनीय महात्मा गांधी जी के जो स्वप्न थे, वह अब साकार होते जा रहे है । अभी तक हमारे समाज में अस्पृशता दूर नही हुई है, अभी उसके थोड़े-थोड़े अंग कहीं न कहीं बाकी है तो मेरा सरकार को सुझाव सै कि गवर्नमैट ने जो एक अन- टचबिल्टी

एकट बनाया हुआ है। उसको और तेजी से इम्पलीमेंट कर दिया जाए अगर इसके साथ अन-टचेबिल्टी के खिलाफ कुछ लोगों के विरुद्ध केस रजिस्टर किए जाए तो समाज में, एक भय पैदा होगा और तभी यह अस्पृशता की भावना लोगों के दिलो से दूर होगी। क्योंकि यह तो हिन्दुस्तान के ऊपर एक कलंक है, और इसको दूर करना हमारी सरकार का फर्ज बनता है। तो स्पीकर साहब, हमारे वित्त मंत्री महोदय मे बजट के अन्दर कोई पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जिस में प्रोग्रेसिव विचार न रखे हों चाहे, वह एग्रीकल्चर है, चाहे बिजली है, चाहे नहरे हैं, चाहे पशुपालन है, किसी भी तरफ आप देख ले, हिरयाणा प्रान्त आज तरक्की के पद पर अग्रसर है। स्पीकर साहब. इसके साथ –साथ इन्डस्ट्रीयलाइजेशन को बात भी यहां पर चली, इसका जिक्र करते हुए एक सदस्य ने कहा कि उद्योग बढा है, मैं इससे सहमत हूं कि इस और तरक्की हुई। मगर हमारी धारणा है कि इन्डस्ट्रीयलाइजेशन को देहातों के अन्दर छोटी-छोटी यूनटो द्वारा चालू किया जाएगा, जिस से गरीब किसान को, गरीब मजदूर को रोजी कमाने के साधन उपलब्ध हो सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों का जो आर्थिक ढांचा है वह इतना सुदृढ नहीं हो सकेगा। इस बारे में मैं अपना सुझाव यह रखूंगा कि देहातों के अन्दर लघु उद्योग खोले जाएं और बड़े उद्योग भी खोले जाएं जिससे कि देहाती के लोगों को एम्प्लायमेंट मिले और उनकी बेरोजगारी हटे। बहुत से उद्योग हमारी सरकार ने खोले भी है और खोलने जा रही है लेकिन मेरा यह सुझाव इस लिए अति आवश्यक है कि हमारा प्रान्त जो है वह देहातों में रहता

है कृषि प्रधान प्रदेश है । और इन सब बातों को देखते हुए यह होना जरूरी है (घटी) स्पीकर साहब, मैं अभी खत्म करता हूँ । हमारे मंत्री महोदय ने हाउसिंग बोर्ड के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि हम गरीब हरिजनों के मकानों के लिये प्लॉट्स दे रहे हैं ताकि जिनके पास मकान नहीं है वे मकान बन सकें । यह भी बहुत अच्छा कदम है । दूसरी इन्होंने यह भी बात बताई है कि बड़े-बड़े शहरों में हाउसिंग कालोनीज बनाई जा रही हैं जिनमें 10 प्रतिशत हरिजनों के लिए रिजर्वेशन रखी गई है । लेकिन स्पीकर साहब, इसके बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार उनको प्लॉट्स भी दे देगी और ग्रांटज भी देगी लेकिन उनके लिए ऐसा कुछ प्रबन्ध कर दिया जाए चाहे वह हरिजन कल्याण निगम की ओर से हो चाहे और किसी की तरफ से हो जिससे कि वे मकान बना सकें । उनके लिए खुद मकान बनाना कठिन है क्योंकि उनकी आमदनी के साधन कम हैं भूमिहीन इन कामगारों के लिए अपने मकान बनाना बहुत आवश्यक है । हमारा विधान क। प्रीएम्बल हर आदमी को मौका प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है यह हमारी कमजोरी होगी यदि हम गरीब आदमियों के लिए मौका उपलब्ध न करें । वैसे तो हमारी सरकार पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है लेकिन स्पीकर साहब, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि जो हमारी प्रधान मन्त्री के स्वप्न है कि हमने देश से गरीबी को हटाना है उसको साकार करने के लिये हम इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ताकि हमारा समाज खुशहाल बने ,ये लोग भी ऊपर उठें । अगर इस ओर पूरा ध्यान दे तो जैसे हम और मामलों में

तरक्की कर रहे हैं हरिजनों की भलाई और तेजी से करें ताकि इससे उनकी भलाई हो। कमजोरी दूर हो। स्पीकर साहब, इस बजट पर विरोधी भाइयों ने भी अपने-अपने सुझाव रखे और मैंने भी रखे। लेकिन जो विरोधी दल वालों ने सुझाव रखे वे तो विरोध की वजह से हैं क्योंकि इनको कोई और काम नहीं है सिवाय विरोध के तो सूरन शब्दों के साथ मैं इस बजट का अनुमोदन करता हूँ और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इसके ऊपर और अच्छे-अच्छे सुझाव रखने की चेष्टा की जाए। धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी (यमुना नगर) : स्पीकर साहब,

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, एक मँबर इधर से बोलना चाहिए और एक उधर से।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया...

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : स्पीकर, साहब यह अबोहर और फाजिल्का तो चारा पीछे ही रह गया, पंजाब और हरियाणा को टाईम मिल गया।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। चार तारीख को राज्यपाल महोदय ने इस सदन था सामने अपना अभिभाषण पेश किया और उनके अभिभाषण का मुख्य नजरिया यह था कि हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रही है

और पांचवीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू होने जा रही है उस पर सरकार का लक्ष्य क्या है? एक तो क्षेत्रीय इमबैलेंस दूर करना और दूसरा वर्गीय इमबैलेंस को भी दूर करना । जो गिरे हुए लोग सैं उनको उठाना और जो गिरे हुए क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाना । आज सरकार जो कारगुजारी करे उसका वितरण हर क्षेत्र में, हर एक वर्ग में बराबरी में हो जाए । गरीबी को दूर करना, स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा उठाना इसका मुद्दा था । 10 तारीख को हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश करने से पहले अपने अनुमान रखे जिसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ । यह बजट बहुत अहम बजट हूँ और इसको ऐसे मौके पर रखा गया है कि अगर पिछले बजटों को देखा जाए तो यह रियल्टी का बजट है । इस बजट पर चर्चा हुई कि यह डैफिसिट फाइनैसिंग का बजट है । डैफिसिट फाइनैसिंग के बजट की एक बहुत बड़ी अहमियत यह है कि डैफिसिट फाइनैसिंग की बुनियाद पर हम अपने को ऊपर उठा सकते हैं । पिछला बजट भी डैफिसिट था और 1971-72 में जहां रिसीट 132, 51 थी वहां रिवाइज्ड. एस्टीमेट में यह 1972-73 में 147.12 हो गई इसका मतलब यह हुआ कि 14.81 करोड़ की बढ़ोतरी हुई । अगर डैफिसिट फाइनैस था तो हमारी रिसीट में इतनी बढ़ोतरी कैसे होती । यह मैं रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा हूँ जो पिछले साल के बजट की बुनियाद पर थी । और आज अगर इस बजट की रेवेन्यू रिसीट ली जाए तो 147.12 जो ओल्ड क्लासिफिकेशन में थी नई क्लासिफिकेशन में टोटल कर दे तो 1974-75 में वह 166.11 हो जाती है यानी 12.73 की बढ़ोतरी

होती है । तो कहने का मतलब यह है एक तरफ हमारी रेवैन्यू की रिसीट बढ़ी और उसके साथ एक्सपेडिचर बढ़ा । क्यों बढ़ा? जो डैफिसिट फाइनेंसिंग का बजट हमने बनाया उससे हमने अपनी इकनोमी रीजनरेट की । इसको री-जनरेट करने के लिए आत्म निर्भरता की बहुत जरूरत होती है । दूसरी ओर इकोनोमी को री-जनरेट करने के लिए प्रोडक्टिव एम्प्लामेंट को जरूरत होती है और प्रोडक्टिव इदारे में बजट खर्च होना चाहिए । वित्त मन्त्री जी ने इस बजट अनुमान में साफ लिखा है कि आज हम इस बजट पर मेन बेसिज रखें—इनवैस्टमेंट इन प्रोडक्टिव सैक्टर । और नान-प्रोडक्टिव सैक्टर को अगर हम लोग रखें तो एक चीज में सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे इदारे एक दूसरे से मिले हुए हैं अगर हम कुछ इदारो के ऊपर प्रायोरिटी दें और कुछ को रख दे तो हम अपनी इकोनोमी को री-जनरेट नहीं कर सकते । जो अनुमान वित्त मन्त्री जी ने इन इदारो में दिए चाहे वह इरीगेशन की बात थी, चाहे एग्रीकल्चर की, चाहे ऐनीमल हस्बैंडरी की, चाहे डेरी डिवैल्पमेंट की और पावर इंडस्ट्री की थी या रोड ट्रांसपोर्ट, रोड्ज या टूरिजम और एजुकेशन इन सब दी बात की गई तो इनमें कुछ इदारे ऐसे हैं जो नान-प्रोडक्टिव हो सकते हैं लेकिन इनको भी प्रौडक्टिव इदारे की तरह प्रायोरिटी बेसिज पर साथ लेकर चलना चाहिए । इसकी बुनियाद पर भी हमारी इकोनोमी री-जनरेट होगी, इसकी बुनियाद पर हमारा पोर्टेंशियल बढ़ेगा । बजट में जो यह 18 करोड़ की कमी है उसको आगे चल कर पूरा करने की बात की गई है वह भी वित्त मन्त्री जी ने कह

दिया कि हमें कुछ सैंटर सो मदद मिलेगी, कुछ हम खर्च में किफायत करेंगे और कुछ करों तथा अन्य डियूज की अच्छी वसूली से पूरा करेंगे । इकोनोमी इन-एक्सपैंडीचर- इसके बारे में एक चीज सदन के सामने रखना चाहता हूँ जोकि किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की । हमारे एक्सपैंडीचर में ही क्यों इकोनोमी हो हम तो कहते हैं कि देश में रहने वाले हर आदमी के एक्सपैंडीचर में इकोनोमी होनी चाहिए । जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सेविंग नहीं कर सकेंगे और यही चीज आज हमने समझनी हूँ । हम सरकार की नुक्ता-चीनी की बात करते हैं...

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 A.M. on wednesday, the 16 January, 1974.

18.30 बजे

(इस समय सदन बुधवार, दिनाँक 16 जनवरी, 1974 के प्रातः 9.30 बजे तक के स्थगित हुआ)

परिशिष्ट

(कृपया डिबेट के पृष्ठ (9) 31 पर पद-टिप्पणी देखिए)

Backward Areas in the State

***670 Chaudhri Phul Singh Kataria** : Will the Minister for Revenue he pleased be state :-

(a) the details of the facilities provided to the Government employees posted in the Backward Areas in the State ; and

(b) whether the facilities referred to in part (a) above are being provided to the Government employees posted in Nahar SubTehsil of District Rohtak ?

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) :

(क) राज्य के निम्नलिखित पिछड़े इलाकों में नियुक्त 850/- रु० मासिक तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति-पूरक भत्ता की सुविधा इस प्रकार दी जाती है :-

जिला भिवानी

(भिवानी, लोहारु तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु दादरी तहसील में) कम से कम दस रुपए तथा अधिक से

अधिक पचास रुपए मासिक

।

जिला नारनौल

(तहसील नारनौल तथा 'यथोपरि'

महेन्द्रगढ में)

जिला अम्बाला

(तहसील नारायणगढ तथा मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत
परन्तु कम

तहसील जगाधरी के बिलासपूर से कम दस रुपए तथा
अधिक से

ब्लाक में)

अधिक पचास रुपए

मासिक ।

स्थानीय कर्मचारियों को उपरोक्त भत्ता का 50 प्रतिशत
दिया जाता है ।

(ख) नहीं जी ।